असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

08 मार्च, 2017

षोडश विधान-सभा बुधवार,तिथि 08 मार्च,2017 ई0
पंचम सत्र 17 फाल्गुन,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर मैं सदन की ओर से महिला सदस्यों के साथ सम्पूर्ण प्रदेश की महिलाओं को मुबारकवाद एवं शुभकामना देता हूँ ।

(इस अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष की महिला माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर विधान सभा में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महादेय, ...

अध्यक्ष : आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप कहां प्रवेश कर रहे हैं, महिला दिवस में आप कहां आ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ दलित महिलाओं के साथ बराबर बलात्कार की घटनायें घट रही है । मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल । माननीय सदस्य श्री शम्भुनाथ यादव ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-1049(श्री शम्भुनाथ यादव)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : महिला सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि यह आरक्षण तो यहां का मुद्दा है नहीं । अब आपकी बात सुन ली गयी है और अब आगे की कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं का जो प्रश्न है, वह बहुत गंभीर प्रश्न है और महिलाओं का आरक्षण का सवाल बहुत लम्बे अरसे से चल रहा है । आसन से मैं आग्रह करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय

विपक्ष में जो बैठे सदस्य हैं, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करावें ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, आज महिला दिवस है और जिस चार साल से राज्य में .....

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल तो चलने दीजिए । श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग ।

(इस अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष की महिला माननीया सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर बैठ गयीं)

तारांकित प्रश्न सं0-1050(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण प्रखंड के जम्होर से परसीया रोड एवं सुन्दरगंज दुधार से प्रितमपुर-जम्होर पथ को नवार्ड योजनान्तर्गत निर्माण कराया गया है, जो पॉच वर्ष के अनुरक्षण से बाहर हो चुका है । दोनों पथ श्रेणी-1 में शामिल है । प्राथमिक क्रमानुसार एवं निधि उपलब्धता के अनुसार इसकी मरम्मती कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि यह दोनों सड़क जो नाबार्ड से बनाया गया था, जो 5 वर्ष के अनुरक्षण के कार्यकाल में एक भी बार इसकी मरम्मती नहीं की गई । दोनों रोड में एक से डेढ़ फीट गड्ढ़े हैं । मैं पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वैसे संवेदकों के विरूद्ध सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : ठीक है, इसकी जॉच करवा लेते हैं लेकिन श्रेणी-1 में है, इसको तो हमको बनाना ही है, बना देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न सं0-1051 ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महादेय, इसको कब तक मरम्मती करा दी जायेगी अवधि तो बता दिया जाय ?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि उनके यहां जो मरम्मती कराने वाले सड़कों की प्राथमिकता सूची है, उसमें श्रेणी-1 में आपके पथ को सरकार ने रखा है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्राथमिकता में है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, अवधि तो बताया जाय, उस रोड में एक फीट, डेढ़ फीट गड्ढ़े हैं, एक कदम चलना उसमें मुश्किल है, अवधि तो कम से कम बता दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न को आगे चलने दीजिए । श्री विद्या सागर केशरी, ग्रामीण कार्य विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-1051(श्री विद्या सागर केशरी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ दो पथांश है, जिसकी स्थिति निम्नवत है:-

1. सुभाष चौक से कोठीहाट चौक पथ, उक्त पथ पर पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ सुभाष चौक से बराठपुर का पथांश उक्त पथ अनुश्रवण अनुरक्षण हेतु श्रेणी-1 की सूची में सम्मिलित है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार इसकी मरम्मती कराया जाना संभव हो सकेगा ।

2. कोठीहाट से खमकौल पथ उक्त पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित है । यह अनुरक्षण हेतु श्रेणी-2 के अन्तर्गत है । उक्त पथ के मरम्मती का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महादेय, यह जो सड़क है, पिछले साल बहुत प्रलयंकारी बाढ़ आयी थी । बाढ़ के कारण जब निगरानी समिति की जिला कमिटी बैठी थी, उसमें बताया गया था कि ऐसे प्रखंड जिसमें पूरी तरह से सड़क पुल, पुलिया बर्बाद हुई है, वैसे सड़कों का हम यहां से लिस्ट बनाकर सरकार को भेज रहे हैं और सरकार इसपर कार्रवाई कर रही है । अध्यक्ष महोदय, जिस रोड का हम बात कर रहे हैं, काफी जर्जर है, बुरी स्थिति है और सरकार के मंत्री महोदय अभी जवाब दे रहे हैं कि इसका अभी तक हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो आबादी है, हजारों की आबादी उस सड़क से आना-जाना करती है और उस सड़क को नहीं बनने के चलते छात्र-छात्रायें जो लोग भी उस रोड से आना-जाना करते हैं तो उससे सभी लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तो कब तक मंत्री महोदय किस फंड से सड़क को मरम्मती का विचार रखते हैं ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्य को बताया कि सुभाष चौक से कोठीहाट चौक पथ यह तो श्रेणी-1 में है, इसको तो हम कर देंगे, दूसरी बात यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त है तो इसको हम देखवा लेते हैं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महादेय, बाढ़ से मात्र फारबिसगंज में फारबिसगंज से ख्वासपुर तक की स्थिति इतनी बदतर है, सैंकड़ों बार हमने सदन में निवेदन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से हमने प्रश्न को उठाया था लेकिन आज तक हमारे विधान सभा में इतने प्रलयंकारी बाढ़ आयी, बाढ़ के चलते पूरे सड़क की हालत हाल-बेहाल है.....

अध्यक्ष : यह बात तो आप कह चुके हैं न । आप पूरक पूछिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय, यह कब तक इसकी सुनिश्चितता करते हैं इस सड़क की मरम्मती का कोठीहाट से खमकौल तक, माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब दें ?

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजियेगा । तारांकित प्रश्न सं0-1052 । पथ निर्माण विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-1052(श्री सत्यदेव राम)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

ग्रामीण कार्य विभाग के आन्दर से तियर पथ की कुल लम्बाई 12.60 कि0मी0 है एवं पथ क्षतिग्रस्त है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. स्वीकारात्मक है ।

4. ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु पथ निर्माण द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प सह पठित ज्ञापांक 935(एस) दिनांक 07.02.2017 में निर्धारित मापदंड को पूरा करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु गठित समिति द्वारा फिजिविलिटी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा । समिति के निर्णय एवं निधि की उपलब्धता के बाद ही विभाग में अधिग्रहण पर विचार करना संभव होगा ।

वर्तमान में इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है ।

टर्न-2/शंभु/08.03.17

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने की अनुशंसा जिला अभियंता कर चुके हैं। अब माननीय मंत्री जी के पास उस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। निधि की समस्या बताया जा रहा है, महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं है।

श्री सत्यदेव राम : तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव कब तक बनेगा?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट इसका उत्तर दिया है कि एक रोड कोड हमलोगों ने बनाया है और उसमें मापदंड वगैरह है और कमिटी गठित की गयी है, उसमें समीक्षा और फिजिबलिटी देखते हुए ही उस कमिटी को फैसला लेना है।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, उस पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने की जितनी प्रक्रियाएं हैं वह पूरी हो चुकी है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : वह कमिटी देख लेगी अगर होता है तो उसमें निधि की उपलब्धता को देखते हुए.....

श्री सत्यदेव राम : मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ चूंकि वह जनहित में बहुत ही जरूरी पथ है और उसकी हालत अभी काफी जर्जर हो चुकी है।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप वह कागजात दे दीजिएगा । इन्होंने कमिटी बना दी है वह देख लेगी। उसमें सारे क्राइटेरिया को पूरा करता होगा तो हो जायेगी आगे की बात।

श्री सत्यदेव राम : जी क्राइटेरिया पूरी है।

अध्यक्ष : आप कागजात दे दीजिए।

तारांकित प्रश्न सं0-1053(डा0 रंजु गीता)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है। एक बाजपट्टी से मधुबन सरहा पूर्वी पंचायत के ग्राम हरपुरवा बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बलवीरवा जानेवाली पथ में पुल निर्माण- यह पुल गांव के आंतरिक पथ के आरेखन पर है जो पूर्णतः कच्ची है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में 750 मीटर की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है। नंबर दो- बनगामा उत्तरी पंचायत के खतवे टोला महमदा जानेवाली पथ पर पुल निर्माण, यह पुल गांव के आंतरिक पथ में है, जो कच्ची है। इस पथ के अप स्ट्रीम में सबा कि0मी0 की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है। उक्त के आलोक में वर्णित पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा0 रंजु गीता : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पुल मधुबन बसहा पूर्वी पंचायत के बलवीरवा टोला जो टापू की तरह है, बिलकुल उसकी कनेक्टीविटी कहीं से नहीं है, सिर्फ जो सीतामढ़ी, पुपरी रोड के जस्ट बगल में नहर टाइप का पाइन है उसपर अगर पुलिया बना दिया जाता, पुल की आवश्यकता नहीं पुलिया का है, पुलिया बन जाता तो वह बलवीरवा टोला जो टापू के रूप में आज की तिथि में है उससे वह वंचित होगा। जहां पर अल्पसंख्यक समाज की बस्ती है और दो सौ, ढाई सौ घर है, लोग नहीं घर है। उसी तरीके से बनगांव उत्तरी पंचायत के खतवे टोला जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं वह भी टापू की तरह बना हुआ है तो इन दोनों पुलिया का निर्माण मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से- आज सचमुच में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि सदन में इन दोनों पुलिया को स्वीकृति देकर उसका कार्यान्वयन कराने का काम करें और कब तक करायेंगे यह मुझे आश्वासन दें।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्या को बताया कि ये पंचायत के अंदर का है और इसके अप में पहला जो था बाजपट्टी से मधुबन बसहा पूर्वी पंचायत में साढ़े सात सौ मीटर.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपकी सारी बातों को सुनने के बाद, सारे तर्कों को सुनने के बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है कि महिला दिवस है। इस अवसर के कारण वे अपने प्रश्न पर विशेष ख्याल चाहती हैं ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : ठीक है महोदय।

डा0 रंजु गीता : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है महोदय क्या मंत्री महोदय, इस वित्तीय वर्ष में दोनों पुलिया का निर्माण करायेंगे ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष तो समाप्ति पर है, अब तो जो होगा अगले.....

अध्यक्ष : इसको देख लीजिए।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1054(श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में वर्णित टोले के संपर्कता की स्थिति निम्नवत् है :- लुधिया टोला उक्त बसावट पी0एम0जी0एस0वाइ0 के स्वीकृत एल-0966 के अन्तर्गत पक्का रोड से गोरियारी पथ के आरेखन पर पड़ता है। उक्त पथ का निविदा निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। नंबर दो- मधेपुरा गांव उक्त बसावट को जी0टी0एस0एन0वाइ0 के अन्तर्गत लिये गये पथों गांधी ग्राम से मधेपुरा लंबाई 500 मीटर के निर्माण को संपर्कता प्राप्त हो जायेगी। प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। नंबर तीन- लच्छा भित्ता एवं बोतल टोला उक्त बसावट की आबादी लगभग 275 से 950 है। उक्त बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर संपर्कता दी जायेगी।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी लुधिया टोला, गोरियारी वाला रोड का कहा कि निविदा हो गयी उसी से सटा हुआ है लच्छा भित्ता मधेपुरा टोला और बोतल टोला जो 5 कि0मी0 का रोड है, महोदय, तीन महीना आदमी उस होकर जा नहीं सकता है, मने इतनी स्थिति खराब है रोड की- हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उस आबादी को देखते हुए इतना कठिन रास्ता है, आप उसको बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना है कि लुधिया टोला वह तो निविदा निष्पादन में है। दूसरा है मधेपुरा गांव के बसावट जी0टी0एस0एन0वाइ0 जो दूसरा गांधी ग्राम वाला है वह तो जी0टी0एस0एन0वाइ0 में आ रहा है और तीसरा जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में इसको हम देख लेते हैं और राशि की उपलब्धता के बाद इसको हम करा देंगे।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : सर, अब तो यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, 31 मार्च के बाद अब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो हम चाहते हैं कि नये वित्तीय वर्ष में बरसात से पूर्व मंत्री जी..

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उसको हम देख लेंगे।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1055(श्री सिद्धार्थ)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : 1-बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0-78 के निर्माण हेतु पटना जिला अन्तर्गत मुआवजा की स्वीकृति राशि रूपये 420 करोड़ 71 लाख के विरूद्ध वर्ष 2016 तक कुल रूपये 283 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष रैय्यतों का आवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार उनका भुगतान किया जा रहा है।

2-स्वीकारात्मक है।

3-नये भूअर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-24 के अन्तर्गत जिन मौजों का अवार्ड दिनांक 31.12.2013 तक नहीं घोषित हुआ है तथा 50 फीसदी से ज्यादा रैय्यतों का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें भूमि अधिग्रहण के नये कानून के तहत नियमानुसार नये दर पर भुगतान किया जा रहा है।

श्री सिद्धार्थ : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जितने भी लाभान्वित किसान हैं, जिन्हें इस राशि का मुआवजा मिलना है और अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को 2013 के नये भूमि अधिग्रहण कानून से मुआवजा दिया जाय क्योंकि कुछ लोगों को जो 2013 के बाद मुआवजा मिल गया है उसके बाद अगर पुराने नियम से मुआवजा दिया जायेगा तो निश्चित रूप से किसानों में विद्रोह होगा।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1056(श्री विजय कुमार मंडल)

श्री राजीव रंजन सिंह,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत सिकटी प्रखंड के पीरगंज स्थल पर एजेंडा सं0-138/52 के तहत 300 मीटर की लंबाई में कटाव निरोधक कार्य को 15 मई, 2017 तक पूर्ण कराकर स्थल को सुरक्षित किये जाने का कार्यक्रम है। नदी में कम जल स्राव रहने के कारण मेघा असराहा स्थल पर वर्तमान में कटाव नहीं हो रहा है। उक्त गांव नदी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। बाढ़ अवधि में कटाव निरोधक परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्रवाई कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, उस बकरा नदी से उस गांव जो पीरगंज, मेघा, असराहा, दैनिया खुटहरा, तीरा, रहुआबाड़ी, तीरा खरदौड़, पररिया ये सब गांव पूर्ण रूप से उजरने के कगार पर है तो सरकार से हम चाहेंगे कि दोनों तरफ बोल्डर पीचिंग करवाकर के गांव की सुरक्षा करने का विचार रखती है ?

टर्न–3/अशोक/08.03.2017

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि एक जगह जहां कटाव परिलक्षित हो रहा था वहां हमलोगों ने 300 मीटर लम्बा, 300 मीटर लम्बाई में हमलोगों ने एन्टी एरोजेन का काम सैंक्शन कर दिया है, जो गांव नदी से 300 मीटर की दूरी पर है और वहां अभी कटाव नहीं हो रहा, वहां अभी हमलोगों को कटाव निरोधक कार्य कराने का कोई कार्यक्रम नहीं है, और ऐसे भी आप भी अवगत हैं अध्यक्ष महोदय कि जो कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत होता है उसके लिए कई तरह की प्रक्रिया है, गुगेल से इसका मैप लिया जाता है, गुगल से मैप लेने के बाद उसका सैटेलाईट इमैजरी के आधार पर, फ्लड के जो इनचार्ज वहां जो चीफ इंजीनियर रहते हैं उनकी अनुशंसा होती है, फिर टेकनिकल कमिटी की अनुशंसा होती है । ये सारी प्रक्रिया में जो मेघाअसराहा वाली की जो स्थिति है, वहां कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है इसलिये वहां कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत करने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी नदी से, उसके बगल में जो....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि तीन सौ मीटर पर जहां खतरा था उस पर काम की स्वीकृति दी गई है और जहां पर भी ऐसा होता है तो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में कराया जाता है । अगर कहीं पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो सूचना दीजियेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1057(श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 5.5 कि.मी. है, जो दो पथों यथा समसा चौक से मथुरापुर एवं बखरी खगड़िया पी.डब्लू.डी. से अमुआर कर्णपूरा पथ से संबंधित है। पथ का निर्माण एम.एम.जी.एस.वाइ. से वित्तीय वर्ष 2009–10 में पूर्ण कराया गया था । पथ श्रेणी–1 में सम्मिलित है एवं इसका डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्रथमिकता क्रमानुसार पथ में मरम्मति कार्य कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1058(श्रीमती अरूणा देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1–स्वीकारात्मक है ।

2– यह पथ श्रेणी–1 में शामिल है । डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति के उपरांत मरम्मति कार्य करा लिया जाएगा ।

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका बिगहा से कुम्भी(कुंभी) रोड जो है वह बहुत जर्जर स्थिति में है, वहां आवागमन की स्थिति बाधित है और आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूॅ कि इसकी समय सीमा बता दें कि कबतक बनाने का विचार रखते हैं, आज तो राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज तो महिला की तो बात रखिये ।

अध्यक्ष : आज महिला दिवस है और महिला सदस्यों के पूरक को आप ऐसे टाल नहीं सकते हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : नहीं, नहीं, टाल नहीं रहे हैं महोदय, हमने कहा कि डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है, स्वीकृति....

अध्यक्ष : आप बता दीजिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : कार्रवाई कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1059(श्री (मो0) तौसीफ आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.212 कि0मी0 है । उक्त पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी.एन.सी.पी.एल. के क्रमांक 51 पर कुतुमोहम्मद नगर से रफीक टोला भाया हाजी टोला मदरू टोला सैफुलटोला के नाम से सम्मिलित है । उक्त हाजी टोला को ही मतीन टोला के नाम से जाना जाता है । उक्त पथ का डी.पी.आर. स्वीकृति की प्रक्रिया में है । स्वीकृति के पश्चात इसके निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री (मो0) तौसीफ आलम : महोदय, इसकी स्वीकृति कब तक होगी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ, टेन्डर के लिए ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : हमने माननीय सदस्य को बताया कि डी.पी.आर. स्वीकृति की प्रक्रिया में इसके बाद टेन्डर हो जायेंगा इसका ।

श्री (मो0) तौसीफ आलम : समय सीमा को बतला दिया जाय । समय सीमा दे दिया जाय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : इसको शीघ्र देख लिया जाय ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1060(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : स्वीकारातमक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल राज्य कोर नेटवर्क के क्रम सं0 146 पर अंकित पथ रानीगंज प्रखण्ड में बड़हरा चौक से शिव मंदिर टोला पर

अवस्थित है । डी.पी.आर. की मांग की जा रही है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त पथ के साथ प्रश्नाधीन पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1061(डॉ अशोक कुमार)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पथ की लम्बाई 2.0 कि.मी. है, जो ईंटकृत है । गॉव का आंतरिक पथ होने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । पथ के 200 मीटर पथांश में पी.सी.सी. कार्य पंचायत द्वारा कराया जाना है ।

इस पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । यह गांव के अन्दर का पथ है महोदय ।

डॉ अशोक कुमार: गांवके अन्दर का पथ है मंत्री महोदय लेकिन ये पथ पी.डब्लू.डी. स्ड़क को जोड़ती है एक तरफ से जाती हैं और दूसरी तरफ से पी.डब्लू.डी. रोड में ही आती है और आपने स्वीकार किया है इसकी स्थिति जर्जर है तो इसको आर.ई.ओ. अपने स्तर से बनवाने का विचार रखती है?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य पुराने हैं, जितने भी पंचायत के अन्दर वार्ड का जो भी रोड है वह पंचायत करायेगा और वार्ड से बाहर जो गांव को सम्पर्कता देना है वह ग्रामीण कार्य विभाग करायेगा, उक्त जो पथ है पंचायत के अन्दर का पथ है इसलिए इसको पंचायत के द्वारा कराया जायेगा महोदय ।

डॉ अशोक कुमार: सभी पथ पंचायत के अन्दर होते हैं गांव में, लेकिन यह पथ पी.डब्लू.डी. के सड़क को एक तरफ से दूसरी तरफ से जोड़ती है, सम्पर्क पथ हैं और जर्जर स्थिति में हैं इसलिए और दो कि.मी. लम्बाई हैं, दो कि.मी. लम्बाई की सडक कई पंचायत से गुजरेगा तो उसमें तो कठिनाई होगी उनको, आर.ई.ओ. से बनाने का विचार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इनको जो सूचना है उसके हिसाब से किसी एक पंचायत के अन्दर वाली सड़क है और आप कह रहे हैं कि कई पंचायतों को जोड़ती है तो मुख्य अन्तर यही है, मंत्री जी, इसको दिखवा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1062(श्री राम बालक सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.9 कि.मी. है, जो ईंटकृत है । पथ का सर्वे किया जा चुका है । मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पथ निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री राम बालक सिंह : महोदय, ये कब तक बना देंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अगले सत्र में महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1063(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के प्रखण्ड गोरैयाकोठी एवं लकड़ी नवीगंज प्रखण्डों में सारण मुख्य नहर से नि:सृत मराची माईनर एवं 18 विभिन्न आउटलेटों से सिंचाई उपलब्ध करायी जाती है । इसके अतिरिक्त 3 नये आउटलेट एवं 2 क्षतिग्रस्त आउटलेट के निर्माण कार्य पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य में सम्मिलित है । नहर पुनर्स्थापन के उपरांत आउटलेट के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सकेगी ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहना चाहता हूँ कि मुख्य नहर में पानी रहने के बाद भी नाला नहीं रहने के कारण पटवन नहीं हो पाता है, नाला नहीं होने के कारण नहर के बगल के दोनों तरफ के फसल सूख जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मत्री से मांग करता हूँ कि उसका सर्वे करवा दे कि कहां कहां नाला होना चाहिए ताकि किसानों को पटवन की सुविधा प्राप्त हो सके । जल उपलब्ध है, इसके बावजूद हमारा फसल सूख जाता है तो फिर नहर का क्या औचित्य है ? आप सर्वे करा लीजिए और उस सर्वे में हमको भी साथ रखा जाय ताकि मैं बतला दूं कि कहां कहां नाला की व्यवस्था करने से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ हो सके । क्रमश:

टर्न-4/ज्योति
08-03-2017

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, क्रमश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब सर्वे कराना चाहते हैं, समय निश्चित करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : महोदय, पश्चिमी गण्डक का जो पूरा टेण्डर हुआ था और उस टेण्डर में सभी आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूट्री, माईनर डिस्ट्रीब्यूट्री सब इन्कलुडेड था और उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा था । विभाग ने तकनीकी समिति बनाकर उसमें विभाग के तीनों अभियंता प्रमुख थे, उनसे उसकी पूरी तकनीकी समीक्षा करायी गयी और समीक्षा के बाद यह पाया गया कि जो संवेदक थे वो मुख्य नहर में ही काम कर रहे थे, जिसमें कम आवश्यकता थी । वास्तव में आवश्यकता आउटलेट्स के और

डिस्ट्रीब्यूट्री के निर्माण की थी जहॉ से माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं कि खेतों में हम जो पानी पहुंचाते हैं, वह हम आउटलेट्स के माध्यम से और जो डिस्ट्रीब्यूट्री है, उसके माध्यम से पहुंचाते हैं । वाटर कोर्स के माध्यम से पहुंचाते हैं तो यह काम हो नहीं रहा था इसलिए विभाग ने यह फैसला किया कि हम उन सभी काम को जो पुराना हुआ था उसको हम क्लोज करेंगे, फोर क्लोज करेंगे, हमलोगों ने फोर क्लोज कर दिया फिर से अभी उसका सर्वे कराके और सबसे पहले माईनरी डिस्ट्रीब्यूट्री, माईनर डिस्ट्रीब्यूट्री, वाटर कोर्स का काम होगा तब मुख्य नहर का काम होगा ताकि खेतों तक सिंचाई सुविधाा पहले पहुंच सके, मुख्य नहर में तो पानी जा ही रहा है । माननीय सदस्य भी कह रहे है कि मुख्य नहर में पानी जा रहा है तो मुख्य नहर में काम कराने की कोई आवश्यकता थी नहीं तो इसलिए हमलोगों ने फोर क्लोज किया है और उसपर समीक्षा हो रही है, मामला कुछ न्यायालय में भी है इसमें शीघ्र हमलोग जितना जल्दी हो सकेगा उस काम को पूरा करायेंगे ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : महोदय, मुख्य नहर में जो डिस्ट्रीब्यूट्री है उसमें बहुत सा सोलिंग करके छोड़ दिया गया है । आधा अधूरा काम किया गया । माननीय मंत्री जी पहले डिस्ट्रीब्बयूट्री में पानी जा रहा था और खेत भी पट रहा था । अब वह आधा अधूरा हो जाने के कारण अब जो भी पानी है, वह जाता ही नहीं है लेकिन ये पटवन की वसूली करते हैं, पटवन की वसूली हो रही है लेकिन हमारी खेत बर्बाद हो रही है उसमें पानी नहीं जा पा रहा है, खेत पट नहीं रहा है । उस डिस्ट्रीब्यूट्री को ब्लौक कर दिया गया । कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचे से नहीं जाता है तो बहुत सी गड़बड़िया पैदा हो गयी है इस ढलाई के बाद तो मेरा कहना है कि इस कार्य को कबतक करवा लेंगे, यह माननीय मंत्री बतलायें ।

अध्यक्ष : नेमातुल्लाह जी, मंत्री जी ने तो कहा है कि अद्यतन स्थिति का सर्वे करा रहे हैं और जो काम बचा हुआ होगा उसको करवायेंगे आप सब लोग सूचना तो उनको दे दीजिये।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : ठीक है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय,....

अध्यक्ष : लीजिये आपकी बारी तो चली गयी ।

श्री सत्सदेव प्रसाद सिंह : वह तो खड़ा हो गए ।

अध्यक्ष : अब खड़ा हो गए । हम तो आपको देख रहे थे, आप उनको देखने लगे तो हम भी उनको देखने लगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : जी, जरा मेरी सुन लिया जाय माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्य नहर में काम नहीं होगा मैं मुख्य नहर की बात कहॉ कह रहा हूँ ।

श्री नेमातुल्लाह : सर्वे का काम कबतक होगा ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : नेमतुल्ला साहेब मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिये ।

अध्यक्ष : अब फिर उन्हीं से बात कर रहे हैं ।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह : जी नहीं , बीच में टपक गए तो मैं क्या करुं आप फिर गाईड करिये । अध्यक्ष महोदय, मुख्य नहर की बात माननीय मंत्री जी ने कहा । मैंने नाला की बात की है कि मुख्य नहर में भी नाला की व्यवस्था करायी जाय ताकि मुख्य नहर के बगल में ..

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो खुद स्वीकार किया है कि मुख्य नहर में काम हो रहा था, नाला जिससे पटवन होता है उसका काम नहीं हो रहा था । इसीलिए उसे बंद कराकर अब वह काम प्राथमिकता से करायेंगे, यही तो वह कह रहे हैं ।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह : प्राथमिकता की बात नहीं, जितना मुख्य नहर बना हुआ है जितने डिस्ट्रीब्यूट्री बनी हैं कोई कार्यरत नहीं है । ये बिहार किसानों का राज्य है 70 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर हैं । माननीय मंत्री जी सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये । माननीय सदानंद बाबू सिंचाई मंत्री रहे हैं वह भी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री सदानंद सिंह : आप भी मंत्री रहे है हुजूर । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा कि सर्वे कराना आवश्यक है और जो उसके डिस्ट्रीब्यट्रीज हैं, आउटलेट्स हैं उससे सिंचाई नहीं हो पा रही है तो माननीय मंत्री जी सिर्फ यह बतायें कि कबतक सर्वे का काम पूरा करा देंगे और सर्वे के बाद क्या इस वर्ष आने वाले खरीफ के पहले ये सारी गड़बड़िया ठीक करवा देंगे ?

श्री राजीव रंजन सिंह, मंत्री : हमने बता दिया, माननीय सदस्य, सिंचाई मंत्री भी रहे हैं और विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं । मैंने कहा कि उसको फोर क्लोज किया गया है और जितना वाटर कोर्स है जितना माईनर डिस्ट्रीब्यूट्री है जितना डिस्ट्रीब्यूट्री है उसका काम पहले करायेंगे और अभी जिसको फोर क्लोज किया गया है उसका कुछ मामला न्यायालय में है लेकिन समानांतर स्तर पर विभाग में पहले से बना हुआ है वेस्टर्न गंडक का टेण्डर हुआ था, उसमें वाटर कोर्स, उसमें माईनर डिस्ट्रीब्यूट्री, माईनर डिस्ट्रीब्यूट्री, उसमें आउटलेट्स सब आईडेन्टिफायड है हमको प्रायरिटी सिर्फ देना है कि ये काम पहले करेगा जो भी संवेदक होगा और मेन कैनाल का काम बाद में करेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1064 (श्री सुबोध राय)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन गोरगामा से परसा पथ में 130 मीटर का पुल निर्माणाधीन है । परन्तु नदी की मुख्य धारा लगभग 500 मीटर आगे बढ़ जाने के कारण चथरु टोल एवं बलुआ टोल गोरगामा के बीच 120 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता होगी । इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता के

द्वारा चेक लिस्ट उपलब्ध कराया गया है, जो विभाग के समक्ष तकनीकी समीक्षा हेतु विचाराधीन है ।

श्री सुबोध राय : मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करुंगा कि उसपर जरा आगामी वर्ष में विचार करके उसका कार्यान्वयन करायें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1065 (डा0 सुरेन्द्र कुमार)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बागमती नदी के दोनों तरफ तटबंध निर्माण से बाढ़ अवधि के दौरान जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ साथ सामान्य आवागमन के माध्यम का भी निर्माण हुआ है । दोनों तटबंधों के बीच नदी अपनी सीमित क्षेत्र लिमिटेड कोर्स में तीन धाराओं के माध्यम से प्रवाहित होती है जिसमें से एक धारा मध्य में, एक धारा दायें और एक धारा बायें तटबंध के टो से सटकर प्रवाहित होती है बाढ़ अवधि में यदा कदा दोनों तटबंधों के बीच के क्षेत्रों में पानी का फैलाव होता है तथा दो तीन दिनों के पश्चात पुनः नदी अपने सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है इस प्रकार दोनों तटबंधों के बीच बाढ़ से स्थायी जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती है । उक्त स्थिति में कृषकों को अपना कृषि कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती है । उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान में बागमती दायें और बायें तटबंधों के बीच के क्षेत्र में स्थायी जल जमाव नहीं है । टाल दियारा क्षेत्र घोषित करने का मैंडेट कृषि विभाग के पास है जल संसाधन विभाग के पास नहीं है।

डा0 सुरेन्द्र कुमार : ठीक है सर ।

तारांकित प्रश्नसंख्या 1066 (श्री शम्भूनाथ यादव)

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य -अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 1067 (श्री संजय सरावगी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव , मंत्री : महोदय, 1- एल0सी0 नं0-25 एस.पी.एल. / 3 ई0 पर आर0ओ0बी0 के निर्माण के लिए रेलवे से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में सहमति प्रदान की गयी थी जबकि एल0सी0 नं0 28 पर आर0ओ0बी0 के निर्माण के लिए रेलवे से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 15-16 में सहमति प्रदान की गयी थी पथ निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 13-14 14-15 एवं 15-16 के प्रतिवेदन में एल0सी0 नं0 25 एस0पी0एल0/ 3 ई0 के संबंध में सूचना अंकित है तो वित्तीय वर्ष 11-12 से 16-17 तक कुल 53 लेवेल क्रौसिंग पर 50/50 कौस्ट शेयरिंग

के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु सहमति दी गयी थी । इनमें से भारतीय रेल द्वारा 47 आर0ओ0बी0 का निर्माण की स्वीकृति दी गयी है । हाल ही में दिनॉक 07-02-17 को मैं माननीय रेल मंत्री से मिला था और इन आर0ओ0बी0 के निर्माण के कार्यान्वयन एजेन्सी के चयन सहित अन्य सभी व्यवहारिक समस्याओं को सर्वसम्मति से समाधान कर लिया गया है । रेलवे से इन आर0ओ0बी0 के डी0पी0आर0 एवं जी0ए0डी0 प्राप्त होने एवं जी0ए0डी0 अनुंमोदित होने पर निर्माण कार्य वर्ष 17-18 में यथाशीघ्र शुरु किया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों आर0ओ0बी0 है 25 स्पेशल थ्री पूरा शहर जाम रहता है इस आर0ओ0बी0 के कारण और 2013 में जो तत्कालीन रेल मंत्री जी थे इसका शिलान्यास भी किए थे । ये 25 स्पेशल 3- 2013 के नवम्वर में अध्यक्ष महोदय, आरै उनका पत्थर और बोर्ड भी लगा हुआ है । और इसका डी0पी0आर0 और पी0पी0आर0 महोदय , 2013 में बना पी0पी0आर0 बना तब ही उन्होंने शिलान्यास किया तो महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसका निर्माण कार्य जब सारी समस्यायें खत्म हो गयी है तो इसका निर्माण कार्य कबतक प्रारम्भ हो पायेगा ? पूरा शहर जो है, यहॉ सभी सदस्य बैठे हैं सब सदस्य जानते हैं दरभंगा शहर के बारे में भर दिन दो तीन कि0मी0 जाने में तीन चार घंटा लगता है इसलिए गंभीरता से लेते हुए दोनों 25 स्पेशल 3 ई0 और 28 बेला कंगवा का कबतक निर्माण करायेंगे ?

टर्न-5/08.3.2017/बिपिन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: महोदय, लगातार प्रयास में हैं और दो बार रेल मंत्री जी से भी मिल चुके हैं । इसका जे.ए.डी. भी एप्रूव नहीं है, वह भी आ जाएगा और एजेंसी का जो चयन है, क्योंकि एरकॉन जो एजेंसी है, उसका जो चार्ज है, 9परसेंट का चार्ज लेती है, तो हमलोगों ने रेल मंत्री के सामने यह बताया था । हालांकि उन्होंने बात की है, मान गए है कि राज्य सरकार की भी एजेंसी पांच परसेंट पर काम करती है महोदय, तो वह दे देंगे लेकिन ऐसा कोई चिट्ठी अभी तक आया नहीं है और इन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं महोदय । हम तो चाहेंगे कि ये भी जाकर उनसे आग्रह करें और जल्द-से-जल्द स्वीकृति करें ।

(व्यवधान)

महोदय, लालू जी रेल मंत्री थे, उसके बाद से आर0ओ0बी0 को क्लीयरेंस के लिए तो काफी मुश्किलें आई हैं महोदय और इनके ही पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, प्रेम कुमार जी रहें या नन्द किशोर जी रहे हैं तो उन्होंने भी क्या गंभीरता दिखाई है, वह भी देखने की बात होनी चाहिए महोदय । हम तो लगातार, जब से बने, दो बार...

अध्यक्ष : पूरी ताकत से सरकार प्रयास कर रही है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में इन्हीं के महागठबंधन के मंत्री जी थे अध्यक्ष महोदय और उन्हीं का यह प्रतिवेदन है और उसमें लिखा हुआ है कि डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है । इन्हीं के मंत्री जी दिए हैं अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, 2013 में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसमें क्या प्रश्न है ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है ...

अध्यक्ष : छोड़िये न ।

श्री संजय सरावगी : एक मिनट अध्यक्ष महोदय । महोदय, स्वीकृति नहीं हुई और इनके महागठबंधन के रेलमंत्री..

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0: 1068 (श्री गिरिधारी यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत फुल्लीडुमर प्रखंड में सहरोई नदी पर अवस्थित कानीमोह बीयर क्षतिग्रस्त है । इससे लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है । स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बीयर का निर्माण सिंचाई प्रमंडल बीजीखोरबा द्वारा 1976 में कराया गया था। वर्ष 2010 में जिला परिषद द्वारा मनरेगा अन्तर्गत इस बीयर का पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ किया गया जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है । जल संसाधन विभाग की संरचना होने के कारण इसके पुनर्स्थापन का प्राक्कलन तैयार कर कार्यान्वयन की कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, भागलपुर को विभागीय पत्रांक 373 दिनांक 07.3.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है ।

श्री गिरिधारी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद का जो मामला आया है, बिना एन.ओ.सी. का जिला परिषद कैसे काम कर सकता है ? उसी के चलते यह कानीमोह बीयर फँसा हुआ है कि यदि वह इरीगेशन का बीयर था तो किस परिस्थिति में इरीगेशन विभाग ने एन.ओ.सी. दिया कि वह जिला परिषद काम करे । मनरेगा से कहां से सर बीयर बन सकता है ? इसलिए आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से...

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दिया गया है ।

श्री गिरिधारी यादव : फिर वहां से आ जाएगा कि वह मनरेगा का कार्य कर रहा था, इसीलिए हम उसको नहीं कराएंगे । इसीलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह क्लीयर कराना चाहते हैं कि मनरेगा की कोई बात नहीं है, इस बीयर का निर्माण कितने दिनों में करा देंगे ? यह बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है माननीय महोदय ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य उत्तर को पूरा ध्यान से नहीं सुने । हमने कहा कि उसका जो कमांड एरिया है वह 1200 एकड़ है और 1200 एकड़ का निर्माण, कोई भी संरचना का निर्माण लघु सिंचाई विभाग के मैन्डेट के अधीन है, फिर भी जब हमने माननीय सदस्य के प्रश्न की समीक्षा की तो यह हमको जानकारी मिली कि बीजीखोरबा ने 1976 में इसको बनवाया था । तो हमने कहा कि भाई, जब बनवाया था और मनरेगा से नहीं बन रहा है तो डायरेक्शन दीजिए चीफ इंजीनियर को कि आपकी परिसम्पति है, आप बनाइए । तो मुख्य अभियंता को यही निर्देश दिया गया है कि चूंकि यह 1976 का जल संसाधन विभाग का है, इसलिए इसको ठीक कराइये । तब सुने नहीं उत्तर ।

श्री गिरिधारी यादव: धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1069 (श्री हरिनारायण सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. नगरनौसा प्रखंड अन्तर्गत लच्छु विगहा लोहण्डा ग्रामीण कार्य पथ से चौरासी लम्बाई लगभग 600 मीटर है तथा एन0एच0-30ए से कैला ग्रामीण कार्य पथ से ग्राम गढ़ीयार पथ की कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 है ।

प्रश्नगत् दोनों पथ खराब स्थिति में है । दोनों पथ श्रेणी-2 में है । डी0पी0 आर0 की मॉग की जा रही है । तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीर्णोद्धार करा देंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: डी0पी0आर0 की मांग कर लिए हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं कि हो जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1070 (श्री राम चन्द्र सहनी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0: 1071 (श्री प्रह्लाद यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: महोदय 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अमरासनी झरना का पानी अमरासनी नाला के माध्यम से मैदानी भाग में पहुंचता है तथा किसानों द्वारा इसका उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है ।

बूढ़वा झरना का पानी लगभग दो-तीन किलोमीटर वन क्षेत्र से गुजर कर एक नाला के माध्यम से कृषि योग्य भूमि तक पहुंचता है तथा किसानों द्वारा इससे सिंचाई की जाती है ।

2. आंशिक स्वीकरात्मक है ।

लहसौरवा गांव अमरासनी नाला के उपरी भाग में अवस्थित है तथा इस गांव का एन0एस0एल0 इसके निकट अमरासनी नाला के तल से काफी ऊंचा है । ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए एक अन्य स्थल, जहां बरसात में पहाड़ियों से पानी एकत्रित होता है, में भी लेवेल का अंतर लगभग 5 से 6 मीटर है । इन स्थलों पर चेकडैम निर्माण के बाद भी लहसौरवा ग्राम के किसान लाभान्वित नहीं हो सकेंगे ।

लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना अन्तर्गत दायां मुख्य नहर से इसके बाएं तरफ के भलूई पंचायत के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है । दांया मुख्य नहर के दायीं तरफ तथा पहाड़ के बीच के क्षेत्र के किसानों को वर्त्तमान में सिंचाई की असुविधा है, जो भलूई के निकट चेकडैम के निर्माण से उपलब्ध हो सकती है ।

3. यथा क्रमांक 2 (i) चेकडैम का निर्माण सार्थक नहीं है । यथा क्रमांक 2 (ii) चेक डैम के लिए वन भूमि के अपयोजन की आवश्यकता होगी । इस संबंध में विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक 367 दिनांक 6.3.2017 से मुख्य अभियंता, भागलपुर को निर्देश दिया गया है ।

श्री प्रह्लाद यादव : माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1072 (श्री बृज किशोर बिन्द)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखंड के पुरूषोत्तम ग्राम के दक्षिण कोहिरा नदी बहती है जिसपर कोहिरा जलाशय एवं इसके डाउनस्ट्रीम में राजपुर बीयर निर्मित है । राजपुर बीयर के अपस्ट्रीम से नि:सृत सिकंदरपुर एवं नरोत्तमपुर माइनर से सिकंदरपुर, ओखरा, पुरूषोत्तमपुर गंगापुर एवं रामपुर (पाँच) गाँवों के किसानों को पटवन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रश्नाधीन गेहुअनवा नदी पर बाँध निर्माण कर विषयांकित ग्रामों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी को विभागीय पत्रांक 355 दिनांक 06.03.2017 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

श्री बृज किशोर बिन्द: महोदय, मेरा यही कहना है कि जितना गांव है वह पहाड़ी क्षेत्र में है तो पानी पहाड़ के लोगों के काम नहीं आ रहा है चूंकि जमीन ऊँची नीची है और जहां गांव बसा है वहां वीयर से बहुत ऊँचा है, पानी चढ़ता नहीं है । पता नहीं कैसे माननीय मंत्री जी को कहां से उत्तर आ जाता है और जितना माइनर की खुदाई हुई है वह सब जीर्ण-शीण-ध्वस्त है, पानी एक बूंद भी नहीं पहुंच पाता है । वहां के किसान के फसल सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं पूरक पूछिये न ।

श्री बृज किशोर बिन्द: पुरूषोत्तमपुर गांव के दक्षिण नदी में बांध बांध दिया जाए तो पांच गांव के लोगों का खेत का पटवन खूब बढ़िया होगा और फसल नहीं सूखेगा । हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी कि वहां बांध बांध दिया जाए ।

टर्न:06/कृष्ण/08.03.2017

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर इन्होंने सुना ही नहीं । असल में समस्या यह है कि प्रश्न तो कीजिये और उसका उत्तर ध्यान से मत सुनिये । मैंने अपने उत्तर में कहा कि प्रश्नाधीन गेहुंअनवा नदी पर बांध निर्माण कर विषयांकित ग्रामों में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता,सिंचाई सृजन, डिहरी को विभागीय पत्रांक 355 दिनांक 6 मार्च, 2017 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है । जो बात हम उत्तर में कह चुके हैं, वही माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं ।

श्री बृज किशोर बिंद : मैं बधाई देता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1073 (श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है । शंकर सरैया से कवलपुर एस0एच0-54 होते हुये छपवा तक पथ की लंबाई 20 किलोमीटर है, के निर्माण हेतु शीघ्र ही सी0आर0एफ0 मद से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था । सी0आर0एफ0 में राशि की उपलब्धता नहीं होने के कारण पथ निर्माण विभाग द्वारा इस पथ की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है । पिपरीया पेट्रौल पम्प चौक भी एस0एच0-54 पर ही अवस्थित है । पिपरीया पेट्रौल पम्प चौक में मुंशी इनार पथांश ग्रामीण पथ है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1074 (श्री विद्या सागर केशरी)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ अनुरक्षण हेतु मरम्मति योग्य पथों की श्रेणी-1 की सूची में सम्मिलित है । प्राथमिकता क्रमानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर इसकी मरम्मती कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, इसकी मरम्मती कबतक करवा देंगे ? महोदय, दो सड़क महत्वपूर्ण है । मैंने बताया था कि फारबीसगंज से खवासपुर पथ की हालत बहुत जर्जर

है । उस सड़क और इस सड़क की मरम्मति करवा दिया जाये, मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि इसको जल्द मरम्मत करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : इसको जल्दी दिखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1075 (श्री अशोक कुमार)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 6.10 किलोमीटर है । यह पथ अनुरक्षण हेतु मरम्मति योग्य पथों की श्रेणी–1 में सम्मिलित है। पथ की मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ की मरम्मति कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1076 (श्री अमीत कुमार)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, खंड–1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड में बागमती बायां तटबंध जीरो किलोमीटर से 7.50 किलोमीटर तक की लंबाई पड़ता है, जिसमें रामपुर खंड, ढेंग, सोनाखान, आखता तक बागमती नदी तटबंध पर प्रत्येक वर्षा ऋतु में पानी का दबाव नहीं रहा है । बल्कि विभिन्न वर्षों में विभिन्न स्थलों पर दबाव रहा है । ऐसा नहीं है कि विगत 20–25 वर्षों में एक ही साथ चारों जगहों पर दबाव रहा हो । वर्तमान में विगत चार–पांच वर्षों में सुप्पी प्रखंड के अर्न्तगत बागमती बांया तटबंध के किलोमीटर 3.56 से 4.79 के बीच रामपुरखंड स्थल पर पानी का दबाव रहा है ।

खंड–2. अस्वीकारात्मक है । रामपुरखंड स्थल पर बाढ़ वर्ष 2015 के पूर्व 1230 मीटर की लंबाई में बोल्डर रीवेंटमेंट एवं पायलट चैनल का कार्य कराकर तटबंध को मजबूती प्रदान किया गया है एवं तटबंध पर पानी का दबाव कम करने का प्रयास किया गया है, जो काफी हद तक प्रभावी रहा है । वर्षा ऋतु में पानी का दबाव बढ़ने से तटबंध के पास बोल्डर एप्रॉन पर कुछ लंबाई में दबाव रहता है, जिसे अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक दल तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के कार्यान्वयन हेतु निर्मित क्षेत्र तकनीकी टीम के अतिरिक्त सेवानिवृत्त वरीय अभियंता को तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाती रही है, जिसके सलाह पर कटाव निरोधक कार्य बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का स्वरूप निर्धारण कर कार्य को कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

खंड–3. यथा ऊपर वर्णित प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कटाव निरोधक कार्यों के कार्यान्वयन के देख–रेख हेतु अध्यक्ष, विशेष जांच दल की प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा की गयी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1077 (श्री रामदेव राय)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1078 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसमें राजपुताना टोला से बलरा इस्माईल तक जिसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर है । यह कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन है । शेष 1. 30 किलोमीटर पथ जर्जर है, जो पुरानी आर0ई0ओ0 सड़क है । यह पथ श्रेणी 2 के अन्तर्गत है । अभी इस पथांश की मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, बाघी कुढ़नी विधान सभा का एक प्रमुख जगह है । वहां उच्च विद्यालय है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 3 किलोमीटर से वहां बच्चे-बच्चियां स्कूल जाते हैं । बहुत जर्जर होने से काफी दिक्कत होती है । मैं मानीयय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहते हूं, माननीय मंत्री श्रेणी 2 में बोले हैं तो यह कब तक रोड बनेगा ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि माननीय सदस्य को बताया कि निधि की उपलब्धता होने के पश्चात् इसको बना देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1079 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1080 (श्री सदानन्द सिंह)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन पथ घोघा सोन्हौला पथ जिसकी कुल लंबाई 16 किलोमीटर है, यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज संख्या 46 (बी) के अधीन है । इस पथ में 8 किलोमीटर में जनवरी,17 तक 25 एम0एम0 थिक एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है । 2.5 किलोमीटर में पी0सी0सी0 कार्य की स्थिति अच्छी है । शेष पथांश 5.70 किलोमीटर में 25 एम0एम0 थिक एस0डी0बी0सी0 का अप्रील,17 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1081 (श्री हेम नारायण साह)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1082 (श्री चन्दन कुमार)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के अन्तर्गत कोई बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोर नेट वर्क में शामिल नहीं है । उक्त पथ के दोनों छोर पर पथ निर्मित है । प्रश्नाधीन पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री चन्दन कुमार : महोदय, अलौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत से ऐसे सड़क हैं जो कोर नेट वर्क से नहीं जुड़ा हुआ है तो वह कैसे बनेगा ? उसको कोर नेटवर्क से जोड़वाने के लिये क्या करना होगा महोदय ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय अरूण बाबू, आप नेता विरोधी दल की सीट से थोड़ा हट जाइये । आपकी इच्छा, आकांक्षा पर सदन को शंका नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अरूण बाबू नेता, प्रतिपक्ष की सीट पर बैठे हैं, कितना शांतिपूर्वक सदन चल रहा है । मैं तो चाहता हूं कि उसी सीट पर बैठे रहें, शांतिपूर्वक सदन चलता रहेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1083 (डा0 मो0 जावेद)

अध्यक्ष : डा0 मो0 जावेद जी ने माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी को अधिकृत किया है ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के करबन्ना पंचायत के अन्तर्गत महेश्वर राय के घर से सुभाष यादव के घर होते हुये महादलित मुहल्ला एवं बजरंगबली तक पथ की लंबाई 2 किलोमीटर है । पथ के एक छोर को पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्मित पथ करबन्ना से करबन्ना टोल से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पथ के 700 मीटर के रेखांकन में करबन्ना गोट ग्राम है, जिसमें महेश्वर राय एवं सुभाष यादव का घर है । प्रश्नाधीन पथ के दूसरा छोर पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित पथ बथनाहा से कोरियाही में मिलता है । प्रश्नाधीन पथ के 700 मीटर लेकर अगले 1300 मीटर के लंबाई में मात्र 7 से 8 घर का बसावट रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेट वर्क में नहीं लिया जा सका है । संप्रति पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टर्न:7/राजेश/8.3.17

डा0 राजेश कुमार:- अध्यक्ष महोदय, यह जो छत्तरघाट है और जो डोंक नदी है, यहॉ से काफी दूरी है और वहॉ की जो आबादी है निकटतम वह काफी प्रभावित करता है, तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसकी दूरी को देखते हुए निकट भविष्य में इसपर पुल बनाने का कष्ट करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1084 (श्री अत्रीमुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग । यह प्रश्न स्थानान्तरित हुआ है भवन निर्माण विभाग से ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, समय दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जॉए ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 08 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :

श्री संजय सरावगी, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्यासागर केशरी, श्री अरुण कुमार सिन्हा, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री केदार प्रसाद गुप्ता । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शून्यकाल में आप ही लोगों का है । क्या है बोलिये ?

श्री संजय सरावगी: यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । पूरे राज्य में अध्यक्ष महोदय 62 लाख सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों को कई माह से, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुकों को पिछले तीन सालों से और कबीर अन्त्येष्टि योजना के लाभुकों को पिछले तीन सालों से कोई भुगतान नहीं हो रहा है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है । अब शून्यकाल ।

शून्यकाल

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अमित कुमार ।

श्री अमित कुमारः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के चैनपुरा निवासी सुनील कुमार, पिता रंजीत राय की हत्या दिनांक 04.03.2017 को हरिहरपुर गॉव में कर दी, जिससे विधि-व्यवस्था पर प्रश्न लग गया है । मृतक परिजनों को 20 लाख मुआवजा भुगतान करते हुए थाना कांड सं0-75/2017 के नामजद अभियुतों को शीघ्र पकड़ा जाय।

श्री शमीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर शहर में श्री विजय कुमार सब एडीटर के पद पर हिन्दुस्तान प्रेस में कार्यरत थे, जीप पलटने से दिनांक 23.2.2017 को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी के पास मृत्यु हो गयी थी । ये मोकिलपुर गॉव के रहने वाले थे ।

अतः सरकार आश्रित परिवार को नौकरी तथा दस लाख रुपये अनुग्रह राशि उपलब्ध करावें ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के बांसगांव पंचायत के एस. एच. 98 पर बसे गांव विकनी टोला से बीस वर्ष पुरानी एक ईंट की सड़क विशुनपुर होकर गोविन्दपुर तक जाती है. 15 हजार ग्रामीण जनता के लिए एक मात्र ग्रामीण सड़क जर्जर हो चुकी है. मैं सड़क की पक्कीकरण की मांग करता हूं।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलांतर्गत मधुबनी शहर में पेय जलापूर्ति की पाईपलाईन 50 वर्ष पूर्व बिछायी गयी थी जो जर्जर होने के कारण 25 वर्षों से बंद है । मधुबनी शहर पूरे राज्य में इकलौता शहर है जहां पाईपलाईन जलापूर्ति शून्य है ।

अतः मधुबनी शहर में पाईपलाईन से जलापूर्ति की मांग करता हूं ।

श्रीमती बेबी कुमारीः अध्यक्ष महोदय, टी.ई.टी./सी.टी.ई.टी उतीर्ण एवं सरकार द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थी को नई परीक्षा शुरू होने से पहले मार्च 2017 तक रिक्ति के आधार पर बहाली का एक मौका दिया जाए ।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के नावाडीह खुर्द के भंवरिया नाला में चेक डैम नहीं रहने से 800 एकड़ जमीन बंजर रह जाता है। गर्मी में जल स्तर ढाई सौ फीट नीचे चला जाता है।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त जगह पर चेक डैम निर्माण करावें ।

श्री मो0 नेमातुल्लाहः अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के पंचायत महम्मदपुर में सारण मुख्य नहर पर नवलखा पुल के पास स्थित नाला सफाई के अभाव में बन्द हो गया है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ जमीन पर उपजी फसल प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो रही है । अतः जनहित एवं किसानहित में सरकार उक्त नाला की सफाई शीघ्र करायें ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-6882 दिनांक 12/05/2015 के आधार पर राज्य में संविदा पर कार्यरत सभी 16,878 प्रेरकों/समन्वयकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सामान कार्य

के लिए सामान वेतन के आधार पर नियुक्ति करते हुए सभी सरकारी सुविधा बहाल किया जाय।

डा0 राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया प्रखण्ड के पश्चिमी सुन्दरापुर में आगलगी के कारण ढ़ाई सौ परिवार घर से बेघर हो गये हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं की उन सभी परिवारों को तत्काल राहत, सरकारी सहायता एवं प्रधानमंत्री आवास देने का कष्ट करें ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर स्थित भीगो श्मशानघाट के दोनों ओर पदाधिकारियों के मिलीभगत से 30 से 40 फीट गहरा अवैध खनन किया गया, कटाव के कारण श्मशान की भूमि का अस्तित्व संकट में है, सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराते हुए, श्मशान की अस्तित्व रक्षा के लिये कार्रवाई करें ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, राज्य में अत्याधुनिक संचार साधनों की उपलब्धता से अपराध का स्वरूप भी बदला है।

जनहित में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी जिला एवं अनुमण्डल मुख्यालयों सहित शेरघाटी अनुमण्डल में साइबर सेल (cyber cell) गठन की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड में महिला महाविद्यालय के अभाव में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतएव प्रखंड मुख्यालय में राजकीय महिला महाविद्यालय शीघ्र खोलने के लिए मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर प्रखण्ड में मध्य विद्यालय सिपहां के भूमिदाता पुत्र के द्वारा विद्यालय के अगल-बगल आम गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन जमीन को मुक्त कराने की मांग करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत सिरीस-नबीनगर पथ में बैरिया रामरेखा नदी में पुल न होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। नबीनगर तथा बारून जाने में 20 किलो मी0 घुमकर जाना पड़ता है। 30 कि0मी0 की सड़क औचित्य बिहिन है।

सरकार रामरेखा नदी में शीघ्र पुल निर्माण करावे ।

श्री विद्या सागर केसरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड में पड़नेवाली सड़क जो फारबिसगंज, अमहारा, रमई होते हुए खवासपुर तक जाती है, पिछले वर्ष आयी

प्रलयंकारी बाढ़ ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त एवं जर्जर कर दिया है । लोगों एवं वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ।

बरसात से पूर्व सड़क मरम्मति का सदन से मांग करता हूँ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर के तरारी प्रखंड अंतर्गत वेलडिहरी-फतेहपुर राजवाहा में खेतों की सिंचाई हेतु वर्ष 1985 में ही सिंचाई विभाग द्वारा 7 बोरिंग (नलकूप) लगाया गया है. लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है. नलकूपों को अविलंब चालू करने की मांग करता हूं ।

डॉ0 मो0 नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत प्रखंडों में आँगनबाड़ी महिला परिर्वेक्षिका की बहाली अप्रैल 2013 और अगस्त 2013 में हुई थी । वे महिला परिवेक्षिका का स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया है जबकि महिला परिवेक्षिका लगभग चार साल से एक ही प्रखंड में पदस्थापित है ।

अतएव मैं सदन के माध्यम से समय अवधि अधिक होने के कारण इनकी स्थानान्तरण की माँग करता हूँ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण सूचना ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/8-3-17

ध्यानाकर्षण सूचना

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह,नितिन नवीन एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(भवन निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, पटना स्थित दारोगा प्रसाद राय पथ में विधायक आवासीय परिसर के ब्लॉक ए. बी. सी. सहित माननीय विधायकगण के अन्य आवासीय परिसर में सफाई, सुरक्षा, जल निकास एवं शुद्ध पेयजल आदि नागरिक सुविधाओं की अति आवश्यकता है।

अतएव विधायक आवास परिसर दारोगा प्रसाद राय पथ सहित अन्य विधायक आवास परिसर को भी नागरिक सुविधा युक्त बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: महोदय, पाटलीपुत्रा भवन प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत दारोगा प्रसाद राय पथ के ब्लाक ए .बी. सी. में माननीय विधायकगण के आवासीय एवं परिसर में सफाई, कचरा उठाव का कार्य नियमित रूप से किया जाता है । जल निकासी की भी व्यवस्था ठीक है । पुराने सिवरेज लाईन को बदलने का भी कार्य शीघ्र शुरू किया जा

रहा है । माननीय के आवासों एवं परिसरों में जलापूर्त्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है । हमेशा शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति की जाती रही है । इसके अतिरिक्त अन्य परिसर में भी विभाग द्वारा समुचित साफ-सफाई एवं जलापूर्त्ति की व्यवस्था संचालित है। फिर भी समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दिया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं दारोगा राय आवासीय परिसर के ब्लॉक बी. के 303 में रहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ सदन में कि मंत्री जी ने जो कहा है कि भवन निर्माण विभाग को कचरा उठाने की जवाबदेही दी गयी है अगर अभी उस परिसर से एक ट्रक कचरा नहीं निकले तो मैं विधायिकी छोड़ दूंगा । मैं सदन में चैलेंज करता हूँ, कि जलजमाव वहां नहीं हो, वहां कचरा नहीं हो अगर वहां सैंकड़ों बोझा कपड़ा नहीं जमा किया गया हो। वहां के पूरा परिसर में पानी लगा हुआ है, कचरा भरा हुआ है बड़े बड़े कीड़े नीचे चल रहे हैं हमलोगों को उसमें से निकलना मुश्किल है । शुद्ध पेयजल की स्थिति यह है कि वह टंकी फूटा हुआ है, पानी का सप्लाई नहीं है । उसमें पानी पीने के लिए जो शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए, आर0ओ0 लगना चाहिए किसी भी फ्लैट में नहीं है और नीचे का टंकी भी फूटा हुआ है जहां शौचालय का टंकी है, एक तो नीचे के निकलने का जो रास्ता है उसका बनावट इस प्रकार से है कि नीचे सर्वेन्ट क्वार्टर और गैरेज बना हुआ है और सारे सर्वेन्ट क्वार्टर अकुपाईड है उसे कोई न कोई अकुपाई किये हुए है, बोझा का बोझा कपड़ा धो रहा है, लोग मरई बनाने हुए हैं उसमें तरह तरह का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आदमी के रहने का वह जगह ही नहीं है, सुअर जैसे रहता है सरकार बतलाये इस पर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं तो इसका हम फिर से समीक्षा करा कर के जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए हम निर्देश देंगे ।

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्यों के आवास का प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह इसकी अलग से समीक्षा करायेंगे तो हमलोग भी चाहते हैं कि जो भी माननीय विधायक उस परिसर में रहते हैं, उन लोगों को जो -जो असुविधा हो रही है वे सरकार को लिखकर भी दे दें जिससे कि समीक्षा में उन सब बातों का ख्याल रखा जायेगा । आप सब लोग लिखकर भी दे दीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, हम आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहेंगे लिखकर तो हमलोग देंगे ही लेकिन एक कमिटी बनाकर आप होली के पहले चूंकि होली का समय है होली में सब लोग सफाई पर घ्यान देते हैं , साफ सफाई रखना हमलोगों का फर्ज भी है और कर्त्तव्य भी है और सरकार का भी दायित्व भी है कि वह जगह को साफ सफाई करावे । होली के पहले एक बार उसकी पूर्ण सफाई तो करवा दीजिये । पानी की व्यवस्था तो ठीक करवा दीजिये, आर0ओ0 तो लगवा दीजिये, सभी

विधायकों के आवास में एक-एक आर0ओ0 तो लगवा दीजिये । माननीय नीतीश कुमार जी भी सदन में हैं पिछली बार जब चन्द्रमोहन राय जी पी0एच0ई0डी0 के मंत्री थे तो सभी विधायकों के आवास में एक-एक आर0ओ0 लगा था तो कम से कम एक -एक आर0ओ0 तो लगवा दीजिये जिससे सबको शुद्ध पानी पेयजल उपलब्ध हो जाय । इतना तो कम से कम आश्वासन दीजिये, कोई बड़ी चीज तो है नहीं।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: साफ सफाई का हम करवा लेते हैं । आर0ओ0 वगैरह का भी देखते हैं।

अध्यक्ष: सरकार ने सफाई का आश्वासन दिया है और आपलोग भी होली में उसको गंदा नहीं करने का आश्वासन दे दीजियेगा ।

डॉ0 अशोक कुमार एवं श्री दिनेश चन्द्र यादव,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद अधिनियम, 1992 को बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद(निरसन)अधिनियम 2007 द्वारा निरसित कर दिये जाने के कारण बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद अधिनियम, 1992 द्वारा किये गये सभी प्रावधान निरसित हो गया। बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद अधिनियम, 2007 में किये गये प्रावधानानुसार विघटित बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में समाहित कर दिया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(संशोधन)अधिनियम, 2007 के द्वारा किये गये प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों के द्वारा स्थापित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्धता देने तथा वापस लेने की शक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रदत्त है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम,1952 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-17 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा अद्यतन संशोधित) में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित करने का प्रावधान है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(उच्च माध्यमिक) संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-4 की कंडिका 15(3) में वित्तीय अनियमितता की स्थिति में विद्यालय की सम्बद्धता वापस लिये जाने का प्रावधान है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सम्प्रति इंटर महाविद्यालय के प्रबंध समिति के गठन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952(यथा अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत गठित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता नियमावली, 2011

(यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों में किसी प्रकार के संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

डॉ0 अशोक कुमार: महोदय,मैं सरकार से जानना चाहता हूँ बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद अधिनियम 1992 को निरस्त कर दिया गया और उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अन्तर्गत समायोजित कर लिया गया लेकिन मेरा प्रश्न इसमें स्पष्ट है कि जो समिति थी उस समय तो वित्त रहित और सरकार का एक पैसा उन महाविद्यालयों में नहीं जाता था जब से सरकार ने करोड़ों रू0 उसे अनुदान स्वरूप देना प्रारंभ किया तो उस स्थिति में उन समितियों से जन प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी इन लोगों को वहां से हटा लेने का क्या औचित्य है ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : ये निर्णय 2007 में मर्जर किया गया, 20.11 का निर्णय है और अगर इसमें प्रावधान किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रावधानों के अनुसार जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में स्कूल चलते हैं लोकल मैनेजमेंट सिस्टम से उस तरह इसको मर्जर करने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने नियम के अनुसार इसको किया है क्योंकि जब बिहार इंटरमीडियट शिक्षा परिषद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मर्ज कर दिया गया तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रावधानों के अनुसार स्कूल को इंटरमीडियट प्लस-टू तक चलाया जा रहा है लेकिन इस पर अगर उच्चस्तरीय कोई निर्णय करना चाहते हैं तो अध्यक्ष जी अपने स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक करायें उसके बाद उस पर जो निर्णय होगा उसको हमलोग मानने को तैयार हैं।

अध्यक्ष: ठीक है।

डॉ0 अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय अगर आप अपने स्तर से इस पर निर्णय करने के लिए बैठक बुलायेंगे इस मामले को देखेंगे तो ठीक है लेकिन मेरा कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केवल परीक्षा संचालन के लिए होती थी और अब उसका अधिकार दिया गया है इंटरमीडियट शिक्षा परिषद वाला, इंटरमीडियट शिक्षा परिषद एक समेकित रूप से पूरी तरह से विद्यालय के पूरी नियंत्रण एवं शिक्षा व्यवस्था को देखती है (क्रमश:)

टर्न-9/मधुप/08.3.2017

...क्रमश:...

डॉ0 अशोक कुमार : तो इस तरह से विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने ढ़ंग से तो कर दिया लेकिन इससे कितना बड़ा अहित हो गया है, हमलोग सारे जन-प्रतिनिधि बैठे हुये हैं । उसके अभाव में अब स्कूलों में भी गठित हो रहा है तो उसमें अध्यक्ष ही होते हैं क्षेत्र के, तो इसमें इंटर कॉलेज में क्यों नहीं होंगे जन-प्रतिनिधि और पदाधिकारी ? जबकि करोड़ों रूपया सरकार का जाता है, उसपर कोई नियंत्रण नहीं है । अपने लोग लेते हैं और स्वयं बॉट लेते हैं, पूरा कुप्रबंधन है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो परिवर्तन आया है, 10 वर्ष हो गये उसके। अब बदली हुई परिस्थिति में आप जन-प्रतिनिधियों को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो यह पृथक विचार है लेकिन उस समय जो निर्णय लिया गया कि कॉलेज एडुकेशन से इंटरमीडिएट को हटा दिया जाय और पूरे देश में जो प्रक्रिया थी, जो परम्परा चल रही थी उसके साथ बिहार को जोड़ने के लिये यह किया गया । स्कूल एडुकेशन +2 तक का है और कॉलेज एडुकेशन उसके बाद होता था । यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में भीषण रूप से कंफ्यूजन था, कुछ स्कूल में भी होता था, कुछ कॉलेज में भी होता था। तो वह एक सुविचारित निर्णय है जो 10 वर्ष पहले लिया गया था, आप अचानक आज 10 वर्ष के बाद इस बात को कहेंगे तो उसके पीछे कारण यही था कि पूरे देश में जो स्कूल एडुकेशन और कॉलेज एडुकेशन का सेग्रीगेशन था, वह बिहार में भी लागू हो । पूरे देश के साथ यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिये जिस प्रकार की प्रक्रिया देश में है, इसलिये यह निर्णय लिया गया था ।

इसके पीछे जो कारण था वह हमने बता दिया और वह 10 वर्षों से चल रहा है । जब अचानक आप कोई नया काम करेंगे तो कई तरह की परेशानी आती है । स्वाभाविक है यहाँ की प्रक्रिया थी कॉलेज में भी पढ़ाई होती थी, स्कूल में भी होती थी, उसको एक तरह का बनाने के लिये यह निर्णय लिया गया था लेकिन अगर मान लीजिये कि इसमें वित्त रहित जिसको कहा जाता था, अब तो कोई वित्त रहित है नहीं, वित्त रहित समाप्त हो गया । वित्त रहित तो जब आपलोग पूरे बहुमत में शासन में थे उस समय की चीज थी । हमलोगों ने तो वित्त रहित को एक तरह से समाप्त किया और परफौरमेंस लिंक्ड ग्रांट देना शुरू किया कि कितने आपके स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं, क्या परफौरमेंस है, वह किया गया । यह निर्णय लिया गया, दोनों सदनों में जो प्रतिनिधि थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखते थे, उनलोगों के साथ परामर्श के बाद हुआ । उस समय भी एक ही बात हुई थी, जो आज बार-बार उठता है, फिर से यह सवाल उठने लगा है कि इसका टेक-ओवर कर लीजिये । हमने उस समय यही कहा था कि टेक-ओवर किसी कीमत पर सरकार नहीं करेगी । अपने नियंत्रण में नहीं लेगी क्योंकि उनके यहाँ जो नियुक्तियाँ हुई हैं वह पूर्व की नियुक्तियाँ हुई हैं और जो सरकार के नियम हैं, वह भिन्न प्रकार के नियम हैं, इसमें आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे, शिक्षकों को नियुक्त करने की अपनी नियमावली है । इस आधार पर तो वहाँ नियुक्ति हुई नहीं है तो हम इसको पूरे तौर पर लेंगे और फिर उन टीचर्स को या उनके इम्पलॉइज को भी हम ले लें, सरकारी नियमों के मुताबिक तो यह सम्भव नहीं होगा । लेकिन जो वित्त रहित है और स्थिति खराब है कि एक जमाने से वहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं और उनको किसी प्रकार का एक निश्चित तौर पर कुछ पैसा नहीं मिल पाता था । इसलिये यह निर्णय बहुत ही विचार-विमर्श के बाद और दोनों सदनों में जो तत्कालीन

सदस्यगण थे, जो इस विषय को उठाते थे, खासकर उच्च सदन में यह प्रश्न बहुत उठता था, तो उसके बाद चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है । अब 10 वर्ष में उसको भुला देना तो यह उचित बात नहीं है लेकिन आप जो कह रहे हैं - मैनेजमेंट कमिटी, वह जो मैनेजमेंट कमिटी है, चूंकि वह प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, उसकी मैनेजमेंट कमिटी में आप जाना चाहते हैं, अब वह जन-प्रतिनिधियों के लिये विचार करना पड़ेगा । अच्छा हुआ इन्होंने प्रस्ताव दे दिया है कि अध्यक्ष महोदय के स्तर पर बातचीत कर लीजिये । एक बार सोच जरूर लीजियेगा कि अगर एक बार आप अध्यक्ष बन जाते हैं और वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जिम्मेवारी जन-प्रतिनिधियों पर भी आयेगी । वह कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं, वह सरकार के द्वारा गवर्नड बॉडी तो है नहीं । सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है तो सहायता के कारण बहुत चीजों को देखना पड़ेगा । ऐसा माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हुआ है ।

उस हिसाब से जो कुछ भी करना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसपर जरा गंभीरता पूर्वक विचार कर लीजियेगा कि एक प्राइवेट स्कूल है और उसको सरकार तो सहायता दे रही है, सरकार तो बहुतों को सहायता देती है । पूरा जो मॉयनोरिटीज इंस्टीच्यूशन है उसको पूरे तौर पर सहायता देती है । अन्य कई बॉडीज को सहायता देती है लेकिन उनका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है । अब जैसे मदरसा स्कूल है, उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण तो सरकार के पास नहीं है लेकिन हम पूरे तौर पर सहायता देते हैं ।

उसी तरह से इस तरह के स्कूल्स हैं, उनको सहायता यानी परफौरमेंस लिंक्ड ग्रांट, जैसा आपका परफौरमेंस होगा उसी हिसाब से आपको ग्रांट की राशि निर्धारित होगी लेकिन उसके मैनेजमेंट में सीधे तौर पर जन-प्रतिनिधि को, सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को इनवॉल्व किया जाय, यह एक ऐसा विषय है कि इस पर जरा गंभीरता पूर्वक सोच लीजियेगा क्योंकि कल होकर प्राइवेट इंस्टीच्यूशन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी अगर होगी तो उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है जैसा कि माननीय मंत्री ने आपको जवाब में ही कह दिया कि अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जायेगी तो उनकी सम्बद्धता रद्द कर सकते हैं आदि-आदि, यह सब प्रावधान हैं ।

उसके साथ अपने को जोड़ना, हमलोगों को कोई एतराज नहीं होगा सरकार के स्तर पर लेकिन हम जरूर कहेंगे कि इस विषय को एक बार गंभीरता पूर्वक जरूर सोच लीजियेगा कि इसमें इनवॉल्व होना चाहिये प्रत्यक्ष तौर पर या नहीं ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ ।

अब सभा की कार्यवाही 2: 00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–10/आजाद/08.3.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा ।

इसके लिये 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	– 59 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	– 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 20 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल)	– 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	– 02 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	– 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 01 मिनट
निर्दलीय	– 03 मिनट
कुल	–180 मिनट

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 252,51,38,80,000/– (दो सौ बावन अरब एकावन करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मॉग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री नितिन नवीन, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री राघव शरण पाण्डेय एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह से कटौती-प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं । इसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा अनुपस्थित है, दूसरा प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का है । अतएव माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटायी जाय राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।''

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण है । शिक्षा का मुख्य लक्ष्य युवा पीढ़ी का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना होता है । लेकिन बिहार सरकार शिक्षा के लक्ष्य से भटक गई है । जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत सरकार की परिकल्पना है, उसे लागू करने में सरकार उदासीन है और पूरे राज्य में अगर यह कहा जाय कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । घोटाले पर घोटाला, बच्चों को किताब नहीं, परीक्षा फल विलम्ब से प्रकाशित होना, छात्रों का बड़ी संख्या में राज्य से पलायन होना यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि शिक्षा विभाग बिहार के भविष्य को संवारने में गंभीर नहीं है । बड़ी-बड़ी बातें सरकार करती है महोदय लेकिन आज भी बिहार की जो स्थिति है, आज भी बिहार की जो लिट्रेसी रेट है, वह देश में सबसे नीचे है, 36वां स्थान पर है । आज भी हमारे राज्य के 37 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, 63.82 प्रतिशत लोग मात्र साक्षर है और जबकि केरल का स्थान प्रथम है, जहां 93.91 प्रतिशत है और राज्य पूरे देश में 36वें स्थान पर है । मंत्री महोदय को अपने जवाब में निश्चित रूप से बताना चाहिए कि बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और आज राज्य में लिट्रेसी रेट पर 36वें स्थान पर क्यों है ? इसपर माननीय मंत्री को निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुल 70934 सरकारी विद्यालय है, जहां सरकारी योजनायें संचालित होती है । यू-डेस्क पर जारी 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 71000 विद्यालयों में 1018 विद्यालय ही मानक पर खड़े हैं और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बिहार का एक भी विद्यालय उसके मानक पर खड़ा नहीं उतरता है । शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राथमिक विद्यालय में 30 छात्र पर एक शिक्षक, मध्य विद्यालय में 35 छात्र पर एक

शिक्षक होना चाहिए लेकिन बिहार की सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में फेल है । आज भी 2,78,602 शिक्षकों की कमी है और अध्यक्ष महोदय, सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, आज भी 62 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय के छात्र अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं । सरकार को अपने जवाब में बताना चाहिए कि क्यों नहीं 62 प्रतिशत छात्र अपने प्राथमिक शिक्षा को पूरा कर पाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की भी बिहार में हालत बद से बदतर है ।

महोदय, हमलोग सरकारी विद्यालय में पढ़कर आये हैं लेकिन आपकी सरकार ने जो सरकारी विद्यालयों की ऐसी स्थिति कर दी है, यहां के अधिकांश लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे । लेकिन आज कल्पना नहीं की जा सकती है, जो स्थिति इन लोगों ने कर दी है । उच्च शिक्षा में भी बिहार की हालत बद से बदतर है । अध्यक्ष महोदय, टोका-टोकी कर रहे है, फिर हम भी इनको बोलने नहीं देंगे । माननीय मंत्री लोग टोका-टोकी करते हैं अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की हालत मैं बताता हूँ, बिहार में वर्स्ट है । एक लाख पात्र आबादी है जो 18 से 23 वर्ष का, एक लाख पर मात्र 6 महाविद्यालय हमारे राज्य में है, जबकि देश में एक लाख पात्र आबादी पर 26 महाविद्यालय है । यह देश में सबसे निचला स्तर बिहार की है । डेन्सीटी में अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालयों में छात्रों की डेन्सीटी एवरेज 2142 छात्र एक महाविद्यालय में हैं, जो देश में सबसे ज्यादा डेन्सीटी बिहार की है, यह हालत है इनके शिक्षा की । महोदय, जो हालत है, जिसकी कल चर्चा हो रही थी , कक्षा-5 के 72 प्रतिशत बच्चे भाग नहीं दे सकते, कक्षा-8 के 39 प्रतिशत बच्चे भाग नहीं दे सकते, कक्षा-8 के 44 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी नहीं समझते अध्यक्ष महोदय, जो हालत है शिक्षा की, पूरा जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है । मैं शिक्षा के अधिकार कानून की बात कर रहा था, जो हालत है बिहार के शिक्षा के अधिकार कानून का है, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 में गरीब बच्चों का एडमिशन होना था और पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन्टरवेन किया था और कहा था इस व्यवस्था को हम बदल देंगे, इसको हम सही करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जो हालत है, मैं केवल पटना की बात करता हूँ, जहां सरकार बैठी है, जहां माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां शिक्षा मंत्री बैठे हैं, मैं एक आंकड़ा पेश पटना का करना चाहता हूँ । 2012-13 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पटना जिला में 954 छात्रों का नामांकन किया गया था, 2015-16 में 1482 और अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में यह घटकर मात्र 846 गरीब बच्चों का नामांकन किया गया है । जहां सरकार बैठी है, वहां यह हालत है । अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में 112 विद्यालयों ने पटना जिला में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत छात्रों का नामांकन किया था और 2016-17 में मात्र 86 विद्यालयों ने नामांकन

किया, मुख्यमंत्री और मंत्री जी यहां आश्वासन देते हैं,

..... क्रमशः .....

टर्न-11/शंभु/08.03.17

श्री संजय सरावगी : क्रमशः.....उसकी निजी विद्यालय सी0बी0एस0इ0 और आइ0सी0एस0इ0 माखौल उड़ाते हैं, सरकार कुछ कर दे हम जो कहेंगे, वही होगा। अध्यक्ष महोदय, यह हालत है, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, अपने जवाब में कि यह हालत शिक्षा के अधिकार कानून में जो गरीब बच्चों की पढ़ाई होनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट टू प्वाइंट बात कर रहा हूँ और माननीय मंत्री जी से भी अपेक्षा करता हूँ कि प्वाइंट टू प्वाइंट जवाब देंगे, भ्रमजाल में, केवल अखबार में छपने के लिए नहीं बोलेंगे, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। महोदय, पूरे देश में टॉपर्स घोटाले ने शर्मसार कर दिया बिहार के छात्रों को, जहां भी छात्र जाते हैं तो कहते हैं कि टॉपर वाली डिग्री तो फर्जी डिग्री है, यह बिहार की डिग्री है। कितना शर्मसार पूरे देश और विश्व में बिहार के छात्रों को होना पड़ता है, यह तो हालत है। महोदय, इनको अपने जवाब में बताना चाहिए क्यों घोटाले पर घोटाला हो रहा है- कागज घोटाला, कॉपी घोटाला, टॉपर घोटाला, घोटालों पर घोटाला शिक्षा विभाग में अध्यक्ष महोदय, यह हालत इस सरकार ने की है। महोदय, सात निश्चय नाम दिया गया- आर्थिक हल युवाओं को बल और इसकी स्थिति लगता है इनलोगों के पार्टी में जो आपस में फंसा हुआ है जिसके कारण 2017-18 में जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होनेवाला है, एक शब्द भी इसके बारे में इनके वक्तव्य में नहीं है। महोदय, लगता है महागठबंधन में आपस में जो फंसा हुआ है, एक शब्द भी 2017-18 के इनके वक्तव्य में नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा कर देते हैं और इनसे राय नहीं लेते हैं, इसीलिए एक शब्द भी नहीं है। महोदय, आर्थिक हल युवाओं को बल की स्थिति क्या हो गयी है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिये, इनको बोलने दीजिए।

श्री संजय सरावगी : महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

श्री शकील अहमद खां : मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ।

श्री संजय सरावगी : कोई व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था है।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री शकील अहमद खां : ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का.....

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सात निश्चय है- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना....

अध्यक्ष : आपके लिए दो मिनट समय है।

श्री संजय सरावगी : दो मिनट दया कर दीजिए सर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया और माननीय मंत्री जी 2016-17 का भाषण पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि 1 अप्रील से लागू करेंगे और ये लागू हुआ 2 अक्टूबर से, चलिये लागू हुआ। इन्होंने कहा कि 2016-17 में हम 5 लाख विद्यार्थियों को इसमें लाभ देंगे, जो 4 लाख ऋण की गारंटी बिहार सरकार दी है, लेकिन 5 लाख में से मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूँगा कि माहवार बतावें कि अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी कितने लोगों को यह आर्थिक हल युवाओं को बल कितने लोगों को इसमें लाभ मिला है? मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि 5 लाख में से 2 हजार लोगों को भी अभी तक इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना नौजवानों को भरमा रहे हैं, आर्थिक हल युवाओं को बल और पहले कहे कि बेरोजगारी भत्ता हम इंटर पास सभी को देंगे और अब कहते हैं कि जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेगा उसको हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। इंटर के बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेगा उसको हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, मतलब ये बाध्य कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता लें, आप जवाब दीजिएगा कि इन्टरमीडियेट में पढ़ाई वाले को बेरोजगारी भत्ता देंगे। महोदय, जब समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलेगा- उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि एक जगह हमारे शिक्षक 8 हजार, 10 हजार उन्हें मिलता है और उसी विद्यालय में 50 हजार मिलता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है। महोदय, वित्त रहित- कितने छात्र हमारे वित्त रहित शिक्षक हैं, उनको भी सरकार वित्त रहित को 5-5 साल से पैसा नहीं दिया, पैसा के लिए वित्त रहित शिक्षकों को- जो इस सरकार की हालत है, यह मेरा आरोप है कि यह सरकार शिक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है। महोदय, 2100 कुछ मध्य विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया है, 500 से उपर भवन बनकर तैयार है, खंडहर हो रहा है, लेकिन आज तक हेंड ओवर, टेक ओवर के कारण कहीं भी पंचायतों में, प्लस टू विद्यालयों में पढ़ाई नहीं चालू हुई, क्यों नहीं हुई ? साल-साल भर से क्यों भवन पड़ा हुआ है ? माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अभी तक प्रबंध समिति का निर्णय नहीं हुआ। मध्य विद्यालय में वार्ड मेम्बर प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। उसको उत्क्रमित करके प्लस टू कर दिया गया, उसका क्या होगा ? जल्द से जल्द जो प्लस टू का उत्क्रमित विद्यालय है उसको जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाय। मेरे क्षेत्र की एक दो समस्या है। राजेन्द्र कन्या प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेरे घर से सौ मीटर की दूरी पर है और देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के नाम पर है, अभी तक वहां प्लस टू का भवन नहीं बना है। माननीय मंत्री जी को मैंने इसके बारे में

लिखकर भी दिया था। दरभंगा में एक मुकुन्दी चौधरी प्लस टू उच्च विद्यालय है वहां का सौ साल पहले का भवन था, पूरा खंडहर हो गया है और अभी तक वहां भी मैंने लिखकर दिया था कि वहां भी भवन बनवा दें। महोदय, दरभंगा के बेलवागंज के वंशीदास मध्य विद्यालय एक कैंपस में तीन विद्यालय चल रहा है और बरसात के दिनों में पानी लगा रहता है।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री संजय सरावगी : महोदय, एक मिनट वहां बाउंड्री नहीं है, कमरा नहीं है उसको बनवा दें। मध्य विद्यालय सोनहान जो सदर प्रखंड में है। तीन साल पहले जिला पदाधिकारी महोदय उसको प्लस टू में उत्क्रमित किये थे और अभी तक नहीं हुआ है। महोदय.....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, इधर चलता है उनको मालूम हो जाता है हुजूर, लेकिन उपेन्द्र कुशवाहा से चल रहा है वह मालूम हुआ है कि नहीं महोदय को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं ?

श्री संजय सरावगी : उसमें मेरे से ज्यादा आपको जानकारी है।

डा0 सुरेन्द्र कुमार : महोदय, आज इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में समाज के, शिक्षा विभाग के बजट पास होने के पक्ष में भाषण के लिए आपने मौका दिया है, बहुत-बहुत शुक्रिया। यह जग जाहिर है कि बिना शिक्षा प्रणाली के समाज सुधार की बात करना मुनासिब नहीं है। जिस तरह समाज में हमलोगों का इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरूष राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक स्थापित हुए उनके जीवन काल में अगर चमक हुई है तो वह शिक्षा प्रणाली से हुई है। आज महागठबंधन की जो सरकार है जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे विभाग के शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी का जो आपस में सामंजस्य स्थपित होकर करके शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का जो कदम बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है और आज देखा जा रहा है कि बिहार में जो शिक्षा पद्धति आगे बढ़ रही है- प्राथमिक विद्यालय से लेकर मध्य विद्यालय और हायर एजुकेशन तक वाकई में यह काबिले तारीफ है। इसलिए क्योंकि गांव गंवई में जो 80 परसेंट, 85 परसेंट अवाम है उनके पी0जी0 हैं, उनके छात्र-छात्राएं हैं उनको शैक्षणिक व्यवस्था से लैस करके इस महागठबंधन की सरकार ने जब गांव की सड़कों पर पोशाक पहनकर के हमारी बच्ची बच्चियां, साइकिल पर चढ़कर जब स्कूल तक पहुंचती है तो समाज के लोग इस चीज को अपनी नजर से देख रहे हैं और शिक्षा के प्रति जो जागृति हुई है यह दर्शा रहा है कि बिहार बढ़कर के रहेगा और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आपसी सामंजस्य से ये महागठबंधन की सरकार स्थपित हुई है।

क्रमशः

टर्न–12/अशोक/08.03.2017

डॉ सुरेन्द्र कुमार : क्रमशः मैं यह कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय के साथ बिहार का सर्वांगीण विकास का जो कदम बढ़ा है उसका बखान भी करे तो इसके लिए न तो शब्द है और न ही संटेंस हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री मो. इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

डॉ0 सुरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग की तरफ देश और दुनिया की निगाह है, इसलिए निगाह है कि शिक्षा विभाग के प्रति आज सरकार इतनी सशक्त है कि आज प्राईमरी एडुकेशन से लेकर हायर एडुकेशन तक लोग एक्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी हाल में मैट्रिक का परीक्षा हुआ है, हर जिला में, बिहार के हर जिला में, जो छात्र, छात्राओं में उत्सुकता देखी जा रही है, यह दर्शाता है कि आज बिहार की शिक्षा पद्धति में जो गुणवत्ता आयी हैं, वह गुणवत्ता कहीं न कहीं इस राज्य को बहुत आगे ले जायेगा । सभापति महोदय, आज महागठबन्धन की सरकार ने शिक्षा को आगे करने के लिए, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये कई योजनायें चला रही है । जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण जो उच्च शिक्षा के इच्छुक के विद्यार्थी हैं उनको 1 अप्रील, 2016 से ही 4 लाख शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी लिया है । मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में सुधार हुआ है और शराबबन्दी के पश्चात शिक्षा के प्रति जो एक रूझान आने वाले पीढ़ी में उत्पन्न हुआ है वह दर्शाता है कि ''हम सब का यह अभियान हैं नशा मुक्ति पैगाम हैं''। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसी योजनायें बनाई गई हैं जिससे हमारे नौजवान छात्र, छात्राओं इससे लैस होंगे और आगे चलकर के बहुत सारे जो उनके शैक्षणिक महौल है उसमें सुविधा मिलेगी । हमारी जो सरकार है वह सरकार काफी उत्साहित होकर के बजट को तैयार की है और केन्द्र सरकार हमारे जो अभी विपक्ष के साथी बोल रहे थे, आज केन्द्र सरकार की उदासीनता के बावजूद राज्य सरकार जो 2017–18 में बजट का प्रावधान की है 252 अरब 51 करोड़ 39 लाख रूपये जब कि केन्द्र सरकार नजरअंदाज कर रही है राज्य सरकार को, उसके बावजूद अपने संसाधन से राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली को बहुत आगे लेकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं ,राज्य सरकार 5 हजार करोड़ रूपया मद्यनिषेध के कारण लॉस में हैं फिर भी उस तरह का एक कदम, एक कड़ा कदम उठाकर के भी शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो, शिक्षा प्रणाली कैसे मजबूत हो हमारे छात्र, छात्रायें कैसे शैक्षणिक महौल में आगे बढ़े हैं, इसके लिए कटिबद्ध हैं । सभापति महोदय, मेरा कुछ सुझाव है, जिस तरह किसान खेती करते, मिट्टी को काफी मेहनत करके उपजाऊ बनाते, बहुत खाद पदार्थ उसमें देते उसी तरह आज जरूरत

है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको शैक्षणिक महौल से लैस किया जाय। इतिहास गवाह है बिहार राज्य में इतने मेधावी शक्ति वरदान है यहां कि आगे चल कर के देश और दुनिया में हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे लेकिन कही न कहीं आज हमारे बिहार के आने वाले पीढ़ी हैं वर्त्तमान पीढ़ी है उसके अन्दर वह जज्बा है कि आज पूरे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरे देश में अपने मेरिट की पहचान कम्पटीशन फेस करके दर्शाते हैं, चाहे यू.पी.एस.सी. की कम्पटिशन हो, चाहे एम्स का कम्पटीशन हो, चाहे इंजीनियरिंग का कम्पीटीशन हो चाहे और पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बैंक हो, एस.एस.सी. हो रेलवे हो, आज सबसे ज्यादा भागीदारी अगर हो रही है तो बिहार के छात्र और छात्राओं का हो रहा हैं, इतनी भागीदारी दूसरे राज्य के नौजवान साथियों का नहीं हैं, यह दर्शाता हैं कि कितना सशक्त शिक्षा प्रणाली बिहार का हैं और खास करके मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज चाहे टेंथ का सिलेबस हो या इन्टर का सिलेबस हो, चाहे ग्रेजुएशन का सिलेबस हो, चाहे मास्टर डिग्री का सिलेबस हो, बिहार का जो सिलेबस है काफी स्टैण्डर्ड का रहा है और सिलेबस के स्टैण्डर्ड के कारण हमारे जो लोग, हमारे जो छात्र छात्रायें हैं, काफी गहन अध्ययन करके, गहन अध्ययन करने के पश्चात बहुत सारे कम्पिटीशन फेस करते हैं और अपने मेधा का पहचान देश ही नहीं वर्ल्ड स्तर पर स्थापित करते हैं । इसलिए माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से इसमें मेरा गुजारिश हैं कि चाहे कॉलेज का सिलेबस हो, चाहे आर्ट्स का सिलेबस हो, चाहे सायंस का सलेबस हो चाहे टेंथ का सिलेबस हो, ऐलेंवंथ, चाहे ट्वेलफ्थ का सिलेबस हो, उस पर बहुत सारा मंथन और चिन्तन करने की जरूरत हैं इसलिए कि हमारे कॉलेज के जो छात्र हैं, छात्रायें हैं जब तक सिलेबस पूरा नहीं करेंग तब तक कम्पिटीशन या एकेडमिक डिग्री, सही डिग्री प्राप्त नही कर सकते हैं और ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी का, कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं उसमें, हमलोगों को सुधार करने की जरूरत हैं, आखिर क्या कारण है कि आज एकेडमिक डिग्री के प्रति हमारे छात्र छात्राओं का जो रूझान हैं वह घटता जा रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है इसलिए कि जब तक एकेडमिक डिग्री नहीं होगा जब तक हमारे नौजवान छात्र, छात्रायें ....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, यह सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार के रिजिम में शिक्षा बहुत तेजी आगे बढ़ रही है और लोगों की रूचियां भी बढ़ रही है, कहां कमियां नजर आ गई आपको ?

श्री मो. नेमतुल्लाह : महोदय, उसमें बच्चियों को शिक्षा के प्रति ज्यादा रूचि हो रही है, साईकिल योजना के तहत लड़कियां अथाह, गांव-देहात की लड़कियां पढ़ने जा रही है ।

डॉ0 सुरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह रहा है कि आज कॉलेज में, कॉलेज में जो एकेडमिक डिग्री है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये, जो एट्रैक्शन हैं, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए ।

महागठबन्धन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा प्रणाली को सुद्ढ़ किये है, उसका हमलोग तहे दिल से इस सदन में उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको बहुत बधाई दे रहे हैं, जो महैाला बना हैं लेकिन हमलोगों का नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि जहां कहीं पर भी दो-तीन परसेंट अगर कमियां हैं तो उसको हमलोग अपने भाषण के क्रम में रखें ताकि विभाग का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो । आज कॉलेज में बिहार यूनिवर्सिटी का सवाल है, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, जितने भी यूनवर्सिटी हैं लेकिन वहां पर एकेडमिक डिग्री के प्रति कुछ ऐसा महौल स्थापित करना होगा ताकि हमारे जो छात्र छात्रायें हैं, एम.एससी., बी.एस.सी., पीएच.डी. में अपना रूझान दिखलावें । मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे वह कम्पीटीशन किसी स्तर का हो अगर एकेडमिक डिग्री हमलोग का स्ट्रौंग हैं, सिलेबस अगर फुॅलफुल होता है, स्टूडेंट को छात्र और छात्राओं को अगर सिलेबस से पूरी तैयारी होगी तो स्वभाविक रूप से कम्पिटीशन कम्पलिट करने में कठिनाई नहीं होगी ।

क्रमशः

टर्न-13ःज्योति

08-03-2017

क्रमशः

डा0 राम कुमार : तो स्वाभाविक है कि कंपीटीशन कंपीट करने में उनको कठिनाई होगी आज की स्थिति में भी आज के परिवेश में पूरे हिन्दुस्तान लेवेल पर जो ऐकेडेमिक डिग्री का जो सिलेबस हमारे बिहार में है जितने भी विश्वविद्यालय हैं वह दूसरे जगह नहीं दिखायी देता इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी का मैं इस तरफ विशेष रुप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इसपर और ध्यान देने की जरुरत है । दूसरा मेरे क्षेत्र का सवाल है। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस विधान सभा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं उस विधान सभा के ही माननीय विधायक जी इस सदन के प्रथम स्पीकर का सौभाग्य प्राप्त हुआ राम दयालु बाबू का और राम दयालु सिंह उच्च विद्यालय स्थापित है । हमारे कटरा प्रखण्ड के बरही पंचायत में और वह बागमती बांध के बीच में आ चुका है । वह कभी उत्तर बिहार का नंबर वन उच्च विद्यालय के रुप में स्थापित था । आज वह बांध के अंदर आ गया । पानी लग जाता है बागमती का बाढ़ के समय में, छात्रावास नंबर वन था । लेकिन आज बागमती बांध के अंदर आने से वह स्कूल आज विकास की गति पर थोड़ा नहीं है इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी का, मैं ध्यान आकृष्ट

करना चाहता हूँ कि राम दयालु सिंह उच्च विद्यालय को पुनर्वासित कर, एक मोडल उच्च विद्यालय के रुप में स्थापित करें और माननीय मंत्री जी जो आज शिक्षा प्रणाली की तरफ अपना कदम बढ़ाये हैं मजबूत करने का मैं इस स दन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी को मैं अपनी तरफ से कोटि कोटि और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूँ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं माननीय सदस्य श्री राजकिशोर सिंह, जनता दल यूनाईटेड को आमंत्रि करता हूँ समय है 8 मिनट ।

श्री राज किशोर सिंह : सभापति महोदय, आज सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है शिक्षा के संबंध में उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जबसे सरकार बनी है डा0 अम्बेदकर का सपना शिक्षित बनो, डा0 राम मनोहर लोहिया का सपना शिक्षित और स्त्री शिक्षा और अधिकार ज्योति बा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई के द्वारा दलितोंद्धार के लिए शिक्षा पर जोर, उन तमाम सपनों को पूरा करने का काम हमारी गठबंधन की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और लगातार प्रयत्नशील हैं । इसी का परिणाम है कि 2017-18 के बजट में सर्वाधिक 252 अरब 51 करोड़ 39 लाख रुपये अर्थात 17.93 परसेंट शिक्षा पर रखा गया । मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज 99 परसेंट बच्चे स्कूल में हैं । लेकिन इसके पहले किसके बच्चे स्कूल में नामांकन नहीं करवाते थे ? ओ0बी0सी0 के , ई0बी0सी0 के, एस0सी0 के मायनरिटी के बच्चे नहीं जाते थे । कुछेक बड़े लोगों का बच्चा भी नहीं पढ़ता होगा यह जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक शिक्षा पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के राज्य में हुआ है और आज अशोक चौधरी जी के राज्य में हो रहा है । विरोध करने के लिए विरोध करना है अभी बोल रहे थे हमारे सीनियर साथी सदन में नहीं है, चले गए, सरावगी जी घोटाला घोटाला घोटाला- दो साल पहले तक तो साथ ही थे मैं जहां से आता हूँ वहीं बिशुनदा कॉलेज है, बर्षों से चल रहा था जब साथ थे तो घोटाला नजर नहीं आ रहा था और आज जब अलग हैं तो घोटाला वाला पकड़ाया और जेल के अंदर है तब उनको घोटाला नजर आया । हाई स्कूल पॉच हजार संतानबे खोला जायेगा पंचायत स्तर पर । साथ ही नया महाविद्यालय पूर्णिया, मुंगेर, पाटलिपुत्र की स्थापना की जा रही है । महोदय, संजय सरावगी जी कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता, उनको जानकारी होनी चाहिए बहुत सीनियर लीडर हैं । बेरोजगारी भत्ता का तो कभी 7 निश्चय में कभी सवाल ही नहीं हुआ । प्रोत्साहन भत्ता 1 हजार प्रोत्साहन स्वयं सहायता उनके लिए उनको नौकरी खोजने के लिए और इतना सीनियर

लीडर होकर सदन में इसतरह की बात बोलेंगे तो दुर्भाग्य है । 2 अक्तूबर 2016 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू है और उसके बाद से अभी जो समय बीता है और आने वाले दिनों में सरकार गांव गांव तक प्रचार करने जा रही है कि सब लोग स्टूडेंट क्रेडिट ले इनको क्या मालूम गरीब का बच्चा कैसा होता है ? दो लाख का कोई संपति नहीं होता है, बच्चा पढ़ना चाहता है गांव और गरीबी नहीं देखे हैं-कुल संपति दो लाख की नहीं है, उसको कोई कर्ज नहीं देता हैं । पढ़ने वाला बच्चा है जब कॉलेज में आगे पढ़ाई करना चाहता है उसको पैसा नहीं मिलेगा । उसके दर्द को हमारी सरकार समझी और 4 लाख तक का क्रेडिट कार्ड देने का एलान किया । महोदय, साईकिल , पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के चलते गरीब और वंचित लोग स्कूल में जाने का काम कर रहे हैं । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम गौरवान्वित हैं बिहार के लोग कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में और महिलाओं को पढ़ाई के लिए उत्साहित करने के लिए, जो हमारी सरकार चुनाव के समय 35 परसेंट आरक्षण देने का वादा किया था सात निश्चय में, वह पूरा हो गया इसके लिए सरकार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ । महोदय, बिहार में सामाजिक न्याय, साम्प्रदायिक सद्भाव और समरस समाज की स्थापना का बिहार का समावेशी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है लेकिन वहीं जब केन्द्र की नीतियों की तरफ हमारी नजर जाती है तो मेरा मन मर्माहत हो जाता है । मैं एक आदमी कितना सोचता हूँ लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को क्यों कहना पड़ा कि लोकतंत्र में असहिष्णुता का स्थान नहीं है । माननीय सदस्यों, जरा हमारी बात सुनिये । नया सदस्य हूँ , अच्छी बात बोल रहा हूँ गलती हो तो क्षमा करियेगा । प्रणम मुखर्जी को आज क्यों कहना प ड़ा कि लोकतंत्र में असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं है यह केन्द्र सरकार क्या कर रही है इस तरफ भी इनको सोचना चाहिए । मैं अपनी बात कह रहा हूँ । राष्ट्रपति के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते । शिक्षा पर ही कह रहा हूँ । सुनिये इस देश में कहीं न कहीं बौद्धिक आतंकवाद फन फैलाये खड़ा है । मैं एक साल पहले इसी सदन में रोहित बेमुला का सवाल उठाया था और बिहार के सपूत कन्हैया के प्रताड़ना जेल में और फिल्म इंस्टीच्युट जो मुम्बई में है उसके दमन का सवाल उठाया था लेकिन आज महिला दिवस के अवसर पर संजय सरावगी जी, इस देश के आप भी नागरिक हैं । वरिष्ठ साथी हैं, गंभीरता से एक छोटा आदमी की बात सुनिये ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप आसन की तरफ देखिये ।

श्री राजकिशोर सिंह : सुनिये ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मेरे नाम से बोल रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : तो हम परमीशन देंगे तब न , आप परमीशन लिए कहॉ मैं दूँगा तो बोलियेगा यह कोई तुक नहीं न हुआ । आसन से आपको परमीशन लेना है । पहले कैसे खड़ा होंगे मैं जब परमीशन दूँगा तब न । माननीय सदस्य राज किशोर सिंह जी, समय बहुत बहुमूल्य है अपनी समस्याओं को रखें क्षेत्र से संबंधित ।

श्री राज किशोर सिंह : सभापति महोदय, आज महिला दिवस है । नारी को देवी का दर्जा दिया गया इस देश में लेकिन जब कल मैं स्तब्ध और व्यथित हो गया जब टी0वी0 देख रहा था । दिल्ली के रामजस कॉलेज में क्या हुआ । ए0वी0पी0 के लोग खुलेआम गुण्डागर्दी कर रहे थे । मैं फुटेज बार बार देखा और मैं देखने का प्रयास किया कि वह बच्ची गुरमेहर कौर क्या गलत बोल रही है ? जो भी बच्चियॉ बोल रही थी सिर्फ यही तो कह रही थी ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप समस्या रखिये क्षेत्र की , आपका समय दो मिनट है ।

श्री संजय सरावगी: दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ यह नजर नहीं आ रहा है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति, शांति कृपया बैठ जाईये । सरावगी जी बैठ जाईये। आपका समय दो मिनट ।

श्री राजकिशोर सिंह : सभापति महोदय, जब देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं और उनके राष्ट्रपति को उनके जन्म दिन की बधाई दी जाती है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप बिहार में आईये । ये आसन का --कृपया बैठ जाईये ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): मैं खुद नियंत्रण कर रहा हूं । आप बैठिये, समस्याओं पर आईये ।

टर्न-14/8.3.2017/बिपिन

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): समस्याओं पर आइये ।

श्री राज किशोर सिह: देश कहां जा रहा है सर, इसपर हमको सोचना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): बैठ जाइये, बैठ जाइए । जो अनावश्यक वार्त्ता कर रहे हैं कोई भी माननीय सदस्य हों, वह प्रोसिडिंग में नहीं आएगी । बैठ जाइये, आप बैठिये न । आप बोलिए ।

(व्यवधान)

आपको जानकारी नहीं है । बैठिये । आप बोलिये ।

श्री राज किशोर सिंह: हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कमार जी और शिक्षा मंत्री जी ठान लिए हैं बिहार के विकास के लिए और शिक्षा में विकास के लिए । मुख्यमंत्री जी के संकल्प को एक शेर के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता हूं –

'आसमां ने ठानी है जहां बिजलियां गिराने की,
मेरी भी जिद है वहां आशियां बनाने की ।'

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): अब कृपया समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य राज किशोर बाबू, आप अच्छे विधायक हैं । माननीय सदस्य बैठ जाइए । अब मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के माननीय सदस्य डॉ0 अशोक कुमार जी, आपका समय 15 मिनट ।

डा0 अशोक कुमार: सभापति महोदय, बिहार सरकार ने जो वर्ष 1917–18 के लिए शिक्षा विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं ।

महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विकासपुरूष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, महागठबंधन के हमारे नेतागण आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधीजी को, आदरणीय लालु प्रसाद जी को और साथ ही बिहार के माननीय वित्त मंत्री, उपमुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को जिन्होंने बिहार के बजट का कुल लगभग 18 परसेंट, 17.58 परसेंट, हिस्सा शिक्षा को आबंटित किया है । सभापति महोदय, जैसाकि हम जानते हैं, कोई भी समाज विकास तभी कर सकता है जब वह शिक्षित हो । हमारे महान बाबा साहब अम्बेकर जी का कहना था कि समाज शिक्षित बनो, संगठित होओ, संघर्ष करो तो कोई भी समाज वही विकास कर सकता है जो शिक्षित होगा और हमारे बिहार की महागठबंधन सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है और यही कारण है कि विकसित बनाने के लिए जो मूलभूत कार्य होता है शिक्षा, उसपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि पिछले एक वर्षों से अधिक समय में शिक्षा में बिहार क क्षेत्र में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी हाल में जो इंटरमीडियेट और मैट्रिक की परीक्षा जो अभी चल रही है वह बिल्कुल कदाचार मुक्त हुई है, इसके लिए मैं सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहता हूं । महोदय, हमारे प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी और यही कारण है कि हमारे पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार आदरणीय डा0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार में पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे बिहार की सरकार ने चार से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों को विद्यालय भेजने को प्राथमिकता दिया और उसमें भरपूर सफलता हासिल की । और यह कारण है कि आज ग्रामीण जो चार से चौदह वर्ष के बच्चे हैं, 99 प्रतिशत् बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं । इससे बड़ी उपलव्धि शायद पहले कभी साची भी नहीं जा सकती थी । महोदय, मैं इस संदर्भ में महादलित टोला सेवकों

के योगदान को याद दिलाना चाहता हूं जो लगभग 30हजार के करीब हैं पूरे राज्य में कार्यरत हैं विभिन्न विद्यालयों में और इनका मूल जो उद्देश्य है, वह महादलित बच्चों को विद्यालय ले जाने का, उनको कुछ देर पढ़ाने का और उन्हें मध्याह्न भोजन में सहयोग करने का है और वह इस कार्य को बहुत सफलता से कर रहे हैं और जिसका परिणाम हमलोगों ने देखा है उपस्थिति को, ऐसे में मेरा येह मांग और सुझाव होगा कि महादलित टोला सेवकों को उसी सविद्यालय मे सांमजन के लिए सरकार को विचार करना चाहिए ।

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत् हमारी महागठबंधयन की सरकार ने काफी प्रयास किया जिसके अंतर्गत हमें योजनाओं का जो लाभ जो केन्द्र सराकार को योगदान देना था उन्होंने नहीं दिया है और उसके बावजूद, इससे यह समझा जा सकता है कि केन्द्र सरकार बिहार की शिक्षा के लिए कितना संवेदनशील है और इस असहयोग के बावजूद जो सर्व शिक्षा अभियान में हमारे राज्य में काम हुआ है वह निश्चित रूप से सराहना के काबिल है । हमारे राज्य में अभी 19,604 प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालयों को नये भवनों और कक्षों का भी निर्माण कराया गया है । यह जरूर है आज भी प्राथमिक विद्यालयों में आज भी आधारभूत संरचनाओं की थोड़ी कमी है जिसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । खास कर विद्यालय के जो भवन हैं उनको और जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं तो अधिकांश विद्यालयों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं जिससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चों का जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आती है । इसलिए उसमें एक आवश्यकता है बेंच-डेस्क होनी चाहिए और उसको एक कंपलसरी कर देना चाहिए कि बच्चे बेंच पर पढ़ें सिसे उनका आत्म विश्वास बढ़े और साथ ही जो शिक्षकों की जो कमी है खासकर प्राथमिक विद्यालयों मुं शिक्षा वहीं से सप्रारभ्भ होती है तो उनकी कमी को एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान के तहत उसको पूरा करने का काम किया जाए । जहां जो खाली पड़े हैं जहां अध्यापक नहीं है उनको पूरा करने का काम किया जाए ।

महोदय, इंटर की शिक्षा और उत्क्रमित महाविद्यालयों में भी, जो विद्यालय हैं उसमें भी हो रही है और इंटर महाविद्यालय में भी होती है । आज ही हमने एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से एक बात पर ध्यान आकृष्ट किया था । महोदय, इंटर विद्यालय विद्यालय परिषद समाप्त हो गया है और उसको विद्यालय परीक्षा समिति में परिणत कर दिया गया है । आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार इंटरमीडियट कौंसिल में कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई जिसके कारण हमें थोड़ा शर्मिन्दगी उठानी पड़ी । महोदय, जब इंटर कौंसिल था, उस समय उस कौन्सिल में विधान सभा और विधान परिषद के माननीय सदस्य भी नामित सदस्य होते थे और उसकी बाद से जब से वह कौंसिल भंग हुई तो उन सदस्यों को वहां से उनको हटा दिया गया और कोई प्रतिनिधि नहीं है । और

इसका यही एक सबसे बड़ा उदाहरण ज्वलंत हो सकता है कि उसके बाद इस तरह के घोटाले करने की छूट मिल गई, किसयी यतरह का अंकुश नहीं रह गया । तो इन बातों को सरकार को सोचना चाहिए कि जन प्रतिनिधियों का रहनार एक अंकुश हाता है और सरकार के नजर उस पर सीधी रहेगी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और यही बात मैंने इंटर कॉलेज के लिए भी कही थी कि जब आप सरकारी अनुदान दे रहे हैं और सरकार का उसपर अधिकार हो जाता है तो सरकार का अंकुश भी होना चाहिए और आपने पूरी तरह से जो अंकुश हटा दिया तो अब वह एक तरह उसको उनको फिर से निजीकरण की ओर आपने धकेल दिया है और मनमानी करने की छूट दे दी गई है । ..क्रमशः

टर्नः 15/कृष्ण/08.03.2017

डा0अशोक कुमार (क्रमशः) और मनमानी करने की छूट दे दी है । इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए और मैं समझता हूं कि सदन के जनप्रतिनिधि इससे सहमत होंगे । उसमें भागीदारी होने से कोई जनप्रतिनिधि घोटाले में फंसता नहीं है बल्कि उस संस्था को घोटाले से बचाने का काम करता है । इसीलिये सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए।

महोदय, उच्च शिक्षा के लिये सरकार ने जो काम किये हैं, वह निश्चित रूप से पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है । जैसाकि यह जो धरती है, नालन्दा विश्वविद्यालय और बिक्रमशीला विश्वविद्यालय जो विश्व की धरोहर थी, उस धरती का यह प्रताप है कि यहां के युवाओं में इतनी प्रतिभा है, यहां के जो नौजवान और जो छात्र हैं, आज आप देखेंगे तो अधिकांश जगहों पर, चाहे वह प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे तकनीकी शिक्षा में हो, डाक्टर हो, इन्जीनियर हो, चाहे और तकनीकी शिक्षा हो, सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी नाम किया है । तो यह इस धरती का संस्कार है । इस बिहार की धरती में यह गुण है । लेकिन उच्च शिक्षा के अभाव में, तकनीकी शिक्षा के अभाव में हमारे छात्र बिहार से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे । दिल्ली, हैदराबाद और कर्नाटक में शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे । बिहार सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने इस बात को ध्यान से देखा । अब बिहार के छात्रों को मेडिकल और इन्जीनियरिंग पढ़ने के लिये मैं नहीं समझता हूं कि अब उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता है । क्योंकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज जिले के स्तर पर खोलने का काम किया जा रहा है । अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेनिक यहां तक कि महिला पॉलिटेनिक और नर्सिंग संस्थान खोलने का काम किया जा रहा है और इस तरह से शिक्षा में उतरोत्तर विकास करने का

हमारी सरकार ने जो योजना बनायी है, मैं समझता हूं कि इसमें हमें भारी सफलता मिल रही है और आनेवाले दिनों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा ।

महोदय, आज जो हमारे तकनीकी संस्थान हैं और जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उसमें शिक्षकों की कमी की बात काफी सुनने में आती है । मैं समझता हूं कि उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिये यह आवश्ययक है कि शिक्षकों की जो कमी है, उसको पूरा करने काम किया जाय । शिक्षकों की कमी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा के सभी माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक में अभी है । जैसाकि इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का काम प्रथम चरण में अभी हो गया है, द्वितीय चरण का होनेवाला है । तो एक समय सीमा के अंतर्गत उसको पूरा करने का काम करेंगे । यह मेरा सुझाव है ।

महोदय, हमारी सरकार बिहार में शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिये कृत-संकल्प है और खास कर के हमारे माननीय मंत्री जी इसमें दिनों-दिन सफलता प्राप्त कर रहे हैं । मैं इसके लिए इनको बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, अभी बात उठी थी सर्व शिक्षा की । सर्व शिक्षा अभियान में जो हमारे आधारभूत संरचना का काम के संबंध में अभी माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी जो बोल रहे थे कि भवन के काम अधूरे हैं, भवन बन गये, अभी टेक-ओवर नहीं हुये हैं, अगर सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार जो उनका हिस्सा है, अगर वह इसका सहयोग कर दें तो मैं समझता हूं कि जो बाधायें है, आधाारभूत संरचना की, उसमें कठिनाई नहीं आयेगी । वह पूरा होगा । मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमने कुछ बातें रखी है, उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और साथ ही, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को और सबसे ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और सभापति महोदय, आपको भी कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : आप पहले सदस्य हैं, आप डेढ़ मिनट पहले ही बैठ गये । आपको साधुवाद देता हूं ।

अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, जिनसे मैं आशा करूंगा कि इनकी जुबान से शहद टपके । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी, आप का 10 मिनट है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ने शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आप ने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आप का आभारी हूं । साथ ही, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो बात मैं यहां कहूंगा

और सरकार को जो मैं आईना दिखाऊंगा, सत्ता पक्ष के माननरीय सदस्यों को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे ।

सभापति महोदय, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इनका चेहरा चमकता रहता है, देख कर मुझे बड़ी खुशी होती है ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन) : आपको जलन है क्या ?

श्री मिथिलेश तिवारी : नहीं, नहीं । मैं बहुत खुश हूं । सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के तरफ से ही शुरू कर के अपनी बात रखूंगा ।

मंत्री के चेहरे पर लाली है,
शिक्षा की बदहाली है ।
बिहार का भविष्य अंधकारमय हो गया,
और पूरा देश कांग्रेसमुक्त और मोदीमय हो गया ।
कहा था बिहार में बहार है,
लेकिन मुख्यमंत्री लाचार हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, इनको कहिये जरा शांत रहें ।

केन्द्रीय विद्यालय के लिये जमीन की दरकार है,
लेकिन वादा खिलाफी कर रही बिहार की सरकार है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक छोटी-सी घटना के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी 10-15 दिन पहले का मामला है ।

(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय पर आईये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य यह सदन कहानियों के लिये नहीं है, समस्याओं के निदान के लिये है ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, इनलोगों को शांत रहने के लिये कहिये । मेरा समय जाया कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आप बैठ जाईये । क्या चाहते हैं ? एक आदमी बोलिये ।

श्री नेमातुल्लाह : उदाहरण जो दिया गया है, उसे कार्यवाही से विलोपित किया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : उदाहरण प्रोसीडिंग्स से हटा दिया जाय ।

(व्यवधान)

अब तो आप शिक्षा पर आ जाईये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं उसी पर आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांत रहें । माननीय सदस्य,आप समस्या बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवाारी : सभापति महोदय, शिक्षा के विस्तार के लिये माहौल चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जाईये । कृपया एक साथ मत बोलिये । सारी बातों को प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया गया है, अब आप बैठिये तो कम से कम ।

टर्न–16/राजेश/8.3.17

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन): जिसकी रही भावना जैसी, अब वही इनकी हालत है । आपलोग शांत रहिये । अब आप आइये शिक्षा पर ।

श्री मिथिलेश तिवारी: शिक्षा के विस्तार के लिए माहौल चाहिए सभापति महोदय, और जिस बिहार में .....(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): इनकी असंवैधानिक बात को प्रोसिडिंग से हटा दिया गया । अब आपलोग बैठिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: सभापति महोदय, जिस बिहार में पत्रकार राजीव रंजन की हत्या हो रही हो, जिस बिहार में बृजनाथी सिंह की हत्या हो रही हो, जिस बिहार में विश्वेश्वर ओझा की हत्या हो रही हो, जिस बिहार में आदित्य सचदेवा को गोली मारा गया हो, जिस राज्य में मिड डे मिल खा करके बच्चे मर रहे हों.....(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन)खड़े होकर: आपलोग बैठ जाइये । माननीय सदस्य सरावगी जी आप भी बैठ जाइये । माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा आज विषय है, गृह विभाग नहीं है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, मैं शिक्षा के लिए माहौल की चर्चा कर रहा हूँ । सभापति महोदय, मिड डे मिल खा करके बच्चे इसी बिहार में मरते हैं, इसी बिहार में पतंग उत्सव के

लिए लोग जाते हैं और उसके बाद मरते हैं, इसी बिहार में पाठ्य पुस्तक घोटाला होता है, इसी बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति अनुदान लेने वाले शिक्षक पिछले.....(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः सभापति महोदय, ये किस विभाग पर बोल रहे हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बैठ जाइये । सदन को गंभीरता बनाइये ।

श्री मिथिलेश तिवारीः मिड डे मिल शिक्षा विभाग में नहीं है क्या ? सभापति महोदय, ये पाकिस्तान चले जाते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं होती है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): फिर आप पाकिस्तान चले गये, आपने पाकिस्तान का नाम लिया । बिहार का मामला है, तो बिहार के शिक्षा पर बोलिये ।

श्री मिथिलेश तिवारीः सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालयों में शौचालय नहीं, विद्यालयों में खेल मैदान नहीं, शिक्षक नहीं, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं, स्कूल में बिजली नहीं, तब भी कहते हैं कि बिहार में बहार है और सभापति महोदय, टॉपर घोटाला करके हमने राजेन्द्र बाबू की आत्मा को दुखी किया है, यह वहीं बिहार है, जहॉ कभी राजेन्द्र बाबू के लिए किसी ने कहा था कि एक्जामिनी इज बेटर देन एक्जामिनर, उस बिहार को हमने टॉपर घोटाला के माध्यम से .....(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य आप बताइये कि किसने कहा था ?

श्री मिथिलेश तिवारीः जिसने भी कहा होगा, आप बाद में जांच करा लीजियेगा । सभापति महोदय, पहले मेरी बात तो पूरा सुन लीजिये । मेरा समय बर्बाद हो रहा है । सभापति महोदय, नियोजित शिक्षक समान वेतन के लिए आज हड़ताल पर हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, दूसरी तरफ बी0एस0एस0सी0 घोटाला हो रहा है, सबौर कृषि विश्वविद्यालय में घोटाला हो गया, आई0ए0एस0 लोग आंदोलन पर है, कॉग्रेसी नेता के द्वारा दलित मंत्री की बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, टी0ई0टी0 शिक्षक धरने पर हैं और हमारा छात्रवृति, स्कॉलरशीप घोटाला हो गया, दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों .....(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्रीः सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । ये जो बोल रहे हैं घोटाला पर तो इसमें व्यापम घोटाले पर भी इन्हें बोलना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी बोलिये ।

श्री मिथिलेश तिवारीः सभापति महोदय, राज्य में 16 हजार से ज्यादा प्रेरक और समन्वयक आज हड़ताल पर हैं और वे धरने पर बैठे हुए हैं । महोदय, मध्याह्न भोजन योजना का चावल बेचा जाता है दो अक्तूबर यानि गॉधी जयंती के अवसर पर, मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चावल बेचते हुए 78 बोरा बरामद किया गया और आज तक अभियुक्त पर कार्रवाई नही हुई.....(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): चावल क्या आज का विषयवस्तु है ?

श्री मिथिलेश तिवारीः मिड डे मिल में चावल आता है, मिड डे मिल शिक्षा विभाग में ही है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन): माननीय सदस्यगण आपलोग बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: सभापति महोदय, 2003 से लेकर 2014 तक जो सवा तीन लाख शिक्षकों का नियोजन हुआ, नियोजन 2003 में हुआ, उसकी जांच अब हो रही है, तो जो भी 1700 शिक्षकों ने इस्तिफा दिया है, इसमें जो दोषी शिक्षक पाये गये हैं, उन शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई कर रही है लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उन शिक्षकों की बहाली क्यों हुई, उन शिक्षकों की बहाली के समय आपने नियमावली क्यों नहीं बनायी, बिहार के छात्रों को आपने फर्जी शिक्षकों के हवाले कर दिया, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी । महोदय सवा लाख शिक्षकों के पद अभी रिक्त हैं, मुझे जानकारी है महोदय, केवल शिक्षकों पर एफ0आई0आर0 करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार से, कि जिसतरह से फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा हो रहा है, उसी तरह तत्कालीन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग पर भी होना चाहिए एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी होना चाहिए। सभापति महोदय, बिहार में जब भी पढ़ाई-लिखाई की बात होती थी, ज्योतिष विद्या की बात होती थी, संस्कृत शिक्षा तो लगता है कि विलुप्त ही हो गया, सरकार के प्राथमिकता में लगता है कि संस्कृत शिक्षा नहीं है । महोदय मैं एक बात और कहकर अपनी बात को खत्म करुंगा, चूंकि मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुनने का साहस नही है आपलोगों में, इसलिए महोदय जो बिहार में शिक्षा है महोदय, जो आज यहाँ कई लोग बोल रहे थे केन्द्रीय विद्यालय और माननीय उपेन्द्र कुशवाहा जी की बात कर रहे थे, तो महोदय हमलोग कई बार जा करके माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं और केन्द्र की सरकार और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है कि बिहार की सरकार हमें भूमि नहीं दे रही है, नहीं तो अब तक हम प्रखंड स्तर तक केन्द्रीय विद्यालय को खोल दिये होते ।

सभापति (श्री मो0इलियास हुसैन):- अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी:- सभापति महोदय, लास्ट में मैं एक बात कहूंगा मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के लिए कि:

''तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां कैसे लुटा,
मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।''

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- माननीय सदस्य श्री फराज फातमी जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी, जो दिवंगत हो गये हैं प्रधान सचिव, इनकी चर्चा कर दी इन्होंने महोदय । हमलोग तो ज्ञानवान इनको बूझते है महोदय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): ये तो बिल्ली की भी चर्चा करते हैं, ये कर दिया तो गनीमत है। माननीय सदस्य श्री फराज फातमी जी ।

श्री फराज फातमी: सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग के मांग के समर्थन में बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यह बात शुरुआत करता हूँ कि जो व्यक्ति, चूंकि आज शिक्षा पर बात होनी थी लेकिन विधि व्यवस्था पर बात शुरु हो गयी और यह दर्शाता है कि जो शिक्षित लोग हैं, वे ही शिक्षा पर बोले तो समझ में आता है । सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस महागठबंधन की सरकार को जिनका एक साल पूरा हो गया, अपने दिल की गहराई से उनको मुबारकवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी सरकार न तो बिहार के अंदर चली है और न आने वाले कल में चलेगी । मैं सबसे पहले श्री नीतीश कुमार जी को, अपने मुखिया श्री लालू प्रसाद यादव जी को और हमारे युवा सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुबारकवाद देता हूँ और इस सरकार को मुबारकवाद देने का काम करता हूँ । आज जिसतरह से हमारे शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी जी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है, इसलिए हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं.....(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन):- आप यूं आसन की तरफ हाथ करके नहीं कहिये, हाथ नीचे करके कहिये ।

श्री फराज फातमी:- सभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज बिहार सही माने में गौतम बुद्व की धरती मानी जाती है, महावीर की धरती मानी जाती है, जहॉ से चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन की महात्मा गॉधी जी ने शुरुआत की, वहॉ पर आज बिहार का भौगोलिक स्ट्रक्चर देखियेगा, उसमें आबादी ज्यादा है, जमीन कम है, आज कारखाने कम हैं, अगर बिहार बढ़ सकता है आगे, तो सही माने में आज एडुकेशन की बहुत ही जरुरत है। आज हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करना बहुत ही जरुरी है । सही माने में अगर आज बिहार आगे बढ़ेगा, तो शिक्षा का उपयोग होना बहुत जरुरी है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति-शांति ।

टर्न-17/सत्येन्द्र/8-3-17

श्री फराज फातमी(क्रमशः) मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो बजट में लाया है, 400 करोड़ रू0 का बजट लाया है । आज बजट बढ़ा है शिक्षा के अन्दर मैं इसके लिए अपने मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को बधाई देता हूँ । महोदय, आज 60 प्रतिशत आबादी बिहार के अन्दर युवाओं की है आज अगर उनको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमारी सरकार ने

सबसे पहला जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम को लॉंच किया है, चूंकि आज बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए गरीब बच्चे हैं आज 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है बिहार के अन्दर, उन परिवारों के पास पैसे नहीं है देने के लिए उनको आगे पढ़ने के लिए सही मायने में उनको पैसे की जरूरत है । सबसे बड़ा योगदान अगर सरकार ने किया है तो वह बच्चों को मदद किया है उनके लिए चार लाख रू0 का स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम लॉंच किया है । क्योंकि उसी के जरिये आज हायर एडुकेशन पढ़ना है अगर किसी को बी0एड0 करना है इंजीनियरिंग करना है मेडिकल करना है तो उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है और आज सरकार का उस पर सबसे पहले योगदान हुआ है, मैं इसके लिए अशोक चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूॅ। दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है वह वाई-फाई है, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के अन्दर वाई-फाई सिस्टम लॉंच किया है । आज यंग बच्चे इंटरनेट जिनको जरूरत है आज कॉलेज में जाईए, यूनिवर्सिटी के अन्दर जाईए तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन की जो परेशानी आती है उनके लिए इंटरनेट का इंतजाम किया है, वाई-फाई का इंतजाम किया है जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । तीसरी सबसे बड़ी अगर आज मानी जाय तो जो नीतीश कुमार जी ने सही मायने में आज सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का है और हमारे लालू प्रसाद यादव जी का है । आज बिहार आगे बढ़ रहा है क्योंकि जिस समय हमारे मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे उसी वक्त से बिहार आगे बढ़ा और उस बिहार को आगे बढ़ाने में हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है । मैं आपको बतलाना चाहता हूॅ, आज हर पंचायत के अन्दर हाई स्कूल खुल रहा है । आज बच्चों को बाहर जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है सरकारी स्कूल हर पंचायत के अन्दर खुल रहा है, उसके भवन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें बच्चे जा रहे हैं । आपको बता दूं, 15 साल पहले बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे उनको पढ़ने के लिए परेशानी होती है लेकिन आज स्कूल बन गया है आज आसानी से बच्चे जा सकते हैं आज साईकिल की सुविधा सरकार ने किया है और फ्री साईकिल बच्चों के बीच बांटी जा रही है, फ्री किताब बांटी जा रही है, फ्री यूनिफार्म बांटी जा रही है । आज बच्चों को तकलीफ नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है । आज सरकार सारा इंतजाम कर रही है इसके लिए मैं सरकार को तहेदिल से मुवारकबाद देता हूॅ, बधाई देने का काम करता हूॅ आज आपको जानकर खुशी होगी कि एक प्रतिशत 6-18 साल के बच्चे जो थे 1 प्रतिशत से कम बच्चे अब स्कूल के बाहर हैं, 99 प्रतिशत बच्चे आज स्कूल के अन्दर जा रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूॅ कि 2 अक्टूबर को जो मानव श्रृखंला हुई, आज पूर्ण शराबबंदी से पूरे बिहार के अन्दर जो अमन चैन आया है वह काबिलेतारीफ है । आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है और घर के बाहर जब निकलती है तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको जानकर खुशी

होगी कि 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ आबादी के लोगों ने मिलकर सबसे ज्यादा योगदान मानव श्रृंखला का जो रेकार्ड कायम किया बिहार की सरकार ने 2 करोड़ लोग एक साथ लाईन में खड़े होकर पूर्ण शराबबंदी का सहयोग करने का काम किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देने का काम करता हूॅ। साथ ही साथ आज 2016-17 का जो बजट में प्रावधान किया गया है उसमें 16 हजार 331 प्राईमरी स्कूल का प्रावधान है जिसमें 12473 तकरीबन 76 प्रतिशत बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है आज 535 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 535 कस्तुरबा आवासीय विद्यालय पूर्ण रूप से शुरू हो गयी है और उसमें 48719 बालिकाओं का नामांकन पूरा हो चुका है । 2158 पंचायतों में मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर के हाई स्कूल में कंभर्ट कर दिया गया है । आज उर्दू और बंगला टीचर्स की नियुक्ति हो रही है साथ ही साथ 596 मिडिल स्कूल में साईंस लैब का इंतजाम किया गया है, 1019 मिडिल स्कूल के अन्दर आर्ट और क्राफ्ट लैब का इंतजाम किया गया है आज जो सबसे पिछड़ी हुई बैकवर्ड लड़कियां थी उसमें 292 लड़कियों के लिए 100 होस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूॅ । महोदय, 368 ब्लौक में मार्डन स्कूल की बिल्डिंग में से तकरीबन 216 मॉडल स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और इसमें सी0बी0एस0सी0 के बुनियाद पर वहां पर पढ़ाई करायी जायेगी । ये भी इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथ ही साथ जो बच्चे बड़ी तकलीफ होती थी लोगों को सबसे बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता था वह थी अंग्रजी की पढ़ाई चूंकि अंग्रेजी बोलने में तकलीफ होती थी और कम्प्यूटर की जो ट्रनिंग थी उसमें कमी थी उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और उसके लिए कम्प्यूटर की ट्रेनिंग इंगलीश स्पीकिंग की ट्रेनिंग हो इसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किया हैं इसके लिए मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूॅ साथ ही साथ बच्चे को नौकरी ढूढ़ने में बच्चों को परेशानी होती थी सही मायने में जब बच्चे बाहर जाते थे काम करने के लिए तो उसमें उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था उसके लिए सरकार ने 1000 रू0 महीना भत्ता दो साल तक के लिए इंतजाम किया इसके लिए मैं सरकार को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूॅ । कुछ समस्याएं मेरे इलाके की है माननीय मंत्री जी से इस बात को रखने की कोशिश की थी कि बनवारी हाई स्कूल मेरे केवटी के अन्दर है वहां पर एक छत गिर गया था कुछ दिन पहले मैंने इसको उठाया था इसलिए छत की तुरंत मरम्मति करवा दिया जाय साथ ही साथ बालिका हाई स्कूल है बनवारी के अन्तर्गत उसके अन्दर उसकी चाहरदिवारी का इंतजाम करा दिया जाय। समस्तीपुर में 50 हजार से ज्यादा की आबादी है लेकिन वहां पर मात्र दो पी0जी0 कॉलेज है वहां पर और पी0जी0 कॉलेजेज का इंतजाम कराया जाय क्वेटी खिरमा हाई स्कूल है, वहां चाहरदिवारी की समस्या है उसको पूरा कराया जाय और मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि सही मायने में आज बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें

बिहार शिक्षित हो रहा है, बिहार विकसित हो रहा है । मैं विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि हमें इसमें समर्थन करें और महागठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करें । आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, आज बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी ने जो शिक्षा विभाग पर सदन में मांग पेश किया है , मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है । आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यह बहुत ही महान दिन है । आज के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जनसंख्या की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाय, हमारी लड़कियां कैसे आगे बढ़े, हमारे गृहणि क्षेत्र की लड़कियां कैसे शिक्षित हो इसके लिए भरूपर व्यवस्था की गयी है । महोदय, शिक्षा एक ऐसा बहुमूल्य धन है जो खरीदा नहीं जा सकता है यह एक ऐसा शस्त्र है जिसके सहारे हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जिसके सहारे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं जिसके सहारे हम स्वाबलंबी हो सकते हैं जो व्यक्ति शिक्षित है हुनरमंद है वह वेकार कभी नहीं रह सकता है और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो चाहकर भी उसे कोई दूसरा बर्वाद नहीं कर सकता है, कोई लूट नहीं सकता है । महोदय, शिक्षा का अपहरण नहीं होता है, शिक्षा जीवनपर्यन्त मनुष्य के साथ रहता है और हर समय साये के साथ एक प्रिय मित्र की तरह जीवन भर जीवनपर्यन्त शिक्षा उनके साथ रहता है और हर चुनौतियों से मुकाबला करने का सहयोग करता है और इसी मर्म को हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने समझा है और उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना चलायी है । ये केवल आने जाने का साधन नहीं है महोदय, मुख्यमंत्री साईकिल योजना हमने देखा है कि जब कोई लड़कियां 10 साल पहले पटना की सड़कों पर साईकिल चलाती थी, कारें चलाती थीं तो लोग फब्तियां कसते थे मुड़कर देखते थे कि क्या हो रहा है अजीव सा लगता था लेकिन आज परिवर्त्तन है महोदय आज गांव की पगडंडियों पर लड़कियां साईकिल चला रही है । क्या यह परिवर्त्तन नहीं है, क्या यह विकास नहीं है।(क्रमश:)

टर्न-18/मधुप/08.3.2017

...क्रमश:...

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह सामाजिक क्रांति है एक पिन-ड्रॉप साइलेंस क्रांति है, आने-जाने का साधन तो हुआ ही लेकिन लड़कियों में एक कंफीडेंस जागा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनमें जो काबिलियत है, उसको उभारने का काम हमारे

माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भाषण नहीं देते हैं बल्कि वे हर पल, हर क्षण सोचते हैं कि और क्या होना चाहिये बिहार की तरक्की के लिये, बिहार के विकास के लिये, बिहार की शिक्षा के लिये, वह उसका खाका तैयार करते हैं और केवल शिलान्यास ही नहीं करते हैं उस चीज को धरती पर उतारने का काम करते हैं, उस कार्य को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं । आप देखिये, आज केवल एक प्रतिशत बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं । हम चाहते हैं सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ना । महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारा क्षेत्र बहुत ग्रामीण इलाका है, हमने देखा है कि गॉव में स्कूल नहीं होते थे, आज हरेक गॉव में गुलाबी रंग का दो मंजिला भवन दिखता है जहॉ पर शिक्षक हैं, जहॉ पढ़ाई हो रही है ।

सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की रचनात्मक सोच और सृजनात्मक विचार ने आमूल-चूल परिवर्त्तन लाया है । केवल प्राथमिक विद्यालय ही नहीं, केवल माध्यमिक विद्यालय ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ही एक अद्‌भुत परिवर्त्तन किया है । पहले यहॉ के बच्चे पढ़ने के लिये बाहर जाते थे, बिहार में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वैसा नहीं था लेकिन आज हमारे बच्चे अपने राज्य में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सबसे गौरव और सम्मान की बात है कि आज दूसरे प्रदेशों के बच्चे, दूसरे देशों के बच्चे भी हमारे यहॉ पढ़ने के लिये आ रहे हैं । हमारे क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक खण्डहरनुमा हो गया था और माननीय मुख्यमंत्री की सोच के कारण ही आज नालंदा यूनिवर्सिटी पुनः जागृत हुआ है, पुनः बनाया गया है और देश-विदेश के बच्चे वहॉ पढ़ने के लिये आ रहे हैं । आज महिलाओं को विकास करने के लिये नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है हर नौकरियों में, बिहार सरकार ने महिलाओं को नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सदन के अन्य सदस्यों से मेरा आग्रह है कि माननीय विधायक जितेन्द्र कुमार जी के वक्तव्य और भाषण से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बालिका पोशाक योजना निकाली थी । गरीब के बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं होते थे, उनके पास जूते नहीं होते थे, उनके पास बैग नहीं होते थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को समझा और बालिका पोशाक योजना की शुरूआत की, आज सम्मान के साथ हमारी बच्चियॉ स्कूल जा रही हैं ।

महोदय, हम कहना चाहेंगे, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र में महोदय, आप गये थे, नालंदा जिला में बिंद प्रखंड है, वहॉ एकमात्र स्कूल है बिंद उच्च विद्यालय, उसका भवन जर्जर है । हम चाहेंगे कि उसपर कृपा दृष्टि बनाइये और हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं, आपने आश्वासन भी दिया

था पिछले वित्तीय वर्ष में, मैं चाहूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में उस भवन का निर्माण हो जाय । हमारे नालंदा जिला में हमारे विधान सभा क्षेत्र में सरमेरा प्रखंड है और उसमें आज तक बी0आर0सी0 भवन नहीं बन पाया है । मैं 2005 से विधायक हूँ और यह 2003-04 की योजना है, अर्द्धनिर्मित है, कई तरह की समस्याएँ आई, महोदय । मैं चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि जो बी0आर0सी0 भवन है, ब्लॉक रिसोर्सेज सेन्टर है, उसका निर्माण हो । हमारे यहाँ कई विद्यालय हैं जो अधूरे पड़े हुये हैं, ए0सी0/डी0सी0 बिल के कारण राशि लौट गई । अस्थावाँ प्रखंड में मोहम्मदपुर उच्च विद्यालय है, हमारे बीच मासी उच्च विद्यालय है, राशि लौट गई । +2 के भवन अधूरे पड़े हुये हैं, हम चाहेंगे कि उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो ताकि छात्र लाभ उठा सकें । हमारे क्षेत्र में कई विद्यालयों को +2 किया गया है लेकिन प्रयोगशाला नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, उपस्कर सामग्री नहीं है, हम चाहेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री उसपर बारीकी से ध्यान देंगे।

महोदय, हमारे बीच कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो हम उठा सकते हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति क्या कर रहा है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, महोदय । माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : समय आपका समाप्त हो गया ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, आज सात निश्चय की बात हो रही है । सात निश्चय के तहत सबसे ज्यादा जिसपर फोकस किया गया है, वह शिक्षा है । आप देख लीजिये, आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिला को अधिकार, अवसर बढ़े आगे बढ़ें । कई तरह की योजनाएँ लागू की गई हैं । आप देखिये - स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड । हमारे गरीब विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते थे, हाई एजुकेशन नहीं कर पाते थे । माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच के कारण आज स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 12वीं पास जो छात्र हैं, किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, उनको चार लाख का ऋण दिया जायेगा 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार पाने के लिये दो वर्ष तक के लिये एक हजार रूपये का भत्ता दिया जायेगा यानी हमारी सरकार सकारात्मक है, शिक्षा को आगे ले जाना चाहती है और शिक्षा के सहारे ही हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं । बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभावान हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़कियाँ हैं और उसके सहारे ही हम पूरी दुनिया पर परचम फहरा सकते हैं । आज बिहारी कहलाना आज शान की बात है गौरव की बात है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, अब आप समाप्त करें । बैठ जाइये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुये अपनी बात समाप्त करते हैं । जय हिन्द । जय बिहार ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या श्रीमती एज्या यादव जी से आग्रह करता हूँ, आपके लिये समय 15 मिनट ।

श्रीमती एज्या यादव : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपकी आभारी हूँ । मैं अपने माननीय वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी जी और अपने माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहती हूँ । मैं शिक्षा बजट 2017-18 के पक्ष में अपना विचार रखना चाहती हूँ ।

बिहार के 2017-18 के लिए जो बजटीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार, शिक्षा के विकास के लिए संकल्पित है ।

मैंने जब बजट को पढ़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार के शिक्षा बजट का Mission "Education for all and Education at all levels है । Basic Education से Higher Education तक पूरा ध्यान दिया गया है । साथ ही साथ पूरे शिक्षा बजट में भारत के दो महान पुरूष महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के शिक्षा नीति और समाज के प्रति सोच पर आधारित है ।

हमारी सरकार की बालिकाओं और किशोरियों को प्रोत्साहित करने के लिए Cycle और पोशाक की योजना बहुत सराहनीय है । जब लड़कियॉं School की पोशाक पहने Cycle पर सवार शान से और रफ्तार में गॉंव को चिरती हुई School की ओर बढ़ती हैं, तो लगता है कि Women empowerment अब दूर नहीं है । मैं बताना चाहूँगी Cycle को महज एक School जाने का माध्यम और पोशाक को महज एक वस्त्र न समझा जाय । Cycle and uniform have a much larger and wider connotation. Cycle is symbolic of independence, of empowerment of emancipation whereas uniform symbolic identity. एक दबी-कुचली समाज की लड़की Uniform पहन कर उतनी ही गौरवान्वित महसूस करती हैं जितना एक Doctor apron पहन कर एक Judge, एक Police अधिकारी, एक Defence Officer uniform पहनकर ।

मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि लड़कियॉं Uniform पहनकर Cycle पर सवार हो गईं तो उनके कदम हमेशा ही आगे बढ़ेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, साईकिल पर जोड़ दे रही हैं अच्छी बात है। मालूम है साईकिल का अविष्कार किसने किया था ? जब चलते-चलते हुआ विकल तो मैकमिलन ने बनाई साईकिल ।

श्रीमती एज्या यादव : ऐसी लड़कियॉं नौकरी करें या न करें, वह अपने Family के लिए और अपने would be family के लिए Asset हो जायेंगी । वह अपने पूरे परिवार

में अनुशासन और शिक्षा लायेंगी । Jawaharlal Nehru का सही मानना था "If you educate a girl child you educate the whole family."

Mhatma Gandhi का सपना था कि हमारे भारत में एक Classless Society की स्थापना हो । एक ऐसा समाज जिसमें किसी तरह की विषमता न हो, जिसमें बड़े लोग और छोटे लोग न हों । यह तभी हो सकता है, जब समाज में सब Educated हो । मैं धन्यवाद देती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को, जिनके Sincere Efforts से आज सिर्फ 1% बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित है ।

Classless Society की स्थापना के तहत हमारी सरकार सर्व शिक्षा अभियान को Sincerity के साथ Successful बनाने में लगी है । इस योजना के तहत हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं । हजारों की संख्या में मिडिल स्कूल का अप-ग्रेडेशन किया गया है । जिन पंचायतों में हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है, वहाँ हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे ।

..क्रमशः...

टर्न-19/आजाद/08.03.2017

..... क्रमशः .....

श्रीमती एज्या यादव : ऐसा करने से स्कूल के बच्चों के नामांकन में वृद्धि भी आयी है और आयेगी। बच्चे की संख्या को देखते हुये स्कूल में क्लासरूम्स बढ़ाने का अच्छा विचार है। मैं यहां पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी और बताना चाहूँगी कि Let us not boast of the numbers we have achieved in terms of infrastructure numbers of school built, toilets built, hand pumps built, given science Labs and art craft , but let us find out ways to make sure that these things are not only maintained but also contribute towards quality education . हमलोगों को याद रखना चाहिए कि सरकारी स्कूल में बिहार के मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, इसमें जो भी नई-नई व्यवस्था हो रही है, उसको मेनटेनेन्स ज्यादा जरूरी है।

एक कहावत है ''Give a man a fish and you feed him for a day, teach him how to fish and you feed him for a life time'' हमारी महागठबंधन की सरकार नई पीढ़ी को ऐसा शिक्षा देना चाहती है, जिससे कि उनके कौशल का विकास हो, उन्हें रोजगार का अवसर मिले । इसी दिशा में सरकार की सटीक योजनायें हैं, जैसे स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, Training in communication and soft skill and also knowledge of computer application. इन योजनाओं का फायदा लेकर हमारे वो बच्चे जो बारहवीं पास कर चुके हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिलेगा । हमारी सरकार ऑलराऊंड

एजुकेशन पर विश्वास रखती है । Qualified competent, capable teachers से student को शिक्षा मिले, इसपर विशेष ध्यान दी जा रही है । विद्वानों का मानना है ''Teachers should be the best minds in the country'' यह भी सही है कि Teachers make a lasting impact in the life of the students. Competent teachers न सिर्फ Quality Education देते हैं, बल्कि Teaching Learning Process को एक Interesting experience बना देते हैं। टीचर्स के एफेक्टीवनेस को इनहांस करने के लिए 33 शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और 250 प्रशिक्षण केन्द्र पर ICT की व्यवस्था की गई है ।

इन्टरनेशनल मार्केट में हमारी सरकार English Language and computer skill के importance को समझती है, समझती है कि ये दोनों ही नीड ऑफ दी आवर हैं । जवाहर लाल नेहरू जी का मानना था कि English in the window to the outside world, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी English Language के महत्व को समझते हुए सेकेन्डरी स्कूल के इंगलिश टीचर्स को Quality English training and skilling students in English Language की ट्रैनिंग करवा रहे हैं । ऐसे टीचर्स कमप्लीट टीचर्स, आईडियल टीचर्स कहलायेंगे, स्टुडेन्ट्स को शिक्षा के क्षेत्र के चैलेंजेज को फेस करने के लायक बनायेंगे । गवर्नमेंट कॉलेज को वाई-फाई करना, कम्प्यूटर पर स्टुडेन्ट्स का कमान्ड, इंगलिश भाषा पर स्टुडेन्ट्स का कमान्ड, हमारे स्टूडेन्ट्स को नेशनल ही नहीं, इन्टरनेशनल मार्केट के लिए भी कम्पीटेन्ट बनायेंगे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : मैडम, एम0एल0ए0 साहिबा, You might be honourable but Your Education Minister is expert especially in English.

श्रीमती एज्या यादव : यस सर । मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि Teaching is an ideal profession. मैं अपने टीचिंग एक्सपीरीयंस से यह भी कहना चाहूँगी कि Teaching is an art and it involves a lot of creativity. हम सब जानते हैं कि Teachers are the back bone of the society and also that teachers have the greatest responsbility towards the society and towards nation building. Teachers समाज के एक मजबूत स्तम्भ है ।

हमारे टीचर्स का उद्देश्य होता है कि हमारे स्टुडेन्ट्स जो रॉ मैटेरियल हैं, उनको इस तरह से शिक्षा देना है कि वे एक resource में डेवलप हो जायं । एक ऐसा human resource जिस पर हमारे देश का future टिका है ।

मैं माननीय मंत्री जी को जो Human Resource Minister हैं से आग्रह करना चाहूँगी कि टीचर यानी कि गुरू, जिनको Human Resouce का डेवलपर्स बनने दें,

उनको डेवलप करने के लिए ही रखा जाय । चाहे प्राईमरी स्कूल के टीचर्स हो या कॉलेज के हों, उन्हें नन् टीचिंग एक्टीवीटीज से, कलर्कियल वर्क, खिचड़ी, जनसंख्या में इनवॉल्व नहीं किया जाय । ऐसा करने से उनकी इफीसियेन्सी में, उनकी मोटिवेशन में कमी आयेगी । कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते समय यदि कोई दूसरा काम करे या सोचें तो बर्तन परफेक्ट नहीं बन पाते हैं ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि teacher-student ratio भी मेनटेन किया जाय । यह संभव ही नहीं कि एक टीचर एक बार में 70 बच्चें, 100 बच्चें को सही तरीके से हैंडिल कर सकें । सर्वे के अनुसार एक टीचर 30 बच्चे से ज्यादा को एक बार में सही तरीके से हैंडिल कर ही नहीं सकते ।

मैं कहना चाहूँगी कि टीचर एक गरिमामय पद है, उनके गरिमा को मेनटेन किया जाय, उन्हें द्रोणाचार्य बनने का मौका दिया जाय ।

मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि भावना के उदगार में यदि मैं कुछ ज्यादा बोल गई तो मुझे माफ करें । मैंने शिक्षकों के भावना का उदगार व्यक्त किया है । मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ और शिक्षा बजट का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : So many thanks. You closed your speech before five minutes more. अब मैं आग्रह करता हूँ, पुनः आता हूँ माननीय विधायक भाजपा के सदस्यों के तरफ, आग्रह के साथ जैसा कि आपने कहा था कि केरल में परसेन्टेज ऑफ एजुकेशन यह है, बहुत तकलीफ होती है, आप काफी क्वालिफायड आदमी हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति शिक्षा पर क्या है, कितना परसेन्टेज है, इसको भी ध्यान में रखिये । अब मैं माननीय सदस्य श्री बृज किशोर बिन्द जी से आग्रह करता हूँ, आपका समय 10 मिनट ।

श्री बृज किशोर बिंद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री संजय सरागवी द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव के समर्थन में कहने के लिए, बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । खुशी भी है और दुःख भी होता है । आज पूरे देश में .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, खुशी के साथ गम, सुख के साथ दुःख और यहां पर आप खुशी बोल देते हैं ।

श्री बृज किशोर बिंद : ठीक है सर । आज पूरे देश के अन्दर टेकनिकल पढ़ाई की ओर हर गार्जियन सोचता है कि मेरा बेटा जाय, मेरी बेटी जाय । माननीय सदस्य के द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन बिहार में हुआ है, सो मैं मानता हूँ और आपने कहा, मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ । लेकिन आपने परिवर्तन क्या किया, जिस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं, उस तरह से आराम से खुब सुनियेगा भी ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : बोलिये, मैं सुन रहा हूँ ।

श्री बृज किशोर बिंद : जिस विद्यालय में आपने कम्प्यूटर भेजा और विद्यालय का भवन तो बन गया, भवन बनकर तैयार है लेकिन उसमें न पुस्तकालय है, कम्प्यूटर तो है लेकिन कम्प्यूटर के शिक्षक नदारद हैं, है नहीं । अगर उस विद्यालय में कम्प्यूटर पहले से रखा हुआ है तो बिजली गायब है । भाई, आप अपने यहां देख लीजियेगा.....

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : प्लीज, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज बोलने दीजिए ।

श्री बृज किशोर बिंद : उस विद्यालय में बिजली की आवश्यकता नहीं की गई है । आज टेकनिकल पढ़ाई में हमारे यहां के बच्चें जो कम्प्यूटर की पढ़ाई सिखना चाहते हैं, शिक्षक सिखाना चाहते हैं, वो कैसे पढ़ पायेंगे । माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे इस देश के बुनियाद हैं और शिक्षा के अभाव में जब हमारा बुनियाद कमजोर होगा तो नि:संदेह समझ लीजिए कि वह परिवार, समाज, गांव, प्रखंड, जिला, प्रदेश और देश कमजोर होगा, इसपर जरूर विचार कीजियेगा । हमारा बुनियाद कमजोर न हो, इसपर सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहता हूँ । एक जमाना था सभापति महोदय, इस बिहार की धरती पर विदेश के बच्चे विद्या अर्जन के लिए आते थे और विदेशों में बिहार की ख्याति जाती थी, इतिहास में नालन्दा विश्वविद्यालय और भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय गवाह के रूप में है, उनके अवशेष बताते हैं । आज क्या वजह है, तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पाकिस्तान की धरती पर चला गया लेकिन आज वजह क्या है कि शिक्षा में इतनी गिरावट हुई कि जो गरीब-गुरबे समाज के लोग अपने बच्चों को उचित शिक्षा और ऊँची शिक्षा और असली शिक्षा देने के लिए खून पसीना एक करके मेहनत की गाढ़ी कमाई देकर के विद्यालय में भेजते हैं । जहां विद्यालय में इस प्रदेश के अन्दर टॉपर घोटाला होता है, जहां जिस प्रदेश में विश्व के बच्चे आते थे विद्याअर्जन के लिए, आज बिहार का नाम विश्व में जा रहा है घोटाले के नाम पर, यही आपने किया । इसीलिए हमने कहा कि दु:ख हो रहा है .....

टर्न-20/शंभु/08.03.17

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य बिन्द जी, एक तो आप आसन की तरफ मुखातिभ होइये, उधर जा रहे हैं तो आकर्षित कर लेंगे ये लोग। मैं बता रहा हूं आपको।

श्री बृजकिशोर बिन्द : ठीक है हुजूर।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : दूसरी चीज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रिजिम में शिक्षा की बेइंतहा बढ़ोत्तरी हुई है, इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। करनी चाहिए आपको तारीफ सच्चाई यही है। अपने रिजिम में तो ये लोग हां-हां कहते थे, अब.....ठीक है बैठिए-बैठिए। बात करने दीजिए इनको, बैठ जाइये।

श्री बृजकिशोर बिन्द : सभापति महोदय, मैं आपकी बात को अक्षरशः स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर स्वयं नेता बोले, नेता का रिजल्ट न बोले तो मैं उसे नेता के रूप में स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन नेतृत्व बोलना चाहिए। अगर विद्यालय बने और चारदीवारी नहीं है, अभी तक ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक नहीं हैं। जिन बच्चों को विद्या अर्जन करना है टेक्नीकल पढ़ाई चाहे बढ़िया पढ़ाई के लिए अगर चले जाइये तो नियोजित जितने शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी को शिक्षा मिलनी चाहिए वह शिक्षक नहीं दे पाते हैं- और एक तरफ कहते हैं कि जॉच हो रहा है, कार्रवाई हो रही है- कार्रवाई आप कर रहे हैं तो कर क्या रहे थे पहले ? मेरा घर कैमूर जिला में पड़ता है, माननीय मंत्री जी कैमूर जिला के विषय में खूब बढ़िया से जानते हैं- चले जाइये अधौरा पहाड़ी पर आदिवासी विद्यालय....

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : शांति, ललन पासवान जमीन में हैं, वे कैमूर पहाड़ पर अधौरा के साइड में नहीं हैं।

श्री बृजकिशोर बिन्द : इनका भी क्षेत्र पड़ता है।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं तो पूरा पहाड़ पर ही हूँ।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइये। मैं आपका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ और अपने ही आप खामोख्वाह गड्ढा में गिरना चाहते हैं तो उसको कौन रोकेगा ? चलिए बोलिये बिन्द जी।

श्री बृजकिशोर बिन्द : हम समझते हैं कि ललन भाई का भी लगभग आधा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ ही है और मेरा तो कम से कम 157 कि0मी0 लंबा बिहार का सबसे लंबा विधान सभा क्षेत्र है।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : विषय पर आइये, समस्याओं को रखिए।

श्री बृजकिशोर बिन्द : हमारे यहां 100 कि0मी0 में पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासी समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खुला हुआ है- देवड़ी में, परमान खुर्द में, असरखी में, आखन में ऐसे आवासीय विद्यालय हैं, लेकिन अब तक की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि वहां शिक्षक नदारद हैं। बच्चे मांड़ भात, आलू भात, चोखा भात खाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं उस विद्यालय में यह सरकार की स्थिति है। मैं सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप जिन बच्चों के लिए विद्यालय और शिक्षा की बात कर रहे हैं वह आदिवासी समाज के बच्चों का जीवन अधर में लटका हुआ है, कृपया उसपर भी ध्यान रखा जाय।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : माननीय मंत्री ग्रहण कर रहे हैं आपकी बातों को।

श्री बृजकिशोर बिन्द : अभी तक रहने के लिए जो छात्रावास बना है, वह छात्रावास खपरैल है जो उजड़ गया है। मैंने जाकर देखा है, चारदीवारी नहीं है और मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वहां चलकर देख लें कि वहां के बच्चे किस स्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सदन का कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जिनके बच्चे प्राइवेट

स्कूल में नहीं पढ़ने जाते होंगे। जब बिहार में विद्यालय की स्थिति सुधर गयी है तो ये लोग अपने बच्चों का नामांकन राजकीयकृत विद्यालय में क्यों नहीं कराते, क्या वजह है? जब सुधर गयी है तो बढ़िया से सुधर जाए, क्यों नहीं कराते हैं ? कहने के लिए आपने सुधार दिया है, लेकिन जरा जाकर देख लीजिए कि आपने सुधारा है क्या ? विद्यालय की स्थिति बिलकुल सुधर गयी है क्या ? एक ध्यानाकर्षण मैंने किया था और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 34500 कुछ शिक्षकों के अंतर जिला स्थापन का मामला था, जो शिक्षक आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और अपने जिला से लगभग 3 सौ, 4 सौ कि0मी0 की दूरी पर उनका स्थनान्तरण हो गया- परिवार को देखना, पढ़ाई को देखना और आना और माननीय मंत्री जी ने भी यह स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्हें गृह जिला में भेजा जायेगा, लेकिन आज तक उन्हें गृह जिला में नहीं भेजा गया, आज तक उसी तरह से परेशान हैं। जब एक-एक चीज पर आप ध्यान देते हैं तो मैं आग्रह करता हूँ कि एक-एक चीज पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बृजकिशोर बिन्द : केवल एक मिनट सर, क्षेत्र का मामला है। भगवानपुर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति और जनजाति का गांव है भटवलियाँ, वहां पैसा चला गया है, अभी तक दो वर्ष से विद्यालय नहीं बन पाया है। दूसरा गांव है बेल्दी जंगल के किनारे है, वहां पैसा पड़ा हुआ है, जमीन भी उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां भवन का निर्माण हो जाता तो कम से कम बच्चे उस विद्यालय में विद्या अर्जन करते। दूसरा चैनपुर प्रखंड में भालु-बुढ़न, तेनौरा आधा अधूरा विद्यालय का भवन बना हुआ है, आधा उसी तरह से बाकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस विद्यालय का भवन बनाने का काम करें।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : कृपया, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बृजकिशोर बिन्द : ताकि बच्चों का पठन पाठन बढ़िया से चल सके। धन्यवाद।

सभापति(मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, आपका समय आठ मिनट।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : शिक्षा विभाग के अनुदान मांग के वाद-विवाद और आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री के इस मांग के समर्थन में हम आज बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। इसके लिए जो हमें मौका दिया गया है, इसके लिए हम माननीय और आदरणीय सभापति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए कि शिक्षा जैसे विषय पर आपने मुझे मौका देकर के सदन को गौरवान्वित करने का काम किये हैं, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। सभापति महोदय, जिस तरह से आप सदन को चलाने का काम कर रहे हैं, भारत के इतिहास में इस तरह का सदन चलाना कोई साधारण बात नहीं है। सभापति महोदय, जो

शिक्षा का बजट आया है, अगर उस बजट को देखा जाय और भारत के शिक्षा मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस बजट को देखा जाय तो जो बिहार में शिक्षा को जो महत्व दिया गया है। मैं इस बजट के माध्यम से आदरणीय नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री जी को हम अपनी ओर से और पूरे अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर से बधाई देना चाहते हैं। महोदय, चर्चा हो रही थी देश पर, राज्यों पर हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जो बजट आया है उस बजट को एक बार नहीं दो चार बार पढ़ने का काम कीजिए बिहार में क्या हो रहा था, शिक्षा की क्या हालत थी, आपका औसत क्या था और इस औसत को आप निश्चित तौर पर गौर से देखिए तब पता चलेगा।

क्रमशः

टर्न–21/अशोक/08.03.2017

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमशः भारत के प्रधानमंत्री जी जो शिक्षा पर बिहारियों को जो आइना दिखाने का काम किये थे और बिहार में शिक्षा के बजट में जो आइना आया है वह साफ साफ नजर आयेगा । सभापति महोदय, समय कम है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा में जो आमूल परिवर्त्तन हुआ है, चाहे प्राईमरी एडुकेशन को देखा जाय जो प्राथमिक विद्यालय थे, उसको आबादी के आधार पर मध्य विद्यालय में परिणत किया गया, जनसंख्या को देखते हुये मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत किया गया, बच्चों की संख्या को देखते हुये जो उच्च विद्यालय थे उसको प्लस टू में परिणत किया गया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ वह बिहार न्याय के साथ विकास पर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संख्या बल के आधार पर, आबादी के आधार पर जब अपना नीति तय करते हैं तो उसको देखने की जरूरत हैं, जहां तक विद्यालय भवन का सवाल है, पूर्व के वक्ता बोल रहे थें, पहले हमलोग जब छोटे–छोटे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो खुले आकाश में पढ़ने का मौका मिला । आज जब हम देखते हैं तो जहां भी देखते हैं, पहुंचते हैं तो पूछते हैं कौन सा भवन हैं, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है और जब कुछ और देखते हैं तो महोदय ये शिक्षित मुख्यमंत्री बिहार के नेतृत्व में जो शिक्षा का विकास हुआ हैं, एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालय से जब उन्होंने सोचा कि एक मॉडल विद्यालय की उन्होंने पूरे बिहार में स्वीकृति प्रदान की, बिहार के 535 प्रखण्डों में मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया गया, मॉडल विद्यालय तो बनकर तैयार हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा नीति, 2017 में उन्होंने प्रावधान किया है कि जो आने वाला समय होगा उसमें गुणवत्ता के आधार पर वहां पर पढ़ाई होगी । जब आठवां

तक मॉडल विद्यालय में, प्रखण्ड के एक स्कूल मॉडल विद्यालय हुआ, उसमें कक्षा, शिक्षा का अध्ययन होगा, उन्होंने सोचा कि जब शिक्षा नीति में सुधार हुआ है तो उन्होंने साईकिल योजना की शुरूआत किये, पूर्व के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि लड़कियां जब साईकिल पर चढ़कर जाती थी तो लोग मुड़ कर देखते थे, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में बिहार पहला राज्य है जहां पर लड़कियां साईकिल से स्कूल जाती हैं, पिछड़े इलाकों से आकर शिक्षा ग्रहण करती हैं और गर्व महसूस करती हैं, उनके अन्दर जज्बा पैदा होता है, उनके अन्दर स्वाभिमान पैदा होता है, महोदय, किसी भी परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए वह हमेशा तैयार रहती हैं छात्रायें । जब छात्र और छात्राओं में लगा कि भिन्नता हैं तो माननीय मुख्यमंत्री यात्रा में बराबर निकल जाते हैं, भारत के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उसको देखने के लिए एक-एक गांव जाते हैं । आश्चर्यजनक बात हैं, हम कहना चाहते हैं भाजपा के लोग देखें दूसरे मुख्यमंत्री को, वे गांव जाते हैं क्या? हम कहना चाहते हैं कि यह जो बिहार है वहां पर प्लस टू में भी पढ़ाई करने के लिए एक व्यापक योजना की तैयारी की गई । उस योजना के मुताबिक कोई भी सदस्य बतला दे कि हमारे प्रखण्ड में हाई स्कूल से जो प्लस टू किया गया, उसका भवन का निर्माण नहीं हुआ । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हमारे साथी पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनको बराबर का दर्जा देते हुये सभी प्रखण्डों में जो-जो उत्क्रमित किया गया हाई स्कूल से प्लस टू, उसमें भवन का निर्माण किया गया हैं, हम मानते हैं कि भवन बन गया है, शिक्षकों की कमी हैं, हम कहना चाहते हैं कि महोदय, आपकी नीतियां शिक्षाविद् की नीतियां है, आपके नेतृत्व में बिहार में शिक्षा का विकास हुआ हैं, बिहार के बाहर जाते थे तो बिहार के लड़के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करते थे, माननीय मुख्यमंत्री पूछते थे कि कहां घर है, तो कहते थे कि नालंदा है, मुजफ्फरपुर है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पुनः जब शिक्षा नीति पर नीति बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बिहार के वैसे बच्चे जिनका पैसा, यहां का पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय शिक्षा मंत्री ने कदम उठाया, क्या कदम उठाये ? प्रत्येक जिला में उन्होंने इंजीयिरिंग कॉलेज की स्थापना की, प्रत्येक जिला में उन्होंने नालंदा में, पावापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के अतिरक्त पॉलिटेकनिक कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने ए. एन.एम. नर्सिग कॉलेज, अन्य टेकनिकल कॉलेजों की स्थापना करने का काम किया, जिससे बिहार के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, बिहार का जो पैसा बाहर जा रहा था उसको रोकने का काम किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से । महोदय, जहां तक क्षेत्र का सवाल हैं, हम नालंदा जिला

के इस्लामपुर से चुन कर आते हैं, नालंदा की धरती शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा पूरे दुनिया में परचम फहराने का काम किया हैं, चाहे मेडिकल का सवाल हो, चाहे इंजीयिरिंग का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हेा, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से चाहे पूर्व के वक्ताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, उसकी अवस्था जीर्ण-शाीर्ण थी और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आये तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को उद्धार करने का काम किया, आवाज को बुलन्द करने का काम किया और भारत के सरकार से मिलकर के निवेदन करके नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को नया यूनिवर्सिटी नालंदा में बनाने का काम किया, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का देन हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आपका एक मिनट का समय बचा है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : हम कहना चाहते है कि उसी नालंदा में, नालंदा का इतिहास है । आदरणीय सभापति जी, हम कहना चाहते है कि आप तेलहड़ा की धरती को आप जानने का काम किये होंगे, तेलहड़ा में खुदाई हो रहा हैं, नालंदा का जो इतिहास हैं, यूनिवर्सिटी का, उससे पांच सौ गज पहले तिलाजित विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी चलता था, वह विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविालय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सभा के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब आदरणीय महामहित राष्ट्रपति जी आये थे सर्टिफिक्ट बांटने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आवाज बुलन्द करने का काम किये थे, हम कहना चाहते है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर तेलहड़ा में तिलाजित विश्वविद्यालय को स्थापित करने की कृपा की जाय, हम यही सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं...

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब आप समाप्त करें, दूसरे पर ध्यान दीजिये ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : समय को ध्यान में रखते हुये बिहार की सरकार जिस तरह से शिक्षा में अपने बजट पर अपने बिहारियों पर ध्यान दिया है यह काबिले तारीफ हैं, हम सदन के माध्यम से अपने माननीय मुत्र्ख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देतें हैं, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय सदस्य श्री ललन पासवान, आपका समय दो मिनट ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, हम जहां से आते हैं वही से शुरू करते हैं । चैनारी पूरा कैमूर के सटे हुये, बिहार का सुदूर इलाका है, जहां पीने के पानी से लेकर शिक्षा की स्थिति खत्म है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यम महोदय ने आसन ग्रहण किया)

वहां दर्जनों विद्यालय हैं, जहां टेन प्लस टू हुआ है, कहीं उच्च विद्यालय है, उत्क्रमित हुआ है, जहां शिक्षक नहीं हैं । दो-दो हजार छात्रों, तीन-तीन हजार छात्रों की संख्या हैं कटुम्बा में, टेन प्लस टू हुआ है, अभी तक मात्र चार शिक्षक हैं, उच्च विद्यालय टेन प्लस टू है, वहीं बगल में रोहतास उच्च विद्यालय टेन प्लस टू हैं, तीनों में मात्र दो भवन पर स्कूल बचा हुआ है, तीनों, चारों भवन टूट चुका हुआ है । क्रमशः

टर्न-22/ज्योति

08-03-2017

क्रमशः

श्री ललन पासवान : तीनों चारों भवन टूट चुका है, उसकी स्थिति पूरे नौहट्टा रोहतास के सभी सामूहिक तौर से कहें तो बोलिया है टुंम्बा है, मझीगांवा हैं, नौहट्टा है और एक, चेनारी में, जब मैं पहली बार एम0एल0ए0 था तो प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय गंगोत्री प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में वृश्ण पटेल जी माननीय मंत्री थे तो 56 लाख रुपया दिए थे । 2005-2006 से दिया हुआ ये 2017 हो गया, आजतक प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय नहीं बना । मैं अपने फंड से दो कमरा दिया था उसी में उच्च विद्यालय चल रहा है 10 प्लस टू । मैं अपने फंड से पैसा दिया । अपने फंड का दो कमरा मैं बनवाया। सरकार का बना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललन जी, आपका दो ही मिनट टाईम है ।

श्री ललन पासवान : बहुत महत्वपूर्ण है, 56 लाख रुपया, लड़कियों को पढ़ने के लिये वहां मात्र एक ही 10 प्लस टू स्कूल है । इतने दिन हो गए अभी तक विद्यालय नहीं बने हैं । पैसे वापस लौट गए । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको बनवा दें मंत्री जी । एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सरकार शिक्षा के मामले में विकास की है । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं । हमारी साक्षरता दर क्या स्थिति है ? बस एक मिनट का समय दिया जाय दलित होने नाते । अनुसूचित जाति की बात है, इसलिए एक मिनट का समय दिया जाय । सरकार कहती है कि आज 63 प्रतिशत साक्षरता दर है, जो सी0ए0जी0 के रिपोर्ट में है ।

(व्यवधान)

इसलिए तो मैं कह रहा हूँ । कल्याण मंत्री जी भी महादलित हैं । आप ही ने बनाया है । लेकिन मैं कहूँगा कि 21 प्रतिशत साक्षरता दर है ।

अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी को क्या कह रहे हैं कि आप ही ने बनाया है । मंत्री बनाया है, महादलित भी इन्होंने ही बनाया है ?

श्री ललन पासवान : महादलित भी बनाया है और मंत्री भी बनाया है । दोनों उन्होंने ही बनाया है । 21 प्रतिशत साक्षरता दर है और महिलाओं का साक्षरता दर है 14 प्रतिशत । हमारे अनुसूचित जाति के चमार, धोबी, पासी, डोम, मुशहर, मेहतर जिसको दलित महादलित कहें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहें, आदिवासी कहें ढाई सौ वर्ष लगेगा आज की तारीख में साक्षर होने में मतलब कि 100 प्रतिशत होने में 70 साल लगेगा, 200-250 साल लगेगा हमारी महिलाओं को साक्षर होने में । मुशहर की आज भी बहू-बेटियॉं, आठ साल की बच्चियॉं माथे पर झाड़ू, बढ़नी लेकर जाती हैं । पढ़ने का कहीं स्थान नहीं है । एक शब्द और आपसे आग्रह करेंगे महोदय कि बिहार में आवासीय विद्यालय, जिसकी चर्चा ब्रज किशोर भाई कर रहे थे । रोहतास और कैमूर में 11 आवासीय विद्यालय हैं । श्रीमान् इसमें हम बैठे हुए लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार सदन मे भी हमने कहा है, उस खाना को खाकर, हमलोग जो यहॉं बैठे हुए लोग है, खानाबदोश, बद से बदतर जिंदगी जीता है आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राएं । महोदय, अगर खाना खाकर दिन भर में हॉस्पिटल नहीं जाय तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा ।

अध्यक्ष : चलिये समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : एक खानाबदोश की जिंदगी है । आवासीय विद्यालय में सुअर भी खाना नहीं खायेगा जिस तरह से खाना मिलता है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ललन जी ।

श्री ललन पासवान : आवासीय विद्यालय में 5 प्रतिशत ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो गया । आप तो अंतिम बात कह करके तीन बात बोले । अब आप बैठ जाईये। चलिए विनय वर्मा जी बोलिये ।

श्री विनय वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा पर नहीं, मुझे बिहार के वन एवं पर्यावरण पर बोलने के लिए कहा गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका समय 5 मिनट है । इधर उधर की बात करने में चला जायेगा ।

श्री विनय वर्मा : सर, आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण ...

(व्यवधान)

हमको इसपर बोलने के लिए कहा गया है ।

अध्यक्ष : विनय जी आप आसन की तरफ देखिये ।

श्री विनय वर्मा : जी, आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरुकता बढ़ी है । राज्य का पर्यावरण एवं वन विभाग इन समस्याओं के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है । पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार राज्य में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कर बाढ़ एवं सूखा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है । कृषि वानिकी के रुप में किसानों के रैयती भूमि पर भी वृक्षारोपण कर बाढ़ के प्रभाव को कम करने की दिशा में सतत् रुप से कार्यरत है । भू-जल संरक्षण की दिशा में वन विभाग क्षेत्र में भू-जल संरक्षण के उपाय पर बाढ़ के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में दूरगामी प्रयास कर रहा है और भूमि विकास जिसके लिए विभाग नोड्ल विभाग है, के अंतर्गत विभाग के राज्य के बड़े एवं मझौले स्थल के जल संग्रहण स्थानों को चिन्हित कर उन्हें वैज्ञानिक रुप से प्रबंधन करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, समाप्त करिये ।

श्री विनय वर्मा : सर, अभी तो बोल ही रहे थे । मैं पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला हूँ और आपके बिहार क्षेत्र का जो भू-भाग है उससे सबसे ज्यादा भू-भाग हमारे जिला पश्चिम चम्पारण में है और वहाँ पर बिहार का एक ही टाईगर रिजर्व है बाल्मिकी टाईगर रिजर्व ।

(व्यवधान)

अभी भाई रहने न दीजिये, हमको अपनी समस्या बोलने न दीजिये । 2005 के वन संरक्षण के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है उसके बाद गया, पूर्वी चम्पारण, रोहतास आदि में है ।

अध्यक्ष : चलिये विनय जी लेकिन अंत में यही हुआ कि न वो माने न आप माने।

श्री विनय वर्मा : हमारा पाँच मिनट है न सर ।

अध्यक्ष : आप एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्री विनय वर्मा : हमारे यहाँ 910 स्क्वायर कि0मी0 बाल्मिकी वन क्षेत्र में से 899.38 वर्ग कि0मी0 में बाघ सेंचुरी बनाया गया है और बाघ योजना है, जो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, टाईगर प्रोजेक्ट जो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय वन मंत्री और वहाँ पर आज ऐसी स्थिति हो गयी, जहाँ पर 12 और 8 बाघ बच गए थे, वहाँ पर आज हमारे यहाँ करीब 32 बाघ उपलब्ध हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आप दो मिनट में अपनी बात कह डालिये ।

श्री सत्यदेव राम : जी महोदय, आपने हमको दो मिनट समय दिया है, मैं सुबह से इसी का इंतजार कर रहा था और वह मिल ही गया । महोदय, कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरे

साथ बहुत ही अन्याय होता है । जब हमारी पार्टी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, हमारे मुद्दो को चुरा लिया जाता है । हमने उठाया था 2000 में जब बिहार और झारखण्ड अलग हुआ था । हमने बिहार को विशेष दर्जा की मांग की थी । उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी केन्द्र में कृषि मंत्री बैठे थे । नहीं सुनी गयी, बाद में हमारे मुद्दों को चुरा लिया गया । महोदय, हम लगातार पूर्ण शराबबंदी के लिए लड़ते रहे, हमारे दर्जनों लोगों पर आज भी केस है । आपके प्रशासन ने लाठी मारा है, केस किया है । आज वह भी मुद्दे चुरा लिए गए, छीन लिए गए । और फिर मैं शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ । निश्चित रुप से आज हमारी बातों की कोई तरजीह नहीं मिलेगी लेकिन मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे ये मुद्दे छीन लिए जायेंगे । महोदय, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि एकल शिक्षा नीति प्रणाली लागू करें। जबतक एकल शिक्षा नीति प्रणाली लागू नहीं होगी तबतक शिक्षा के गुणवता के विकास की बात करने की बात बेमानी होगी । महोदय, यह दोहरी शिक्षा नीति जबतक जारी रहेगी तबतक गरीबों के बच्चे डी0एम0 और एस0पी0 नहीं बनेंगे, बड़े लोगों के बच्चे बनेंगे । आज सदन में जितनी शिक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, सारे लोगों से ईमानदारी से पूछा जाय कि आपका बच्चा उस सरकारी विद्यालय में है तो कोई हाथ नहीं उठा सकता है । अपने बच्चों को धीरे से छुपा कर भेज दे रहे हैं प्राईवेट विद्यालयों में और गरीबों के साथ, मेहनतकश किसानों के साथ यहाँ धोखाधड़ी हो रही है । इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । महोदय, आज मुझे एक मिनट का समय दीजिये । यह जरुरी बात है । यह नीति का सवाल है महोदय । ये दोहरी शिक्षा नीति सरकार की है, जो गलत है । यह मजदूरों, गरीबों, किसानों के साथ यह एक धोखा है, ईमानदारी से बात करनी चाहिए । सरकार आपकी रहेगी, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा हूं कि सरकार नीति बदलें, नहीं तो मुट्ठी भर लोग डी0एम0 और एस0पी0 बनते रहेंगे और गरीब का बेटा चपरासी भी नहीं बनेगा । खिचड़ी विद्यालय में जाकर कोई इंतजार करता है कि कब वह ढक्कन खपड़िया खड़खड़ाया कि खिचड़ी भेटायगा और खिचड़ी खाकर चल देता है । आप कहते हैं कि 99 प्रतिशत बच्चे स्कूल में गए हैं, प्रशासन ने आपको धोखा दिया है । मैं साफ कहता हूँ । मैंने एक विद्यालय का सर्वे किया है ।

टर्न-23/8.3.2017/बिपिन

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री सैयद अबु दौजाना जी, आप बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री सैयद अबु दौजाना : अध्यक्ष महोदय, आज मैं शिक्षा विभाग के वाद-विवाद पर महा गठबंधन सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । नालन्दा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां पर दुनियां के सभी देशों से स्टूडेन्ट्स पढ़ाई करने के लिए भारत आकर बिहार के नालन्दा में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश और दुनिया में तरक्की के लिए ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात सुनी गई । अब वह बोल रहे हैं । अब आप की कोई बात नहीं जाएगी । आप दौजाना जी को बोलने दीजिए ।

श्री सैयद अबु दौजाना : एक-से-एक पढ़-लिख कर हमारे युवा नौजवान अपने देश के भविष्य को सँवारने में लगे हुए हैं । महोदय, आज जितना भी विकास हुआ है । यहां तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जिसके बदौलत महोदय, यह सबों को बताने की जरूरत नहीं है । यह सब शिक्षा का ही कमाल है । मुझे फख्र है अपने सरकार पर, मुझे गर्व है अपने प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर, मुझे खुशी है अपने ऊर्जावान युवा उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, मुझे फख्र है शिक्षा मंत्री जी पर।

अध्यक्ष महोदय, हमारी महागठबंधन की सरकार ने प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विस्तार और उसकी गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आज इसी का नतीजा है कि बहुआयामी...

अध्यक्ष : ठीक है, दौजाना जी, अब समाप्त करिए । आपकी बात प्रौसिडिंग्स में आ जाएगी ।

श्री सैयद अबु दौजाना: they will address the all issues related to teacher, teaching and teachers. Preparation of the professionals curriculums of the design. It also aims to develop the strong professional cadre of teachers. By setting of the performance standard and creating the top classes institutional of facilities for innovative of the teaching.The scheme will also address to the qualified teachers attracting talented of the teaching of the professors and rising the quality of teaching at school and colleges.

अध्यक्ष : श्री रामप्रीत पासवान । आप पांच मिनट में समाप्त करिए ।

श्री रामप्रीत पासवानः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य संजय सरावगी जी ने शिक्षा विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, मनुष्य के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है । बहुत सारे सदस्य, सभी उच्च विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। हो सकता है इनके स्कूल में पढ़ाई होता हो । हम मधुबनी जिला से आते हैं । समय बहुत कम है । उच्च विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है । शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कोचिंग में प्राइवेट ट्यूशन करके आपका रिजल्ट निकलता है । मैं आपको आमंत्रण देता हूं जो मेरे विद्यालय हैं, मेरे जिला के किसी विद्यालय में आप चले आएं और यदि उसमें 50 परसेंट बच्चा उपस्थित हो तो आप मुझे जो कहिये । बच्चे नहीं आते हैं । कोचिंग में पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट होता है । आप परीक्षा टाइट लेते हैं । आपके विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है । विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं । प्राथमिक विद्यालय को आपने मध्य विद्यालय बनाया, मध्य विद्यालय को आपने उच्च विद्यालय बनाया लेकिन आपने शिक्षक बहाल नहीं किया । कहीं भी शिक्षक नहीं है । विज्ञान का शिक्षक नहीं है। पढ़ाई नहीं होती है । स्थिति यह है आपकी । जहां महाविद्यालय है, महाविद्यालय में आठ हजार व्याख्याता को 2014 से आपने नहीं किया । वहां विषय के शिक्षक नहीं है । हम तो पहली बार देखा है बिना शिक्षक के बच्चे पढ़ते हैं और आप परीक्षा लेते हैं । हाई स्कूल का जो परीक्षा होता है बच्चे परीक्षा देते हैं । मैं एक बात बता दूं और मधुबनी में हमारे एक विद्यालय हैं सूरी जिसको आपने प्लस-टू किया है, आपके राज्य में तीन दिन लड़के और तीन दिन लड़कियां स्कूल करती हैं । उसके पास भवन नहीं है और यही चाहते हैं । बाकी लोग, जितना आप पीठ थपथपा लें, शिक्षा का पूरा बंटाधार हो गया है । पूरा बंटाधार हो गया है शिक्षा का और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले एक डी.ई.ओ. और डी.एस.ई. होता था, आज आप एक डी.ई.ओ. और पांच पदाधिकारी बनाए हैं । 15 दिन मीटिंग आप पटना में करते हैं । ये सभी पदाधिकारी आपके पटना आने के बहाने वहां और निरीक्षण नहीं करते हैं । एक भी पदाधिकारी आपका विद्यालय का निरीक्षण नहीं करता है । कोई मध्याह्न भोजन का पदाधिकारी है, कोई उच्च विद्यालय का पदाधिकारी है, कोई स्थापना का पदाधिकारी है । आपने सबसे बड़ा गलत काम किया शिक्षक को आपने बी.आर.सी.-सी.आर.सी. बनाया और वही दलाली करता है पदाधिकारी का । पदाधिकारी और शिक्षक के बीच में मिलकर दलाली करता है और आपके पदाधिकारी शिक्षक के जेब के तरफ ताकता है। मध्याह्न भोजन में दलाली होती है । आपने शिक्षको को भवन बनाने के लिए दे दिया है। सरकार के पास भवन विभाग है और भवन विभाग से आपको भवन बनना चाहिए लेकिन आप प्राथमिक विद्यालय के, मध्य विद्यालय के शिक्षक को भवन बनाने के लिए दिए हैं । हमारे यहां 15 प्रतिशत् शिक्षक पर एफ.आई.आर. हुआ है और हमने माननीय

मुख्यमंत्री जी को कहा था निश्चय यात्रा में, आपको महीना में 30 दिन में 20 दिन कलेक्टेरियट के सामने धरना प्रदर्शन होता है । विद्यालय में कहीं पढ़ाई नहीं होती है । आप जाकर देखिए । हो सकता है दूसरे सदस्य के यहां पढ़ाई होता हो । लेकिन मधुबनी की स्थिति पूरा बंटाधार है । कहीं पढ़ाई नहीं होती है । मैं एक बात बता दूं आपको, ठीक है, आपने शिक्षक दिया, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला शिक्षक । पहले एक कैडर होता था अध्यक्ष महोदय, जिला का शिक्षक, वहां पांच कैडर हो गया है और दस संरक्षक बन गया है । प्रतिदिन धरना प्रदर्शन में वह रहता है । समान कार्य का समान वेतन मांगता है लोग । बिना संरक्षण के ये सारे लोग शिक्षक हैं । शिक्षक की जो गुणवता होनी चाहिए, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं । गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको कितना मिलेगा । इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बिना प्रशिक्षण के वह शिक्षक है । उनको इन्होंने बहाल किया है और कहीं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़कर बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं । इनके विद्यालय में पढाई नहीं होती है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है । मेरे यहां एक आर0के0 कॉलेज है । उस समय में जब तिरहुत कमिश्नरी था, उस समय का वह विद्यालय है । वहां प्रोफेसर नहीं हैं । बच्चे कभी क्लास में नहीं जाते हैं, कभी काल हमलोग टहल कर चले जाते हैं । पेशे से शिक्षक रहे हैं । जानकारी है । एक क्लास नहीं चलता है । पहले कॉलेज में नहीं चला, अब हाई स्कूल में नहीं चलता है और यहां परसाही मध्य विद्यालय में शिक्षक नहीं है । बच्चे को क्या पढ़ाया जाए ? क्या पढ़ेंगे बच्चे ? इसलिए यहां प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय केवल खिचड़ी खाने के लिए बच्चे आते हैं । आपने दिखाया है कि नामांकन हो गया । मैं मानता हूं बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो गया है लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे नहीं आते हैं । वह बच्चे अभी भी खासकर जो हमारे दलित, महादलित समुदाय के बच्चे हैं इन बच्चों का निश्चित रूप से वहां अध्यापन नहीं होता है । सातवां वर्ग के बच्चे को इतिहास नहीं लिखने आता है । इतना गिरावट हो गया है और एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं । मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुझाव देता हूं, मैं आपको उलाहना देता हूं शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपके चेम्बर से एक दिन आठ मिनट बैठकर चले आये लेकिन आपको फुर्सत नहीं हुआ एक विधायक से बात करने का । मैं उलाहना देता हूं अपने शिक्षा मंत्री को और मैं बैठा रह गया । संस्कृत के कुछ शिक्षक लोग थे लेकिन हमसे बात नहीं किए और हम उठ करके चले आए । कुछ सुझाव आप नहीं लेंगे तो क्या आप पूरे बिहार के शिक्षा को सलाह देंगे ? इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने माननीय सदस्य का सुझाव लीजिए और..

अध्यक्ष: ठीक है । धन्यवाद ।

श्री रामप्रीत पासवानः बिना सुझाव लिए शिक्षा में गुणवत्ता नहीं होगी । एक मिनट सर । मेरा क्षेत्र है।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री रामप्रीत पासवानः आज आपने प्रश्न का जवाब दिया है । हमारे यहां सम विकास योजना से 10 विद्यालय बना । उस 10 विद्यालय में चार विद्यालय अभी तक अधूरा है । वह नहीं बना है और आपने जवाब दिया है, जो पैसे आएंगे तो बनेंगे । भवन बन गया । खिड़की-चौखट नहीं लगा है, प्लास्टर नहीं हुआ । बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । धन्यवाद ।

टर्न-24/कृष्ण/08.03.2017

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय शिक्षा मंत्री ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की मांग पर 14 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें हैं । हम धन्यवाद देते हैं माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी का, सुरेन्द्र कुमार जी का, राज किशोर जी का, अशोक कुमार जी का, मिथिलेश तिवारी जी का, युवा सदस्य फराज फातमी साहब का, जितेन्द्र जी का एज्या जी का, वृज किशोर बिंद जी का, चन्द्रसेन प्रसाद जी का, ललन पासवान जी का, सैयद अबु दोजाना जी का, सत्यदेव राम जी का और रामप्रीत पासवान जी का । उन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात को सदन में रखा, जिसको सरकार आनेवाले समय में वित्तीय वर्ष में इसको नियमानुकूल इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग पर अपने वक्तव्य की शुरूआत मैं एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक से करना चाहता हूं :-

''नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत् ।
नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम् ।।''

यानी विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं या सुख नहीं ।

महोदय, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज 8 मार्च, 2017 को मैं सदन में शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं शिक्षा पर प्रस्तावित व्यय के संबंध में माग संख्या-21 पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं । महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं एवं लड़कियों का दिवस है, यह लिंगभेद विरोध का दिवस है और महिलाओं के शक्तिकरण का दिवस है । बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के संकल्प का दिवस है । इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी महिलाओं और बेटियों को शुभकामनायें देता हूं और चतुर्दिक उन्नति करने के लिये उनका आह्वान करता हूं ।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक प्रमुख संदेश है :

" Educate girl and empower a nation. "

हम अपने क्रांतिकारी एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने Educate girl and empower a nation पर 10 वर्ष पूर्व साईकिल एवं पोशाक योजना के माध्यम से शुरूआत करने का प्रयास किया । इसके तहत हम आपको एक आंकड़ा देना चाहते हैं ।

महोदय, वर्ष 2017 की मैट्रिक की परीक्षा में 8,98,256 बालक एवं 8,67,471 बालिकायें, इण्टर की परीक्षा में 7,04,868 बालक एवं 5,56,925 बालिकायें शामिल हुई हैं । लगातार बिहार में लड़कियां मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में अधिक से अधिक की संख्या में शामिल हो रही है और 2017 की मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की भागीदारी 49 प्रतिशत एवं इण्टर में 44 प्रतिशत रही है अर्थात् आधी अपनी आधी हिस्सेदारी प्राप्त करने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार के लिये एक बड़ी बात है कि हमने अपने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिये, शिक्षित करने के लिये जो सरकार ने दस वर्ष पूर्व प्रयास किया था, वह आज परिलक्षित हो रहा है । मैं यहां भारत की महिला सावित्री बाई फूले और बाबा साहब अम्बेदकर को याद करना चाहता हूं जिनके अथक प्रयासों से भारत में महिलाओं के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ । बाबा साहब ने कहा था कि –

" I meassure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

आधुनिक शिक्षा के महत्व को हमारे महापुरूषों ने भी अच्छी तरह समझ लिया था तभी तो स्वामी विवेकानन्द ने कहा था –

" There is only one purpose in whole life- Education otherwise what in the use of men and women, land and wealth.... If the poor cannot come to education then education must go to him ... Our work should be mainly Educational both Moral and Intellectual."

इसीलिये हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में शिक्षा को सबसे अधिक बजट देकर यह साबित कर दिया है कि हम शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं । हमारी

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष कर बालिका की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संपन्न किये हैं और शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार को हम अग्रसर कर रहे हैं । शिक्षा के द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य को संक्षिप्त जानकारी मैं आपके समक्ष रख रहा हूं ।

शिक्षा में सुधार के लिये 2016 में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा का उदाहरण देकर बिहार में प्रस्तुत किया गया । यह क्रम भी इस वर्ष जारी रहा । आज छात्र-छात्राओं में स्पष्ट संदेश गया है कि कड़ी मेहनत वाले बच्चे ही अच्छे अंक लायेंगे अभिभावकगण भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक और सचेत हुये हैं । पढ़ने की, सीखने की संस्कृति कायम हुई है । इसे हम भविष्य में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कायम रखेंगे ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 9 प्रमंडलों में परीक्षा केन्द्र की स्थापना की जा रही है एवं 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं । इससे बच्चों एवं अभिभावकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिये पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ।

अंक-पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों के लिये बच्चों को कठिनाई होती थी और सत्यापन की आवश्यकता होने पर परेशानी झेलनी पड़ती थी । 2005 से अद्यतन मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के सभी अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र ऑन लाईन कर दिये हैं अब नियोक्ता को बिहार के बच्चों के प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिये परीक्षा समिति कार्यालय से पत्राचार नहीं होगी एवं अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन समिति के वेवसाईट से किया जाना संभव हो पायेगा ।

आवश्कता पड़ने पर बच्चे भी अपने अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र दुनिया के किसी भी कोने से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं । इस सुविधा के लिये आधार कार्ड से जोड़ कर फ्री डिजिटल लॉकर की सुविधा दी गयी है ।

इस बार की परीक्षा में हमने ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये हैं तथा उत्तर पुस्तिकाओं की बार कोडिंग कर पारदर्शी मूल्यांकन कराने की व्यवस्था की है । इससे गोपनीयता भी रहेगी और पक्षपात की संभावना समाप्त हो जायेगी । यद्यपि नई प्रणाली के कारण कुछ कठिनाई भी हुई है, जिसे पूरी संवेदना एवं पारदर्शिता के साथ दूर किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने कहा था कि -

" Those who educate chilren well are more to be honored than those who produce them, for they only gave them life and these the art of living well. "

हमारी भारतीय परम्पराओं में गुरूओं का गुणगान तरह-तरह से किया गया है और शिक्षक यदि प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रहेंगे तो वे अपना पूर्ण योगदान नही दे पायेंगे ।

इसीलिये हमारी सरकार ने 34,540 कोटि के सहायक शिक्षक के स्थानान्तरण से संबंधित नीति का निर्धारण किया है । इस कोटि के पुरूष शिक्षक जिनका पदस्थापन अपने गृह जिला में नहीं है, उनके द्वारा विभाग से यह मांग लगातार की जाती रही है कि उनके एकल अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिये नीति बनायी जाय । विभाग ने ऐसे शिक्षकों के कठिनाई एवं उनके द्वारा तनावरहित शिक्षा देने के उद्देश्य से इस कोटि के शिक्षकों के जिला के अंदर एवं अंतरजिला स्थानान्तरण से संबंधित नीति का निर्धारण करते हुये विभागीय आदेश ज्ञापांक 92 दिनांक 10.02.2017 निर्गत किया गया । इसके आधार पर जिन पुरूष शिक्षकों की सेवा अविध दो वर्ष या उससे कम रह गई है, गंभीर रोग से ग्रसित हैं एवं पति-पत्नी के पदस्थापन के आधाार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई की जा सकेगी ।

राज्य सरकार की यह नीतिगत निर्णय है कि प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम एक उर्दू शिक्षक का पदस्थापन किया जाय । वर्ष 2013 में उर्दू शिक्षकों के नियोजन के लिये विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गयी । उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक 14.11.2016 से 18.11.2016 की अवधि में कैम्प का आयोजन किया गया था। इसमें पंचायत नियोजन इकाई को प्रखंड स्तर पर एवं प्रखंड नियोजन इकाई/नगर नियोजन इकाई का जिला स्तर पर कैम्प का आयोजन किया गया एवं हजारों उर्दू एवं बंगला शिक्षकों की बहाली की गयी है ।

नियोजित शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान के लिये राज्य सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान करने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत केन्द्रांश मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराने फलस्वरूप नियोजित शिक्षकों के माह नवम्बर,2016 से वेतन भुगतान की समस्या उत्पन्न हो गयी थी । हमने नियोजित शिक्षकों के माह नवंबर,2016 से फरवरी,2017 के वेतनादि भुगतान के लिये राज्य सरकार ने अपने निधि से 2100 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया ।

महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां मौजूद हैं । हम इनसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह शिक्षा के लिये चिन्तित रहते हैं, जिस तरह शिक्षा के लिये परेशान रहते हैं, जिस तरह शिक्षा के स्तर को बिहार में बढ़ाने के लिये परेशान रहते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे प्रोग्राम एडवाईजरी बार्ड ने बिहार सरकार को 5,799 करोड़ रूपये देने का वादा किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने मात्र 2,706 करोड़ रूपया ही उपलब्ध कराया है । हमारे नेता यहां पर बैठे हुये हैं, जितना परेशान इस सरकार में रहते हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये हमारा बकाया 3093 करोड़ रूपया जो भारत सरकार के पास बाकी है, उसके लिये भी अगर ये परेशान रहते तो सर्व शिक्षा

अभियान में जो हमने नियोजित शिक्षक को पैसा दिया है, उस पैसे से सर्व शिक्षा के माध्यम से हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिये क्रियेटीव कार्य करने के लिये प्रयास करते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बसाव क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा गत वर्षों में लगभग 21,253 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं । बच्चे को पढ़ने के लिये विद्यालय भवन उपलब्ध होने चाहिए । इस उद्देश्य की प्रतिपूर्त्ति के लिये वैसे बसाव क्षेत्र जहां एक किलोमीटर की परिधि में एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय उपलब्ध है, वहां भूमिहीन एवं भवनहीन प्राथमिक विद्यालय के संबंधित बसाव क्षेत्र के अन्य प्राथमिक, मध्य विद्यालय में शिक्षकों के इकाई सहित सामंजन करने का निर्णय विभागीय आदेश ज्ञापांक 197 दिनांक 09.02. 2017 के द्वारा लिया गया है । ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या 1773 है ।

महोदय, विद्यालय में औसत उपस्थिति को बढ़ाने के लिये लाभुक योजनाओं से वैसे छात्र-छात्राओं को ही आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है, जिनकी न्यूनतम औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत है ।

टर्न-25/राजेश/8.3.17

श्री अशोक चौधरी, मंत्री, क्रमशः जिसकी न्यूनतम औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत हो, इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के लिए 608.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है जिससे एक करोड़ 16 लाख 70 हजार 776 बच्चे के लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया है । प्रथम किश्त के रुप में 422.00 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है । सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रवृति की राशि वितरण हेतु तत्काल कुल 100 करोड़ की राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गयी है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुने हैं, आप बैठिये, हमारी बात को भी सुनिये । शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसी से पता चलता है कि शिक्षा के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं कि मात्र 6 विधायक शिक्षा विभाग के मांग पर यहॉ पर अभी बैठे हुए हैं, अगर आपलोग इतना ही चिंतित रहते शिक्षा के लिए तो पूरा विपक्ष को यहॉ बैठाते और शिक्षा पर बहस करते ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए हर्ष की बात है कि 6-14 आयु वर्ग के लगभग 99% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। इन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले, इसके लिये हमारा सतत् प्रयास जारी है । हमारे विद्यालयों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे आ रहे हैं

जिनके माता-पिता पढ़े-लिखें नहीं हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, परन्तु अपने बच्चों को पढ़ाने का और आगे बढ़ाने की लालसा उनके मन में है। इनकी मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका या बज्जिका है। खड़ी हिन्दी की भाषा, शब्दावली इनके लिये दुरूह हो जाती है। ऐसे बच्चों को सहजता से एवं सुगमता से स्कूल के लिये तैयार करना तथा कक्षा के क्रियाकलाप एवं किताबों से जोड़ना और सीखने के लिये वातावरण पैदा करना हमारे लिये बड़ी चुनौती है। इस दृष्टि से हम **'चहक'** नाम से स्कूल रेडिनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं । इसके लिये एस0सी0ई0आर0टी0, बी0ई0पी0 एवं किलकारी के सहयोग से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पूरे राज्य में वर्ग- 1 से 8 के बच्चों के लिये हमनें आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की । इसके लिये बिहार शिक्षा परियोजना ने मूल्यांकन हस्तक बनाया है। अब मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर बिना किसी भय के ग्रेडिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुये लागू किया गया है। इस आन्तरिक मूल्यांकन से बच्चों को, शिक्षकों को एवं अभिभावकों को जानकारी मिलती है कि बच्चा सीखने में कहाँ है और उसे किस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है। बिहार में की गयी इस आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली का अभिभावकों ने जोरदार समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है और भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की है और कहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इस इन्टरनल मूल्यांकन सिस्टम जो बिहार ने शुरु किया है इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास करेंगे ।

पाठ्य पुस्तकों का ससमय विद्यालय में आपूर्ति करना :- बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है । पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज का क्रय हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड से किया जाता रहा है । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पर्याप्त संख्या में कागज की ससमय आपूर्ति नहीं करने के कारण पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण में विलम्ब होता है और इसका परिणाम छात्र-छात्राओं के बीच विलम्ब से पाठ्य-पुस्तक के वितरण में होता है। इस पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर खुली निविदा आमंत्रित कर टेक्स्ट एवं आवरण कागज खरीद की जाय ताकि शैक्षिक सत्र (अप्रैल) शुरू होने से पहले पुस्तकें राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को प्राप्त हो सके।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त नये विद्यालयों की स्थापना, भवनहीन विद्यालयों का भवन निर्माण, परिभ्रमण योजना, मध्याह्न भोजन योजना आदि पर ठोस एवं परिणामकारी कार्य किये गये हैं। प्रयोग के तौर पर पूर्णियाँ जिले के 100 विद्यालयों के

किचेन गार्डेन विकसित किया जा रहा है जिसका लाभ उन विद्यालयों में आनेवाले बच्चों को मिलेगा ।

माध्यमिक शिक्षा के लिए पहुँच :

अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उपरांत माध्यमिक शिक्षा का विस्तारित करना इसका स्तर सुधारना हमारी प्राथमिकता है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के विस्तारीकरण के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 4500 माध्यमिक विद्यालय विहीन में प्राथमिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की यह नवीनतम पहल है। इस क्रम में 2160 अनाच्छादित पंचायतों अन्तर्गत मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर इन पंचायत के छात्र/छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता का अवसर प्रदान किया गया, साथ ही जनसंख्या में लिंग अनुपात में वृद्धि होना संभावित है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए माध्यमिक विद्यालय से अनाच्छादित शौचमुक्त पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का योजना है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त अनाच्छादित पंचायत के तहत खुले में शौचमुक्त पंचायत (ODF) को प्राथमिकता दी जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किये गये कार्य :

अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की परिकल्पना में मार्गदर्शक तत्व, यथा– कही से भी पहुंच, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासंगिकता, विकास एवं पाठ्यक्रम का समावेश आवश्यक पहलू है। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण बराबरी की ओर बढ़ने का मौका देता है ।

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, यह उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक का नियोजन किया जा रहा है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध शीघ्र नियोजन किया जाना हमारी प्राथमिकता है।

राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को गुणवर्त्तापूर्ण करने के क्रम में नवाचारी, आई0सी0टी0 आधारित शिक्षण विधियों आदि के विकास एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये गये है। वर्त्तमान में 869 विद्यालयों में आई0सी0टी0 योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा संचालित है।

माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग कक्ष छात्र अनुपात के आलोक में माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कमरे का निर्माण, जीर्णोद्धार एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकासित करने के क्रम में आवश्यकतानुसार यथा प्रयोगशाला, कॉमनरूम, शौचालय एवं पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस क्रम में 1001 वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1153 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के विरूद्ध 583 विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही 653 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक पहुच एवं वर्ग कक्ष में छात्र/छात्राओं के ठहराव सुनिश्चित करने के लिए लाभुक आधारित विभिन्न योजना यथा मुख्यमंत्री साईकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन योजना एवं सभी कोटि के छात्रवृति योजना प्रारंभ की गयी है।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना :-

राज्य सरकार द्वारा जमुई जिलान्तर्गत उत्कृष्ट मापदंडयुक्त सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रति वर्ष 60 छात्र/छात्रा का नामांकन लिया जाता है। विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के फलस्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा, 2016 में प्रथम 10 स्थानों में पर 42 छात्र/छात्रा उत्तीर्ण हुए है।

वर्चुअल क्लास कक्ष :

अध्यक्ष महोदय, उच्चतर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को गूढ़ विषयों पर उत्कृष्ट शिक्षकों का मार्गदर्शन मिले, उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठों को प्रत्यक्षतः देख-सुन और समक्ष सकें, इसके लिऐ वर्चुअल क्लास रूम की हमारी योजना है, जिसे हम प्रथम चरण में 1000 विद्यालयों में लागू करना चाहते है। इस व्यवस्था में प्रारंभ में श्रव्य-दृश्य माध्यम से बच्चे राज्य एवं बाहर के योग्य शिक्षकों के पाठ्य से विषय वस्तु पर ज्ञान हासिल कर सकेंगे। बाद में पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रचर तथा नेट सुविधा मिलने पर देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे क्लास रूम ट्रांजेक्शन से भी उन्हें जोड़ा जा सकेगा।

मॉडल स्कूल :

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मॉडल स्कूल योजना बन्द कर दी गई है । बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित 216 मॉडल स्कूल का भवन निर्मित है। अगले वित्तीय वर्ष में नवनिर्मित भवन में उपस्कर की व्यवस्था माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षा का संचालन सुनिश्चित करेन की योजना है।

बालिका छात्रावास :

अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक प्रक्षेत्र अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में 14–18 वर्ष की SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय तथा BPL परिवार की छात्राओं के नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित 100 बालिका के विरूद्ध 20 बालिका छात्रावास संचालित है। आगामी शैक्षणिक सत्र से संचालित करने की योजना है। उनमें एवं शेष 80 छात्रावासों में छात्राओं के आवासन हेतु उपस्कर आदि की समुचित व्यवस्था कर आगामी शैक्षणिक सत्र से बालिका छात्रावास का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णियाँ में खोला गया है। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिये मिड डे मील की सुविधा दी जा रही है एवं उसकी प्रस्वीकृति प्रणाली को पारदर्शी बनाया जा रहा है। मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता इस बहस में शामिल नहीं रहे और जब सरकार का जवाब हो रहा है, तब ये खड़े हो रहे हैं, अगर ये शिक्षा पर चिंतित होते, तो पूरा तीन घंटा ये बहस में शामिल होते और ये सरकार को अपना सुझाव देते लेकिन जब सरकार का जवाब हो रहा है, तो विपक्ष के नेता खड़े हो रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- आपका समय समाप्त है । आपका जो समय है, वह खत्म है, इसलिए माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

<u>उच्च शिक्षा में किये गये महत्वपूर्ण कार्य</u> :

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माता बी0आर0अम्बेदकर ने उच्च शिक्षा के विषय में कहा था :

"Education in something which ought to be brought whithin the reach of Everyone.... the policy therefore ought to be to make highter education as cheap to the lower classess as it can possibly be made. If all there communities are to be brought to the level of equality then only remedy into adopt the principle of equality and give favoured treatment to those who are below the level"

क्रमश:

टर्न–26/सत्येन्द्र/8–3–17

श्री अशोक चौधरी,मंत्री (क्रमश:): उच्च शिक्षा को सामान्य जनों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बिहार में बच्चों की भागीदारी बढ़े, यह हमारी प्राथमिकता में है । इसके लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं । हमने उन क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां आवश्यकता होते हुए भी

विश्वविद्यालय नहीं थे यथा - पूर्णियां, पाटलीपुत्र एवं मुंगेर में हमने तीन नये विश्वविद्यालय स्थापना करने का निर्णय लिया है । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति सरकार शीघ्र करना चाहती है । इस हेतु उच्च स्तर पर निर्णय लेते हुए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है । आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत समय की आवश्यकता को देखते हुए हमने तीन शैक्षणिक अध्ययन केन्द्र - सेंटर फोर जर्नलिज्म एंड मास कॉम्युनिकेशन, पाटलीपुत्रा सेंटर फोर इकोनॉमिक्स एवं सेंटर फोर रिवर स्टडीज स्थापित करने का निर्णय लिया है । महोदय, बिहार में ऐसे भी प्रखंड हैं जहां डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां नालंदा ओपेन विश्वविद्यालय के माध्यम से ओपेन डिस्टेंस लर्निंग मोड के अन्तर्गत लर्निंग सेंटर चालू किये गये हैं । अब इन प्रखंडों के छात्र-छात्राओं को भी महाविद्यालय की पढ़ाई का अवसर उपलब्ध होगा ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय...

(इस अवसर पर बी0जे0पी0 के सभी माननीय सदस्यगण सदन से वाक-आउट कर गये)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूरा विपक्ष बिहार के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्नशील और चिन्तनशील है ..

अध्यक्ष: हमलोग तो आपकी बात समझते ही है लेकिन सबसे अधिक चन्द्रसेन जी आपकी बात समझते हैं ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: राज्य में अब तक 76 महाविद्यालयों एवं 7 विश्वविद्यालयों को नैक के माध्यम से प्रमाणीकरण कराया जा चुका है । जगजीवन राम संसदीय अध्ययन राजनीतिक शोध संस्थान को विकसित एवं समर्थ बनाने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है । अध्यक्ष महोदय, अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के निर्धारित संख्या (सीट) में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है । 10 अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है । नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा 47 महाविद्यालयों तथा 89 उच्च विद्यालय अथवा इंटरमीडियट कॉलेजों में अध्ययन केन्द्र खोले जा चुके हैं अर्थात आज की कुल 136 अध्ययन केन्द्र नालंदा खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा कुल 82 ज्ञान संसाधन केन्द्र भी संचालित किये जा रहे हैं । हमारा जी0 आर0 माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इस प्रदेश में हम कैसे जी0आर0 को आगे बढ़ाये, उसी के लिए हमलोंगों ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय और मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को लागू करते हुए जी0आर0 को हम इनक्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं । महोदय, जन शिक्षा में भी महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है । जन शिक्षा के कार्य को हम सामाजिक परिवर्त्तन का बड़ा

उपकरण मानते हैं । Victor Hugo ने कहा था 'He who opens a school, door closed a prison.' हमारे साक्षरता कार्यकर्त्ता ऐसे ही क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं । हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था- 'Education imported by heart can bring revolution in the society.' इसी को दृष्टांत करते हुए हमलोगों ने शिक्षा के माध्यम से जन शिक्षा का हमलोगों ने प्रयास किया है । शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुधार एवं सामाजिक परिवर्त्तन के लिए हम सतत् प्रयत्नशील हैं । हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि महात्मा गांधी के 100 वें वर्ष पर इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया हैं । आजादी के बाद इस देश में इतना बड़ा सामाजिक क्रांति पहली बार इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नशाबंदी का कानून लागू कराकर सही रूप में महात्मा गांधी को अपना 100 वें चम्पारण वर्ष में महात्मा गांधी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है । हमारे इस अभियान में बच्चों ने अपने अभिभावकों एवं परिवार के पुरूष सदस्यों को नशा से दूर रहने एवं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने हेतु शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है । पिछले वर्ष 1 करोड़ 70 लाख अभिभावकों ने लिखित रूप से शपथ ली और आज लोग जोरदार शब्दों से नशामुक्ति के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं । ''नशामुक्त रहे बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार'' । बच्चों एवं महिलाओं ने भी नशामुक्ति का पैगाम घर घर तक पहुंचाया है । मुख्यमंत्री का अपील बांटा गया, 70 लाख से अधिक नारे लिखे गये । पुनः राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को मद्य निषेध अभियान(द्वितीय चरण) को घर-घर तक चलाने के लिए, इसके पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जिम्मा दिया है । हम नारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के द्वारा घर घर अलख जगाकर संदेश को फैला रहे हैं, इसमें हमें कामयाबी मिल रही है । अब बिहार में शादी-विवाह के मौके पर झगड़े कलह नहीं होते, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है । अपराध की घटनाओं में कमी हुई है, गरीब-गुरबे मेहनतकश अपनी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और चिकित्सा एवं परिवार के विकास में कर रहे हैं । नयी पीढ़ी, नौजवान, नौनिहाल एवं माताएं-बहनें, बेटियां सबों में प्रसन्नता है और लोग सुख और शांति का जीवन जी रहे हैं। नशामुक्त बिहार के पक्ष में 21 जनवरी, 2017 को राज्य सरकार ने राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम रखा था । हमने पूरे बिहार के लिए 11,292 कि0मी0 की मानव श्रृंखला का मार्ग निर्धारित किया था और 2 करोड़ लोगों की भागीदारी की अपेक्षा की थी । मुझे आपको सूचित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की जनता, महिलाएं, युवा, बच्चे, शिक्षक, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, सभी वर्गों के लोग, राजीनतिक दलों के नेता कार्यकर्त्ता, सम्पूर्ण बिहारवासियों ने मिलकर ऐतिहासिक विशाल राज्यव्यापी 12760 कि0मी0 की मानव श्रृंखला का निर्माण किया । जिलों से

प्राप्त लिखित हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज के अनुसार 3,11,08,535 लोगों की भागीदारी हुई। इसमें एक पंक्ति की संख्या मात्र है । कई स्थानों पर लोग दो-तीन पंक्तियों में खड़े हुए। हमारे निर्धारित मार्ग के अलावे भी कई मार्गों पर कतारें बनायी । सट सट कर लोग खड़े थे । आपने भी देखा होगा, अपार जन समूह ने स्वतः स्फूर्त ढंग से विशाल मानव अभेद्य दीवार बनाया । अनुमानतः चार करोड़ के लगभग लोगों की भागीदारी रही । नशा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जन चेतना का यह विराट प्रदर्शन बिहार ने कर दिखाया है । न भूतों न भविष्यति । नशा जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला बनाकर ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सबों को बधाई देता हूँ । हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया और हम अपने आपको गौरवशाली महसूस करते हैं कि इसमें इतने बड़े सामाजिक क्रांति के साथी बने हैं । David Archer कहते हैं -Literacy is the fertilizer needed for Development and Democracy to take roots and grow. यह दुखद बात है कि अभी भी हमारे समाज में निरक्षर लोग मौजूद हैं । हम साक्षरता विस्तार के लिए कई कदम उठा रहे हैं । साक्षर भारत मिशन । वर्ष 2012-13 से राज्य सरकार द्वारा महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने, विशेष शिक्षण देने एवं उनकी माताओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता के लिए महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संचालित की जा रही है । इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत पायलट परियोजना के रूप में नालंदा जिले में ''कोई बच्चा पीछे नहीं, माता पिता भी छूटे नहीं'' कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 20 प्रखंडों के सभी महादलित, दलित, अल्पसंख्यकों के टोले में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इस पायलट परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय एवं जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। यह पायलट परियोजना 4 महीने के समय अवधि में पूरी की जायेगी । नालंदा में इस पायलट परियोजना से प्राप्त सीख, अनुभव एवं कार्यकर्त्ताओं में विकसित कौशल के आधार पर शेष जिलों में चरणबद्ध तरीके से इस अनुभव एवं सीख को हम उतारेंगे । आप सभी जानते हैं कि 2017 गांधी के चम्पारण सत्याग्रह का सौवां साल है । 1917 की 10 अप्रैल को महात्मा गांधी बिहार आये थे और चम्पारण जाकर नीलहे-गोरों के अत्याचार की व्यथा कथा को सुना और अपनी आंखों से उनका हाल देखा । उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के अपने प्रयोग चम्पारण में किये । चम्पारण सत्याग्रह के द्वारा किसान और मजदूरों को नीलहे अत्याचार से मुक्ति दिलायी । इस युग परिवर्त्तनकारी घटना की भूमि बिहार नरे फिर एक बार गांधी जी को याद किया है और हम उनके सपनों को घर-घर, गांव-गांव तक पहुंचाने जा रहे हैं । बिहार के गौरव की चर्चा करते हुए गांधी जी ने 5 मार्च, 1947 को पटना की प्रार्थना सभा में कहा थाः-'चम्पारण सत्याग्रह से

पहले भारत में मुझे कौन जानता था ? अफ्रीका में 20 वर्ष बिताने के बाद मैं भारत लौटा और चम्पारण आया । इसके बाद मेरे साथ पूरा देश जाग उठा । इससे पहले मैं चम्पारण को नहीं जानता था परन्तु जब मैं चम्पारण आया तो मुझे लगा कि मैं बिहार के लोगों को सदियों से जानता हूँ और वे भी मुझे गहराई से जानते हैं । यह बिहार है, जिसने पूरे भारत वर्ष को गांधी का परिचय दिया ।' उनके 100 वें चम्पारण दिवस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने चम्पारण दिवस को विशाल रूप में मनाने का निर्णय किया और इस देश, इस प्रदेश के हरेक बच्चे और हरेक माता-बहनों के घर पर दस्तक देने का निर्णय किया, जो विध्वंसकारी ताकतें इस देश में राज कर रही है जो इस देश की कौमी एकता को गंगा यमुना संस्कृति को तोड़ना चाहती है, उसके खिलाफ गांधी के सत्याग्रह के इस 100 वें साल को मनाने का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया है, हम इनको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। चम्पारण सत्याग्रह के सौ साल बाद हम कहां हैं ? आगे कहां, हम कैसे जाना चाहते है, इन प्रश्नों के उत्तर के साथ वर्ष पर इनके परिवर्तनकारी कार्यक्रमों को लेकर हम जन-जन, घर-घर, द्वार-द्वार दस्तक देने वाले हैं । (क्रमशः)

टर्न-27/मधुप/08.3.2017

..क्रमशः...

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : मैं सम्मानित सदस्यों का भी, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आह्वान करता हूँ कि शिक्षा का मुद्दा बिहार का मुद्दा है । हम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है । अंधकार से लड़ने की और प्रकाश की ओर कदम बढ़ाने की हमारी कोशिश में आप सबों का साथ चाहिये । हमारा प्रयास नये चाह का प्रयास है, नये लय का प्रयास है, नये गीत का प्रयास है । विद्या, ज्ञान और विज्ञान का प्रयास है । इन्हीं प्रयास से बिहार के अतीत में मिले सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं ।

मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण चिन्तन रखने की प्रेरणा दी है । मैं महागठबंधन के दोनों प्रमुख नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे निरन्तर सहयोग एवं मार्गदर्शन देने का काम किया है ।

शिक्षा विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्यय वहन हेतु कुल रू0 252,51,38,80,000/- (दो सौ बावन अरब एकावन करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार रूपये) का उपबंध मॉग संख्या-21 के अन्तर्गत प्रस्तुत है । इसमें गैर योजना व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है ।

इसमें गैर योजना व्यय के लिये रू0 110,33,50,03,000/- (एक सौ दस अरब तैंतीस करोड़ पचास लाख तीन हजार रूपये) प्रस्तावित है ।

राज्य योजना व्यय के लिये रू0 142,17,88,77,000/- (एक सौ बयालीस अरब सतरह करोड़ अठासी लाख सतहत्तर हजार रूपये) का प्रस्ताव है जिसमें से केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि रू0 92,67,56,00,000/- (बेरानवे अरब सड़सठ करोड़ छप्पन लाख रूपये), राज्यांश की राशि रू0 34,45,08,75,000/- (चौतीस अरब पैंतालीस करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये), राज्य स्कीम के लिए रू0 10,76,67,02,000/- (दस अरब छिहत्तर करोड़ सड़सठ लाख दो हजार रूपये) वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु रू0 4,28,57,00,000/- (चार अरब अठाइस करोड़ सन्तावन लाख रूपये) है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह अजम है कि हर जबान, इलम के हर शोबे और इखलाकी और मोआशराति खिदमत के लिए किसी पहलू को नहीं छोड़े । चिराग से चिराग जलेंगे । अपनी और अपने बाद वाली नसल को इस अन्दाज से सींचने का मुक्कमिल इरादा है कि मुसतकबिल की धुंध को साफ और शफाक कर दें । इलम और तालीम को रोजगार, तिजारत और तहजीब के हर शोबे में कामयाबी की राह पर गामजन करें ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि

''पाना है जो मुकाम अभी बाकी है
अभी तो आए हैं जमीन पे,
आसमां की उड़ान अभी बाकी है''

और

''सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है
कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है ।''

अध्यक्ष महोदय, अंत में हम आपसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह से शिक्षा के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है, शिक्षा के प्रति जिस तरह से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से हम यह बात मानते हैं कि पहले की हमारी सरकारों ने इस प्रदेश में मूलभूत संरचनाओं का विकास किया और मूलभूत संरचनाओं के विकास के क्रम में इस प्रदेश के सभी टोलों में प्राथमिक विद्यालय बनाये गये जो हमारे माध्यमिक विद्यालय थे, उनको उत्क्रमित किया गया और उसके बाद हाई स्कूल में हमने +2 की व्यवस्था की जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं । पिछले चार-पॉच वर्षो में हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो बच्चे हमारे स्कूल के बाहर हैं, हम उनको विद्यालय में लाने का काम करें और इस तरह से कार्यक्रम करके इस प्रदेश में हम समझते हैं बिहार दो-चार-पॉच ऐसे राज्यों में होगा इस

देश में जहॉ कि स्कूल से बाहर जो हमारे बच्चों की संख्या है, मात्र एक प्रतिशत है । हमने एक प्रयास किया है, ठोस प्रयास किया है जिससे कि स्कूल के बाहर के हमारे बच्चे स्कूल में आये हैं लेकिन हमें एक बड़ी चुनौती है कि इस प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कायम करना है । गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कायम करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमलोगों ने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बहाल करने का मिशन गुणवत्ता शुरू किया है । हमें मालूम है कि हमारे पास परेशानियॉ हैं, चुनौतियॉ हैं लेकिन सरकारी पूरी तरह से शिक्षा को सशक्त और मजबूत कराने के लिये संवेदनशील है और इसीलिये हमलोगों ने फिफ्थ चरण में माध्यमिक में हमलोगों ने टीचर के एप्वायंटमेंट प्रोसेस को एक्सक्यूट किया है । बहुत जगह बहालियॉ हुई हैं, कुछ जगहों पर बहालियॉ नहीं हो पाई हैं, उन जिलों में जहॉ बहालियॉ नहीं हो पाई हैं, उसके लिये भी हम प्रयासरत हैं ।

वर्चुअल क्लास रूम का हमलोगों ने प्रयास किया है जिससे कि जो हमारे हाई स्कूल हैं उसमें वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से हम जो बाहर की तकनीक है उसके माध्यम से जो अच्छे-अच्छे हमारे यहॉ शिक्षक हैं, भारत के जो भी राज्य हमारे हैं जहॉ पर हमारे अच्छे मैथ्स और साइंस के टीचर उपलब्ध हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर हम बच्चों को दिखायें और उस तरह से हम एक हजार स्कूलों को टारगेट किये हैं कि 2017-18 में हम एक हजार स्कूलों को वर्चुअल क्लास रूम से कनेक्ट करेंगे लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का इरादा है कि जितने हमारे इस प्रदेश के हाई स्कूल हैं, सबको हम आने वाले समय में वर्चुअल क्लास रूम से कनेक्ट करेंगे । हम पूरी तरह से शिक्षा पर संवेदनशील हैं । अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे क्योंकि अगर 21वीं सदी का बिहार देखना है तो शिक्षा को बिना सशक्त एवं मजबूत किये हुये 21वीं सदी का बिहार देखना सम्भव नहीं होगा । इसीलिये हमलोगों ने इस प्रदेश में शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का प्रयास किया है । हम एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा के प्रति इनकी सजगता, शिक्षा के प्रति इनकी चिन्तन पर हम उनके दिखाये हुये मार्ग पर शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, वसंत का आगमन हो चुका है, होली आने ही वाला है । आप सबों को वसंतोत्सव की शुभकामना देते हुये हिन्दी के महान कवि निराला द्वारा लिखी गयी प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियॉ आपको सुनाना चाहता हूँ । ज्ञान की उपासना में अपनीी अमर कविता के माध्यम से निराला कहते हैं -

काट अंध-उर के बंधन-स्तर
बहा जननि, ज्योतिर्मय निर्झर,
कलुष-भेद-तम हर प्रकाश भर

जगमग जग करा दे !
नव गति, नव लय, ताल-छंद नव
नवल कंठ, नव जलद-मन्द्ररव,
नव नभ के नव विहग-वृंद को
नव पर, नव स्वर दे !

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ हम माननीय सदन से आग्रह करते हैं कि हमारी मॉंग पर अपनी सहमति प्रदान करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव वापस लेने का भी अनुरोध किया जाय ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हम कटौती प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह माननीय सदस्य से करते हैं । हम चिंतित हैं, संवेदनशील हैं, इसलिये आप हमारी मॉंग पर अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मॉंग 10/- रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 252,51,38,80,000/- (दो सौ बावन अरब एकावन करोड़ अड़तीस लाख अस्सी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
मॉंग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 08 मार्च,2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 45 (पैंतालीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, अभी माननीय शिक्षा मंत्री, वसंत में जो पर्व आने वाला है होली, उस की चर्चा कर रहे थे ।

हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहार वासियों को सदन की ओर से मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और कामना करता हूँ कि यह त्यौहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाये ।

इसी खैरअंदेशी के साथ सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

.....